

वैश्विक संवाद

9.3

17 भाषाओं में एक वर्ष में 3 अंक

समाजशास्त्र पर बातचीत
किंग्जी हुआन के साथ

क्रिस्टिन शिकर्ट

ब्रिजिट ऑलेनबैकर
एंड्रियास नोवी
फ्रेड ब्लॉक
मागरिट आर सोमर्स
एंटीनिनो पालुम्बो
एलन स्कॉट
गैरेथ डेल
जोनाथन डी लंदन
एटिला मेलेग
क्रिस हैन

द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन
(75 वर्ष पश्चात्)

स्मृति में:
एन बार्डन डेनिस

लिंडा क्रिस्टियानसेन – रफमैन
एंजिला माइल्स
मार्लिन पोर्टर

प्रवासन

केरिन शेरशोल
गेरडा हेक
कार्लोस सैंडोवाल
बेदिज यिल्माज
सरा शिलिगर

सैद्धांतिक परिपेक्ष्य

जूलिया कैसर
जैस्पर स्टैंज

सेनेगल से समाजशास्त्र

मुस्ताफा ताम्बा
सौलेमन गोमिस
एल हदजी मलिक सी कैमारा
सांबा डायफ
मोहम्मद मुस्ताफा दीये

खुला अनुभाग

> महिला अधिकारों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना

पत्रिका



International
Sociological
Association
ISA



अंक 9 / क्रमांक 3 / दिसम्बर 2019
<http://globaldialogue.isa-sociology.org/>

GD

> सम्पादकीय

वैश्विक उत्तर और दक्षिण के देशों में समान रूप से जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संकट पर बहस हाल ही वर्षों में आगे आई है। किंग्जी हुआन, बीजिंग, चीन में तुलनात्मक राजनीति के प्रोफेसर और इको-समाजवादी नीतियों के प्रस्तावक एक साक्षात्कार में चीनी बहसों और पिछले दशकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति पर्यावरणीय नीतियां और दृष्टिकोण कैसे बदल गये हैं, के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

1944 के प्रकाशित कार्ल पोलान्थी की उत्कृष्ट कृति, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन (टीजीटी) ने सामाजिक एवं राजनैतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र में काफी शोध को प्रेरित किया है। वैश्विक संवाद द्वारा आयोजित हमारी पहली संगोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय कार्ल पोलान्थी सोसाइटी के अध्यक्ष एंड्रियास नोवी ने उनकी पुस्तक की 75 वी वर्षगांठ मनाई। कार्ल पोलान्थी के जीवन और कृत्य पर पथप्रदर्शक पुस्तकों के लेखक जैसे फ्रेड ब्लॉक, गेरेथ डेल, क्रिस हैन एवं मार्गरेट आर सोमर्स और शोध के विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ जो हमारे समय के लिए पोलान्थी के कार्य का पाठन कर रहे हैं, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। इसमें पोलान्थी के दृष्टिकोण के लेंस से पिछले दशकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक घटनाक्रमों के लिए विश्लेषण हेतु प्रासंगिक बौद्धिक संदर्भ सम्मिलित हैं।

एन बॉर्डन डेनिस का फरवरी 2019 में निधन हो गया। उन्हें न केवल उनके शोध के क्षेत्र में समाजशास्त्रीय कार्य के लिए बल्कि आईएसए के साथ उनके मजबूत जुड़ाव के लिए भी स्मरण किया जायेगा। ऐसा लिंगा क्रिस्टियान्सेन-रफमैन, एंजिला माइल्स एवं मार्लिन पोर्टर्स ने उनको दी अपनी श्रद्धांजली में कहा।

केरिन शेरशेल द्वारा आयोजित हमारी द्वितीय संगोष्ठी, प्रवासन एक विषय जिसकी समाजशास्त्र में लंबी परम्परा है और पिछले कुछ वर्षों में जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया है, की जांच करती है। विभिन्न देशों के आलेखों का यह संकलन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रवासन के कारक, प्रवासियों और विशेषकर शरणार्थियों की स्थिति, विवादास्पद राजनैतिक नियमन और नागरिक समाज की संलग्नता का विश्लेषण करते हैं।

फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक अनूठा सामाजिक आंदोलन बन गया है, जो अगली पीढ़ी की आजीविका के लिए खतरनाक पारिस्थितिक आपदा का सामना करने वाले युवाओं के बढ़ते प्रतिरोध को दृश्यता प्रदान करता है। जूलिया कैसर और जैस्पर स्टेंज द्वारा आलेख लामबंदी एवं गठबंधन-निर्माण के लिए क्रॉस-क्लास उपागम का चित्रण करता है, जो पर्यावरण आंदोलन के मध्य एक नया घटनाक्रम है।

मुस्तफा ताँबा ने सेनेगल के समाजशास्त्रियों के लेखों का एक संग्रह जुटाया। वे शिक्षा के समाजशास्त्र पर ध्यान केन्द्रित करते हैं और हमें शिक्षा के संगठन एवं पहुंच और विभिन्न प्रकार के विद्यालय एवं उनके विनियमन पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

हमारे खुले अनुभाग में संयुक्त राष्ट्र में आईएसए की युवा प्रतिनिधि, बेंगी सुलु, महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग के 63 वें सत्र, जिसमें उसने भाग लिया था, पर रिपोर्ट करती है।

ब्रिजिल ऑलनबैकर एवं क्लॉस डोरे
वैश्विक संवाद के संपादक

- > वैश्विक संवाद आई.एस.ए वेबसाइट पर 17 भाषाओं में देखा जा सकता है।
- > प्रस्तुतियाँ <globaldialogue.isa@gmail.com> पर भेजी जा सकती हैं।

isa International
Sociological
Association

**GLOBAL
DIALOGUE**



> संपादक मण्डल

संपादक : ब्रिजित ऑलनबॉकर, क्लॉस डोरे

सह-सम्पादक : जोहाना ग्रबनर, क्रिस्टीन शिकर्ट

सहयोगी सम्पादक : अर्पणा सुन्दर

प्रबंधन संपादक : लोला बुसुतिल, अगस्त बागा

सलाहकार : माइकल बुरावे

मीडिया सलाहकार : जुआन लेजाररगा

परामर्श संपादक :

साडी हनाफी, ज्योफी प्लीयर्स, फिलोमिन गुतिरेज, एलोइजा मार्टिन, सावाको शिराहेस, इजाबेला बरलिंस्का, तोबा बेन्सकी, चिह-जुए जेचेन, जेन फ्रिज, कोइची हासेगावा, हिरोशी इशिदा, ग्रेस खुनो, एलिसन लोकोन्तो, सुसन मेकडेनियल, एलिना ओइनास, लोरा ओसो कैसास, बंडाना पुर्कायस्था, रोहडा रेडॉक, मौनीर सैदानी, आयसे सकतांबर, सेलीस्कालोन, नाजानीन शाहरोकनी।

क्षेत्रीय संपादक

अरब दुनिया : साडी हनाफी, मौनीर सैदानी, फातिमा रधौनी, हबीब हज सलेम, सोराया मौलोदजी गराउदजी, अब्देलहादी एल हालहोली, सालिदा जाइन।

अर्जेन्टीना : एलेक्जेंद्रा ओतामेंडी, जुआन इगनासिया पियोवानी, मार्टिन दी मार्को, पिलर पी पुइग, मार्टिन उर्दुसन।

बंगलादेश : हबीबुल हक खंडकर, हसन महमूद, जुवेल राणा, यूएस रोकेय अख्तर, तूफिका सुल्ताना, असिफ बिन अली, खैरुन नाहर, काजी फदिया एशा, हेलल उदीन, मुहिमिन चौधरी, मोहम्मद यूनुस अली।

ब्राजील : गुस्तावो तानिगुती, एंजेलो मार्टिन्स जूनियर, एंड्रेजा गली, लुकास अमरल ओलिविरा, बेनो वार्केन, दिमित्रिा सर्बोन्सीनी फर्नांडीस।

फ्रांस/स्पेन : लोला बुसुतिल

भारत : रश्मि जैन, निधी बंसल, प्रज्ञा शर्मा, मनीष यादव, संदीप मील।

इंडोनेशिया : कमांतो सुनार्तो, हरि नुग्रोहो, लूसिया रतीह, कुसुमादेवी, फिना इट्रियती, इंदेरा रत्ना इरावती पट्टिटनसारानी, बेनेडिक्टस हरि जूलियावान, मोहम्मद शोहीबुद्दीन, डोमिंगगस एलसीडली, एंटोनियस एरियो सेतो हार्डजाना, डायना तेरेसा पाकासी, नुरुल ऐनी, गेगेर रियांतो, आदित्य प्रदान सेतियादी।

ईरान : रेयहाने जावदी, नियाश डॉलाती, अब्बास शाहरबी, सैयद मोहम्मद मुतालेबी, एहसान पुरनेजाति।

जापान : सतोमी यामामोतो, सारा मेहारा, ताकेशी कुनिताके, रिहो तनाका, एकातेरिना स्टेपोशिना, युसुके योत्सुगी।

कजाकस्तान : अइगुल जाबिरोवा, बायन स्मागमबेट, आदिल रोदियोनोव, अल्माश त्लेसपयेवा, कुआनिश टेल, अलमागुल मुस्सीना, अकनूर ईमानकुल।

पौलैंड : जेकब बारस्जेवस्की, एलेक्सांड्रा बियरनाका, इवोना बोजादज्जेवा, कतारज्यना देब्सका, मोनिका हेलक, सारा हरस्जींस्का, किंगा जकीला, जुस्तिना कोसिंस्का, एडम मुलर, वेरनिका पीक, जोफिया पेन्जा-गेबलर, जोनाथन स्कोविल, मार्कजाना स्जेजेपिनायाक, एग्निजका स्जिपुल्स्का, एलेक्सांड्रा वेगनर।

रोमानिया : कोसिमा रुधिनिस, राइसा-गोब्रियला जमीफिरेस्कू, लुसियाना एनास्तोसोई, क्रिस्टियन चीरा, एलेक्सांड्रा-इवोना ड्रेगरनिर, डायना एलेक्सेंड्रा डुमित्रोस्कु, राडू, मिहार्ड डुमिस्त्रेस्कू, युलिआन गेबर, डैन गिओर्टमैन, लूलियन जुगानारू, इयाना मोलुरेनु, बियांका मिहायला, एलिना किस्तिना पॉन, कोद्रुत पिनजारू, सुसाना मरिया पोपा, एड्रियाना सोहोदोलानु, ग्रेब्रियला स्तोइन, मारिया स्तोइसेस्कू, मारिया-किस्तिना तितिया, कार्मेन यूजिनिया वोइनिया

रूस : ऐलेना ज्द्रावोम्यस्लोवा, अनास्तासिया दौर, वेलेंटीना इसाएवा।

ताईवान : जिंग-माओ हो।

तुर्की : गुल कोरबासियोग्लू, इरमक एवरेन।



द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन (टीजीटी), 1944 में प्रकाशित, कार्ल पोलान्सी की महान कृति 1920 और 1940 के दशक के मध्य उनके सामने होने वाले घटनाक्रमों के संदर्भ में पूंजीवाद के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करती है। यह इस बात की गहन जाँच करती है कि पूंजीवाद के इतिहास में क्या हुआ और क्या हो सकता है। यह प्रथम संगोष्ठी 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को कार्ल पोलान्सी के कृत्यों के साथ-साथ उसके द्वारा प्रेरित परिपेक्ष्यों एवं उपागमों के इतिहास पर आलेखों को प्रस्तुत कर मनाती है।



प्रवासन को एक पृथक प्रघटना नहीं माना जा सकता है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक अधिकार, राष्ट्र-राज्यों का विभाजन, नागरिकता, वैश्वीकरण और प्रवासीय प्रक्रियाओं के बन्धकारी नियंत्रण जैसे बहुत कारकों के मध्य परस्पर क्रिया के रूप में माना जा सकता है। यहाँ एकत्रित आलेख प्रवासन के कारणों, प्रवासी और शरणार्थियों की स्थिति, विशेष रूप से विवादास्पद राजनैतिक नियमन और नागरिक समाज संलग्नता का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।



यह खण्ड सेनेगल से समाजशास्त्र से समाजशास्त्र के बारे में सैद्धान्तिक और आनुभाविक अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। इनमें सेनेगल की स्कूल व्यवस्था के बारे में सूचनात्मक समीक्षा और इसके विभिन्न पक्ष जैसे फ्रेंच-अरबी निजी एवं सार्वजनिक स्कूल और धर्म की प्रासंगिकता कर गहन विश्लेषण सम्मिलित हैं।



सेज प्रकाशन की उदार ग्रांट से वैश्विक संवाद का प्रकाशन संभव है।

> इस अंक में

सम्पादकीय 2

> समाजशास्त्र पर बातचीत

इको-सोशललिस्ट विजन ;दृष्टि के लिए : किंग्डी हुआन के साथ साक्षात्कार
क्रिस्टिन शिकर्ट, जर्मनी द्वारा 5

> द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ;75 वर्ष पश्चात्

द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के 75 वर्ष
ब्रिजिट ऑलेनबैकर एवं एंड्रियास नोवी, आस्ट्रिया द्वारा 9

75 पर पोलान्थी की द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन
फ्रेड ब्लॉक एवं मार्गरेट आर सोमर्स, यू.एस.ए 11

स्टेटक्राफ्ट के रूप में बाजार : एक पोलान्थी व्याख्या
एंटीनियो पालुम्बो, इटली एवं एलन स्कॉट, आस्ट्रेलिया द्वारा 13

पोलान्थी, लेंखाकन और 'जी डी पी से परे'
गैरेथ डेल, युनाइटेड किंगडम द्वारा 15

ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन: पूर्वी एशिया का विपणन
जोनाथन डी लंदन, नीदरलैंड द्वारा 17

आबादी प्रतिस्थापन का भय
अत्तिला मेलेग, हंगरी द्वारा 19

लोकलुभावनवाद की तरफ मार्ग
क्रिस हैन, जर्मनी द्वारा 21

कार्ल पोलान्थी की चिरस्थायी विरासत
एंड्रियास नोवी, ऑस्ट्रिया द्वारा 23

> स्मृति में

एन बर्डिन डेनिस: सराहना में
लिंडा क्रिस्टियानसेन-रफमैन, एंजिला माइल्स, एवं मार्लिन पोर्टर,
कनाडा द्वारा 25

> प्रवासन

प्रवासन – आगे बढ़ते हुए
केरिन शेरशेल, जर्मनी द्वारा 27

यूरोपीयन कल्पना और अफ्रीकी गतिशीलता का यथार्थ
गेर्दा हेक, मिस्त्र द्वारा 29

मध्य अमरीकी कारवाँ : 21वीं सदी का एक पलायन
कार्लोस सैंडोवाल, कोस्टा रिका द्वारा 31

पराधीन श्रम बल के रूप में शरणार्थी: तुर्की से टिप्पणी
बेदिज यिल्माज, तुर्की द्वारा 33

एकजुट शहरों में सीमाओं को खोलना
सारा शिलिगर, स्विट्जरलैंड द्वारा 35

> सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य

भविष्य के लिए विद्यार्थी : पारिस्थितिकी वर्ग राजनीति
जूलिया कैसर और जैस्पर स्टैज, जर्मनी द्वारा 37

> सेनेगल से समाजशास्त्र

सेनेगल में निजी कैथोलिक शिक्षा
मुस्ताफा ताम्बा, सेनेगल द्वारा 40

सेनेगलीज विद्यालय व्यवस्था का समाजशास्त्र
सौलेमन गोमिस, सेनेगल द्वारा 42

सेनेगल में फ्रेंको-अरब शिक्षा में सामरिक समायोजन
एल हदजी मलिक सी कैमारा, सेनेगल द्वारा 44

सेनेगल में धर्मनिरपेक्ष निजी शिक्षा
सांबा डायफ, सेनेगल द्वारा 46

सेनेगल में धार्मिक नेतृत्व का सामाजिक-नृविज्ञान
मोहम्मद मुस्तफा दीये, सेनेगल द्वारा 48

> खुला अनुभाग

महिला अधिकारों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना
बेंगी सुलु, यू.एस.ए द्वारा 50

“एकजुट शहर (सोलिडेरिटी सिटी) के नारे के साथ जुटने वाली इन सभी पहलों में जो समान है वह है एक ठोस यूटोपिया का है। इस ठोस यूटोपिया में प्रवासन और सामाजिक नीति मुद्दों को जोड़ कर (एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय) राजनैतिक बाधाओं से बाहर निकलने की क्षमता है।”

सारा शिलिगर

> इको-सोशलिस्ट विजन (दृष्टि) के लिए

किंगज़ी हुआन के साथ साक्षात्कार

किंगज़ी हुआन चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय में तुलनात्मक राजनीति के प्रोफेसर हैं। 2002-03 में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हार्वर्ड-येनचिंग विजिटिंग स्कॉलर थे और 2005-06 में जर्मनी के मैनेम विश्वविद्यालय में हम्बोल्ट रिसर्च फ़ेलो थे। उनका शोध पर्यावरणीय राजनीति, यूरोपीय राजनीति के साथ वाम राजनीति पर केन्द्रित है। उन्होंने इन मुद्दों पर अनेक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया है जिसमें 2000 में *ए कम्परेटिव स्टडी ऑन यूरोपीयन ग्रीन पार्टिस एवं इको-सोशलिज्म एज पोलिटिक्स* और 2010 में *रिबिल्डिंग द बेसिस ऑफ आवर मोडर्न सिविलाइजेशन* सम्मिलित हैं

क्रिस्टिन शिकर्ट, फ्रेडरिख शिलर विश्वविद्यालय जेना, जर्मनी में पोस्ट-ग्रोथ समाजों पर शोध समूह की प्रशासनिक निदेशक एवं वैश्विक संवाद की सहायक संपादक ने उनका साक्षात्कार किया।



किंगज़ी हुआन | श्रेय: एफएसयू जेना

सी.एस. : हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन राजनीतिक मुद्दों में सबसे अधिक चर्चित मुद्दा बन गया है, कम से कम वैश्विक उत्तर के देशों में तो, क्या आप आज की चीनी राजनीति एवं समाज में इस चर्चा की भूमिका का वर्णन कर सकते हैं ?

क्यू.एच. : अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति के प्रमुख मुद्दों में से एक के रूप में वैश्विक जलवायु से निपटने, मैं 1992 में रियो शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू.एन.एफ.सी.) पर हस्ताक्षर करने के बाद से काफी लम्बा सफर तय किया है। आम तौर पर, अन्य विकसशील देशों की तरह, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने पर चीन की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत है—इसे “समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी का सिद्धांत”

(सीबीडीआर) कहा जाता है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन केवल उन्नत या विकासशील देशों के बजाय पूरे मानव समाज के लिए समान चुनौती या संकट है। दूसरा, तथाकथित उन्नत देशों या क्षेत्रों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ और अमरीका, को विकासशील देशों को आवश्यक संसाधनों एवं प्रौद्योगिकी की पेशकश या उसका हस्तांतरण कर अपनी प्रमुख ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तीसरा, विकासशील देशों, जिनमें चीन भी शामिल है, को अपनी बढ़ती क्षमताओं के अनुसार वैश्विक जलवायु परिवर्तन नियंत्रण एवं अनुकूलन में अधिकाधिक योगदान देना चाहिए।

इस नीतिगत स्थापन के आधार पर, पिछले कुछ वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की राजनीति में चीन की भागीदारी को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है: 1992 से पूर्व, 1992-2012,

2012 से अब तक। 2012 तक प्रभावी समझ यह थी कि उन्नत देश जैसे यूरोपीय संघ के देश और अमरीका को ही तुरन्त कार्यवाही करनी है। 2012 के बाद से चीनी सरकार ने धीरे-धीरे जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर अपनी स्थिति को विशेषकर यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क के तहत अद्यतन या स्थानांतरित करा। यहां सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेरिस समझौते तक पहुंचने और इसे लागू करने में चीन की नई भूमिका है।

सच्ची बात है कि चीनी नीतिगत स्थापन के लिए इस समायोजन का मुख्य प्रोत्साहन पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर या क्रियान्वयन से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि यह पारिस्थितिक-सम्यता (इको-सिविलाइजेशन) के निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय रणनीति को लागू करने से आता है। संक्षिप्त रूप से, चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के 18वें राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अंकित “राष्ट्रीय पारिस्थितिक पर्यावरण शासन प्रणाली और शासन क्षमता” के आधुनिकीकरण को सीपीसी एवं चीनी सरकार के लिए शीर्ष राजनैतिक और नीतिगत लक्ष्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना उनकी राजनैतिक इच्छाशक्ति को दर्शाने का एक आदर्श प्रतीकात्मक मामला है। उदाहरण के लिए, चीन 2019-20 में कई महत्वपूर्ण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का आयोजन कर यूएन. कन्वेंशन ऑन बायोलोजिकल डाइवर्सिटी (सीबीडी) पर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के क्रियान्वयन पर अधिकाधिक ध्यान दे रहा है।

सी.एस. : चीन में पर्यावरणीय संरक्षण कोई नया मुद्दा नहीं है। 1972 में समाजवादी पार्टियों द्वारा शासित अन्य देशों के विपरीत, चीन ने मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की संगोष्ठी में भाग लिया जहां पर्यावरण संरक्षण सम्बंधी कई सिद्धांतों और सिफारिशों पर सहमति हुई थी। क्या आप तब से चीन की पर्यावरणीय नीतियों के विकास और बदलावों की चर्चा कर सकते हैं ?

क्यू.एच. : यह सच है कि चीन में सार्वजनिक नीति के रूप में पर्यावरण संरक्षण की औपचारिक शुरुआत 1972 में हुई जब चीनी प्रतिनिधिमंडल ने मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया। परिणामस्वरूप, 1973 में चीन ने पर्यावरण संरक्षण पर अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और इस नीतिगत मुद्दे के प्रभारी के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना की। तब से, चीन की पर्यावरण नीति ने विकास के चार चरणों का अनुभव किया है: 1973-89, 1989-92, 1992-2012 और 2012 से अब तक।

प्रथम चरण में, डेंग जियाओपिंग के राजनैतिक नेतृत्व में 1978 में “सुधार और खुलने” के गठन और कार्यान्वयन के साथ पर्यावरणीय संरक्षण शीघ्र ही प्रमुख नीतिगत मुद्दा बन गया और परिणामस्वरूप

“बुनियादी राज्य नीति के रूप में पर्यावरण संरक्षण” को 1983 में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हुई और यह अब तक चीन के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख नीति दिशानिर्देशों में से एक है। दूसरे चरण के दौरान, जियांग जेमिन के राजनैतिक नेतृत्व में, सतत विकास सीपीसी और चीनी सरकार की राजनैतिक पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय शासन रणनीति की प्रमुख अभिव्यक्ति बन गया। 2002 से 2012 तक, कई मायनों में एक संक्रमण चरण, हू-जिंताओं के राजनैतिक नेतृत्व में 2005 में अग्रेषित “द्वि-प्रतिमान समाज निर्माण” (संसाधन बचत एवं पर्यावरण अनुकूल समाज) की अवधारणा उस समय की सीपीसी और चीनी सरकार का केन्द्रीय सम्बोध थी। 2007 में “पारिस्थितिक सम्यता निर्माण” सम्बोध को सीपीसी की 17वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया। 2012 के बाद से, वास्तविक परिवर्तन यह नहीं है कि “पारिस्थितिक सम्यता निर्माण” सीपीसी और चीनी सरकार की राजनैतिक पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय शासन की रणनीति के लिए एक छत्र शब्द बन गया है बल्कि यह कि पर्यावरण संरक्षण (सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से) और शासन को एक नये युग में चीनी विशेषताओं के साथ समाजवादी आधुनिकीकरण का अनुसरण करने वाले एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता मिली है।

सी.एस. : काफी समय से, आपके काम ने इको-सोशललिज्म के विचार पर ध्यान केंद्रित किया है। आप तर्क देते हैं कि “हरित” पूंजीवाद वर्तमान पारिस्थितिक संकट का हल नहीं है लेकिन न ही हरित पारंपरिक समाजवाद है। क्या आप इस तर्क पर विस्तार से बता सकते हैं और यह व्याख्या कर सकते हैं कि इको-सोशललिज्म का क्या अर्थ है ?

क्यू.एच. : संक्षेप में, एक हरित राजनैतिक दर्शन के रूप में इको-सोशललिज्म में दो प्रमुख पहलू सम्मिलित हैं : एक तरफ, यह तर्क देता है कि स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक और पर्यावरणीय चुनौतियां, विशेष रूप से समकालीन पूंजीवाद के प्रभावी संस्थागत ढांचे के तहत, सिर्फ आंशिक या अस्थायी समस्याएं या दोष नहीं हैं बल्कि वे स्वयं फ्रेमवर्क से अविभाज्य हैं : वे पूंजी विस्तार के तर्क और पूंजी-मालिकों के हितों की रक्षा का अनुसरण करते हैं। इस अर्थ में, पूंजीवादी शासन के तहत विभिन्न उपाय, तथाकथित “हरित पूंजीवाद” या “इको-पूंजीवाद” पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। बेशक, जैसा उलरिख ब्रांड एवं मार्क्स वीसेन ने अपनी पुस्तक *द लिमिट्स टू कैपिटलिस्ट नेचर* में स्पष्ट रूप से खुलासा किया, इसका मतलब यह नहीं है कि पर्यावरणीय क्षति के खिलाफ पूंजीवादी उपायों या “हरित पूंजीवाद” भी यथार्थ में पूर्ण रूप से असम्भव हैं (यद्यपि हमेशा चयनात्मक रूप से लागू किये जाते हैं)।

दूसरी तरफ, एक राजनैतिक दर्शन के रूप में इको-सोशललिज्म में जिस पर जोर दिया गया है, वह यह है कि यह एक नये प्रकार का

समाजवाद है या समाजवाद का एक अद्यतन संस्करण है और इस तरह वह पारंपरिक समाजवाद के सरलीकृत या मिथ्यात्मक हरितन से भिन्न है। यह ध्यान देने योग्य है कि कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स ने जिस वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद का सुझाव लगभग दो शताब्दियों पूर्व दिया था, एक ऐसा आदर्श है जिसे अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे पूर्व सोवियत संघ में या वर्तमान के चीन में और यह आदर्श आने वाले भविष्य में किसी देश या क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पायेगा। इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस की कल्पना या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं वह एक पूर्णतया नवीन समाजवादी समाज के बजाय हमारे समकालीन विश्व का एक इको-सोशलिस्ट अभिमुखन है। अन्य शब्दों में, आज इको-सोशलिस्ट का मुख्य कार्यों में से एक यह स्पष्ट करना है कि पूंजीवादी शासन के तहत विभिन्न उपाय आखिरकार उन समस्याओं का समाधान करने में क्यों विफल होंगे जिनके समाधान का वे दावा करते हैं, और वास्तविक या अतिवादी विकल्पों के रूप में इको-सोशलिज्म के विभिन्न उपाय क्यों सभी समाजों में वास्तव में काफी बदलाव ला सकते हैं ताकि "अन्य दुनिया वास्तव में संभव हो"।

सी.एस. : मेरे द्वारा अनुसरण किये गये कई विमर्शों में, इको-सोशलिज्म की चर्चा हरित पूंजीवाद के विकल्प में की जाती है। जिसकी भविष्य का अपना दृष्टिकोण है जो न सिर्फ पारिस्थितिक संकट के समाधान की पेशकश करता है बल्कि यह असमानता के प्रश्नों को भी सम्बोधित करता है; यह पर्यावरणीय न्याय को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ने का उद्देश्य रखता है। इको-सोशलिस्ट सम्बोधनों को आकर्षक नहीं प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों ?

क्यू.एच. : सच में, इको-सोशलिज्म की अवधारणा अभी भी उतनी लोकप्रिय नहीं है जितना लोग अपेक्षा करते हैं या तर्क देते हैं। ऐसा न केवल पूंजीवादी देशों में बल्कि चीन सहित समाजवादी देशों में भी है। मेरी राय में, इस विसंगति को समझाने के कई कारण हैं। पहला, एक राजनैतिक विचारधारा और सार्वजनिक नीति के रूप में इको-सोशलिज्म अभी भी पूर्व सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में पारंपरिक समाजवाद की दागदार प्रतिष्ठा से काफी प्रभावित है। ये देश स्पष्ट रूप से समाजवादी आदर्शों और मूल्यों के संस्थाकरण में (सरल सरकार ने अपनी पुस्तक इको-सोशलिज्म और इको-केपिटलिज्म में जैसा विश्वासोत्पादक विश्लेषण किया है) और पर्यावरणीय मुद्दों पर करने में असफल थे। इसके अलावा विश्वभर में 1990 के दशक के प्रारम्भ में समाजवादी गुट के पतन के बाद नवउदारवाद और वैचारिक निस्संदेह सफल थे। इसने अधिकांश लोगों का मानना था कि वास्तव में पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है। सबसे दिलचस्प और/या अफसोस की बात है कि इस समय यूरोप और अमरीका का 2008 के आर्थिक और वित्तीय संकट ने भी इको-सोशलिज्म सहित अतिवादी या वैकल्पिक राजनीति की संरचनात्मक स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं किया। हाल

के वर्षों में "हरित पूंजीवाद" या इको-सोशलिज्म की बढ़ती लोकप्रियता को इस तर्क के लिए समर्थन साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।

दूसरी बात, जहां तक चीन का सवाल है "इको-सिविलाइजेशन निर्माण" और "समाजवादी इको-सम्यता निर्माण" की राजनैतिक एवं नीतिगत व्याख्या इस बात पर प्रकाश डालने के लिए अच्छा उदाहरण थी कि इको-सोशलिज्म अभी एक स्थापित राजनैतिक विचारधारा और राजनैतिक पारिस्थितिकी बनने से कहीं दूर है। एक गहरी भिन्नता यह है कि क्या वर्तमान चीन के पर्यावरण संरक्षण और शासन प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए समावादी अभिविन्यास या दिशा एक संस्थागत पूर्व शर्त है या नहीं। इको-मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से, अमरीका और यूरोपीय संघ की पर्यावरण संरक्षण और शासन की तथाकथित आधुनिक संस्थाओं या तंत्रों के प्रारम्भ पर अधिक जोर देना पूरे समाज के समाजवादी पुररूथान की उपेक्षा करने के जोखिम पर होगा जो एक भावी समाजवादी इको-सम्यता के लिए आवश्यक है।

सी.एस. : भावी समाज की छवि के लिए इको-समाजवाद को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किस की आवश्यकता है ?

क्यू.एच. : कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह आज इको-समाजवादियों के लिए आवश्यक और काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबसे पहले, समाजवादी/हरित-वामपंथी राजनैतिक दल और राजनीति अभी भी भावी समाज के लिए इको-समाजवादी परिदृश्य को जनता के मध्य अधिक वांछनीय और आकर्षक के लिए प्रमुख ताकतें हैं और उनके द्वारा बहुत सारे काम किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2019 के यूरोपीय संसदीय चुनावों से एक उत्साहजनक संदेश यह है कि यूरोपीय मतदाता, विशेषकर युवा पीढ़ी, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए काफी सहायता कर रहे हैं लेकिन एक समग्र रूप में वामपंथीयों को इससे अधिक लाभ नहीं हुआ। दूसरा, इको-समाजवाद से संबंधित सभी मुद्दों पर शिक्षाविदों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए। बेशक, यह पश्चिम और विकसशील देशों के मध्य एक अधिक समान और खुले विचारों वाली द्वितरफा प्रक्रिया होनी चाहिए। सच्ची बात है कि पिछले दशकों में चीन पश्चिम का अच्छा छात्र रहा है। उसने, उन्नत देशों ने अपने देशों को आधुनिक बनाने के लिए जो किया या कर रहे हैं, का अनुकरण करने बढिया प्रयास किया है। यद्यपि अब से, चीन को अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक समुदाय का एक अधिक स्वतंत्र और चिंतनशील साझेदार बनने की आवश्यकता है और इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि देश को कैसे बेहतर बनाना है। तीसरा, इको समाजवाद को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, विशेष रूप से चीन में, प्रमुख कार्यों में से एक "नये युग में चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद" को अधिक आकर्षक बनाना है। मेरी दृष्टि से, एक महत्वपूर्ण तरीका

>>

“समाजवादी इको-सभ्यता निर्माण” के सिद्धांत और नीति को सावचेत रूप से लाना और लागू करना है।

सी.एस. : आप “विकासशील अर्थव्यवस्था” और “विकसित अर्थव्यवस्था” के मध्य अंतर करते हैं, परवर्ती जो निरंतर आर्थिक विकास पर निर्भर है, वह जो पारिस्थितिक संकट को हल करने के लिए बाधक प्रतीत होता है। चीन के संबंध में इस अंतर का क्या अर्थ है।

क्यू.एच. : मैंने 2008 में “विकासशील अर्थव्यवस्था” शब्द का उपयोग उस समय के चीन में आर्थिक विकास की प्रकृति की अवधारणा के लिए किया, यह दिखाने के लिए कि मैं कैसे लंदन स्थित एक यूनानी चिंतक, ताकीस फोतोपोलोस से अलग हूँ जिसने चीन के विकास को देखते हुए यह विश्लेषण किया कि क्या सतत विकास वैश्वीकरण के साथ सुसंगत है। मेरे मुख्य तर्क निम्न हैं : संसाधन समर्थन की वैधता, वांछनीयता और धारणीयता एवं पर्यावरणीय क्षमता दोनों के संदर्भ में 21वीं सदी के प्रारम्भ में चीन की आर्थिक वृद्धि दर काफी हद तक आवश्यक या रक्षणीय थी। बेशक, पिछले एक दशक में चीन के आर्थिक विकास की समग्र स्थिति काफी नाटकीय रूप से परिवर्तित हुई है और चीन आज अमरीका के साथ व्यापार विवाद/युद्ध के कारण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहा है।

इस विषय में वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या चीनी अर्थव्यवस्था जैसा कि ताकीस फोतोपोलोस ने परिभाषित किया था, धीरे-धीरे विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है या नहीं। मेरा चिंतन यह है कि इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं है। एक तरफ, 2015 के बाद से 6-7 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर दस वर्ष पूर्व की दर (2005 में 11.4 प्रतिशत) से लगभग आधी थी। यह दर्शाता है कि चीन लगातार विकास के विभिन्न चरणों के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को अनुकूलित कर रहा है और कम से कम चीन के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए, निकट भविष्य में एक भी उचित आर्थिक वृद्धि दर अभी भी आवश्यक है और अनुरक्षणीय है। दूसरी तरफ, आज चीन के आर्थिक समग्र को देखते हुए-विश्व बैंक के अनुसार, यह 2018 में कुल मिलाकर 13.608 ट्रिलियन अमरीकी डालर और पूरे विश्व का 15.86 प्रतिशत है। लगभग 5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर भी हमारे पारिस्थितिक वातावरण पर व्यापक और जबरदस्त प्रभाव ला सकती है। यही कारण है कि हम तर्क देते हैं कि एक इको-सोशलिस्ट परिप्रेक्ष्य या “समाजवादी इको-सभ्यता निर्माण” आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और पारिस्थितिक पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता को बेहतर ढंग से संयोजित करने की क्षमता रखते हैं : अधिक पारिस्थितिकवाद एवं अधिक समाजवाद।

सी.एस. : यूरोपीय देशों और उत्तरी अमरीका में, हरित पूंजीवाद का विचार मौजूदा पारिस्थितिक चुनौतियों का मुख्य उत्तर है। भविष्य की वैकल्पिक दृष्टि, जैसी आप सुझाते हैं, से उन्हें क्या लाभ हो सकता है ?

क्यू.एच. : यकीनन, “हरित पूंजीवाद” या “इको-पूंजीवाद” यूरोपीय देशों और उत्तरी अमरीका में मौजूदा पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे व्यावहारिक या शायद ‘तर्कसंगत’ दृष्टिकोण है क्योंकि पदानुक्रमित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था और विकासशील देशों में “रहवास के शाही तरीकों” की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण ये ‘उन्नत’ देश वैश्विक संसाधनों और सिंक को अपने फायदे के लिए काम में ले सकते हैं। यदि इस तरह का संरचनात्मक विन्यास अपरिवर्तित रहता है तो यह कल्पना की जा सकती है कि दुनिया की एक इको-समाजवादी भविष्य की ओर अग्रसर होने की बहुत कम संभावना है।

यद्यपि ऐसा लगता है कि हाल के वर्षों में यह विन्यास सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से समस्याग्रस्त बन गया है। एक तरफ, चीन सहित कई प्रमुख विकासशील देशों के आर्थिक उदय के बाद अमरीका और यूरोपीय देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की यथास्थिति को बनाये रखना और कठिन होता जा रहा है, जो न केवल पारंपरिक अर्थ में उनकी प्राधान्य स्थिति बल्कि “इको-पूंजीवाद” के उनके ग्रीन मॉडल के लिए खतरनाक होगा। दूसरे शब्दों में इन “उन्नत देशों के लिए भौतिक उपभोग के उच्च स्तर का आनंद लेते हुए अपने स्थानीय वातावरण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए यथार्थ में बहुत कम स्थान या संभावना होगी। अमरीका के नेतृत्व में पश्चिम और चीन के मध्य बढ़ते तनाव को कुछ हद तक, इस संदर्भ में देखा जा सकता है। दूसरी ओर, अधिकाधिक विकासशील देश, विशेषरूप से चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं, पारिस्थितिक पर्यावरणीय समस्याओं को भिन्न कारणों से गंभीरता से ले रही हैं। जैसा कि फिलीपींस और कनाडा के मध्य अपशिष्ट आयात पर विवाद ने स्पष्ट रूप से दिखाया है, इसका मतलब है कि कचरे और कूड़े को छोड़कर “मलिन” पूंजी और प्रौद्योगिकी की स्वीकृति पर विकासशील देशों की तरफ से अधिक और कड़े प्रतिबंध होंगे।

उपर वर्णित दोनों अर्थों में, मेरी राय में इको-समाजवाद के सिद्धांत और सोचने के तरीके अंततः यूरोपीय और उत्तर अमरीकी देशों को “हरित पूंजीवाद” या “इको-समाजवाद” की सीमाओं और दोषों की समझको विकसित करने में योगदान दे सकते हैं। स्थानीय या अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करना जबकि अन्य अतिवादी सामाजिक-पारिस्थितिक रूपांतरण की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। एक अधिक स्वच्छ वातावरण के लिए एक अधिक न्यायसंगत विश्व और अधिक समान समाज एक पूर्व शर्त है। ■

सभी पत्राचार किंग्डी हुआन को <qzhuang@sdu.edu.cn> पर प्रेषित करें।

> द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के 75 वर्ष

ब्रिजित ऑलेनबेकर, जोहांस केप्लर विश्वविद्यालय लैंज, ऑस्ट्रिया एवं आई.एस.ए. की अर्थव्यवस्था और समाज (आर.सी. 02), निर्धनता, समाज कल्याण और सामाजिक नीति (आर.सी.19), कार्य का समाजशास्त्र (आर.सी. 30) एवं महिलाएं, लिंग और समाज (आर.सी. 32) पर शोध समितियों की सदस्य और एंड्रियास नोवी, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ़ इकोनॉमिक्स एण्ड बिजनेस (डबल्यू यू), ऑस्ट्रिया द्वारा



कार्ल पोलांन्यी की पुस्तक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की महत्ता और सतत् प्रासंगिकता कई भाषाओं में अनुवादित होने के कारण प्रदर्शित होती है।
श्रेय: एना गोमेज

सन् 1944 में प्रकाशित, कार्ल पोलांन की महान कृति, *द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन (टीजीटी)* 1920 और 1940 के दशक के मध्य उनके सामने होने वाले घटनाक्रमों के संदर्भ में पूंजीवाद के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करती है। इनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद का बाजार रूढ़िवाद, 1929 में उसके परिणामस्वरूप उपजा संकट और स्टॉक मार्केट क्रैश, महामंदी, अर्थव्यवस्था एवं समाज को पुनः व्यवस्थित करने की फासीवादी और समाजवादी कोशिशें, द न्यू डील एवं अंत में, द्वितीय विश्वयुद्ध सम्मिलित हैं।

द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इस बात की गहन जांच करती है कि यदि अर्थव्यवस्था और समाज "स्व-नियमित बाजार" (कार्ल पोलांन, *द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन: द पोलिटिकल एण्ड इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ़ टाइम*, बोस्टन: बीकान प्रेस, 2001 संस्करण, पृष्ठ-141) के उदार पंथ के अनुसार संयोजित हो और समाज सामान मांग, आपूर्ति, मूल्य और बाजार की लाभउन्मुख गतिशीलता के द्वारा चलित अधिकाधिक एक "बाजार समाज" बन जाता है तो पूंजीवाद के इतिहास में क्या हुआ और क्या हो सकता है। इस तरह की व्यवस्था में, जहां "मानव समाज आर्थिक व्यवस्था का सहायक बन जाता है" (टीजीटी 79), भूमि (प्रति) श्रम एवं धन, जैसे वे तत्व जो कभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध या उत्पादित नहीं किए गए थे— "काल्पनिक वस्तु" बन जाते हैं। "लेकिन श्रम एवं भूमि स्वयं भी मनुष्य के अलावा नहीं है जिनसे प्रत्येक समाज बनता है और प्राकृतिक परिवेश जिसमें यह मौजूद रहते हैं। उन्हें बाजार तंत्र में सम्मिलित करने का अर्थ है समाज के स्वयं के अस्तित्व को बाजार के नियमों के अधीन करना" (टीजीटी 74) एवं यह इसके "विध्वंस" (टीजीटी 75) की ओर ले जाना है। कार्ल पोलांन उन्नीसवीं सदी के पूंजीवाद के इतिहास का विश्लेषण एक "दोहरे आंदोलन" के परिणाम के रूप में करते हैं। इसमें बाजारीकरण और उसके प्रतिरोधी आंदोलनों श्रम आंदोलन, कानून, संरक्षणवाद इत्यादि—की तरफ चलना जिनके द्वारा मानव समाज सुरक्षा और संरक्षण चाहता है, सम्मिलित हैं।

2014 में योकोहामा में आई.एस.ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में माइकल बुरावे ने टीजीटी के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि कैसे 1970 के दशक में प्रारंभ "बाजारीकरण" की नई "लहर", 1989 के बाद में वैश्वीकरण साम्यवाद पश्चात के दौर, 2007-08 के वित्तीय संकट, और

उत्तरगामी सामाजिक प्रतिरोधों को पोलांन के दोहरे आंदोलन के रूप में समझा जा सकता है। और वास्तव में, विशेष रूप से 1990 के बाद से पोलांन के कार्य में दिलचस्पी बढ़ गई है। दुनिया भर से विद्वान "दोहरे आंदोलन" के उनके विश्लेषण का उल्लेख कर रहे हैं और "काल्पनिक वस्तुओं" के उनके रूप को काम में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे "एक जटिल समाज में स्वतंत्रता" पर भी उनकी श्रुति और एक न्याय पूर्ण और मुक्त समाज पर उनके विचारों को पुनः खोज रहे हैं जो तब संभव हो सकते हैं जब औद्योगिक सभ्यता के इतिहास में स्व-नियमित बाजार का आदर्शवादी प्रयोग स्मृति मात्र से अधिक नहीं हो। (टीजीटी 258)।

यह संगोष्ठी टीजीटी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को कार्ल पोलांन के त्यों के इतिहास के साथ-साथ उनके श्रुतिकोणों एवं उपागमों को काम में लेने वाले आलेखों को प्रस्तुत कर मानती है। फ्रेड ब्लॉक और मार्गरेट आर सोमर्स नवउदारवाद के गुरु हायेक एवं माइस के संदर्भ में कार्ल पोलांन के समय के काम को पढ़ते हैं। इसके साथ ही वे फासीवाद का भी संदर्भ लेते हैं और आज की सत्तावादी अभिवृत्तियों को समझने में इसकी प्रासंगिकता दर्शाते हैं। एंटोनिनो पालुम्बो एवं एलन स्कॉट ने राज्य-बाजार के सरल द्विभाजन को दूर किया और यह व्याख्या देते हैं कि राज्य बाजारों का समर्थन क्यों और कैसे करते हैं। गैरथ डेल लाभ पर आधारित आर्थिक व्यवस्था को स्थिर करने वाले राष्ट्रीय लेखांकन के इतिहास की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। और इन प्रतिबिंबों से उपजी "जीडीपी के परे" बहस को कथित तौर पर कार्ल पोलांन की व्याख्या के रूप में समस्या ग्रस्त किया जाता है। जोनाथन डी. लंदन पूर्वी एशिया में महान रूपांतरण की जांच करते हैं और वे बाजारीकरण और कल्याण नीतियों के समकालिक वृद्धि के विरोधाभास पर ध्यान देते हैं। अटिला मेलेग एवं क्रिस हैन यूरोप में प्रवास और घटनाक्रमों के संबंध में दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद पर कार्ल पोलांन के समय के समकालीन चिंतन की गहरी समझ रखते हैं। एंड्रियास नोवी पोलांन की चिरस्थायी विरासत, सामाजिक आंदोलनों के लिए उनकी प्रेरणा, समकालीन "वैश्विक" पूंजीवाद की उनकी आलोचना, और उनके द्वारा विकल्पों की तलाश पर जोर देकर बात समाप्त करते हैं। ■

सभी पत्राचार ब्रिजिट ऑलेनबेकर को <brigitte.aulenbacher@jku.at> और एंड्रियास नोवी को <andreas.novy@wu.ac.at> पर प्रेषित करें।

>75 वर्ष पर पोलान्थी की द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन

फ्रेड ब्लॉक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस, यूएसए एवं मार्गरेट आर सोमर्स, मिशीगन विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा



कार्ल पोलान्थी, डबल्यू डबल्यू आई। श्रेय: कार्ल पोलान्थी लेवित

सन् 1964 में जब पोलान्थी का निधन हुआ, उनके बौद्धिक योगदानों के बारे में ग्रीक एवं रोमन पुराकाल के विद्वानों के अलावा कोई नहीं जानता था। एक शरणार्थी बुद्धिजीवी के रूप में, पोलान्थी ने अपने जीवन काल को चार अलग देशों—ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, अमेरिका एवं कनाडा में व्यतीत किया था। इसके अलावा, वे किसी एक विषय से संबंधित नहीं थे; उनके कृत्य इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं श्रेष्ठ ग्रंथों के मध्य से गुजरते हैं। इस सबने उनके लिए अनुयायियों के महत्वपूर्ण समूह, जो अन्य महत्वपूर्ण शरणार्थी बुद्धिजीवियों की प्रतिष्ठा को बनाये रखे थे, को एकत्रित करना कठिन बनाया।

इसके अलावा, पोलान्थी अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में एक अविश्वसनीय पैगंबर साबित हुए। उन्होंने अंतिम अध्याय में यह सुझाव दिया कि दुनिया ने आखिरकार यह मान लिया कि वैश्विक स्व-विनियमन बाजार बनाने का विचार गलत था। वास्तव में, द्वितीय विश्वयुद्ध—पश्चात की आर्थिक व्यवस्था में “सन्निहित उदारवाद” युद्ध-पूर्व की स्वर्ण मानक व्यवस्था जितना विनाशकारी नहीं था। लेकिन 1940, 1950 एवं 1960 के दशक में निर्मित कीन्स के कल्याण राज्य पोलान्थी द्वारा कल्पित समाजवाद के प्रकार से काफी दूर थे। इसके अलावा, पोलान्थी शीत युद्ध के आगमन या एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था जिसमें माल और पूंजी राष्ट्रीय सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकते हैं, को पुनःनिर्मित करने की वॉशिंगटन के संकल्प का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे।

विडंबना यह है कि उनके निधन के बाद होने वाली घटनाओं ने एक पैगंबर के रूप में पोलान्थी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। 1920 के दशक में वियना में, पोलान्थी ने लुडविन वॉन और उनके विद्यार्थी फ्रेडरिख हायेक के बाजार कट्टरवाद के विरोध में अपने विचार विकसित किए। पोलान्थी के निधन के 10 वर्ष पश्चात, हायेक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला और उसके कुछ वर्ष पश्चात उन्हें मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन की मुक्त बाजार आर्थिक नीतियों के लिए सैद्धांतिक प्रेरणा के लिए सराहा गया। संक्षिप्त में, बाजार की कट्टरवादी नीतियों के गत चार दशकों ने पोलान्थी को एक असफल पैगंबर से स्वनिर्णयित बाजार की शक्तियों और खतरों के सबसे अधिक प्रसिद्ध और भविष्यदर्शी विश्लेषक में परिवर्तित कर दिया।

> स्वर्ण मानक मितव्ययता एवं फासीवाद

द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में, पोलान्थी सुस्पष्ट रूप से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मानकों की बहाली पर फासीवाद के उदय का आरोप लगाते हैं। इस निर्णय के लिए बोल्शेविकों सहित सभी प्रकार के राजनेता जिम्मेदार थे। लेकिन एक बार यूरोप भर में स्वर्ण मानक की मितव्ययता की कठोरता आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ने लगी तो समाजवादी एवं राजनीतिक उदारवादी समान रूप से इसके विरोध में आ गए। यह विरोध न सिर्फ मजदूरी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के कठोर शमन के लिए था बल्कि लोकतंत्र के निरर्थक—करण के लिए भी था।

दूसरी तरफ, बैंक कर्मी और अधिकांश नियोक्ताओं ने जोर दिया कि स्वर्ण मानक प्रकृति के आर्थिक नियमों को साकार करते हैं और इन तंत्रों से छेड़छाड़ करने से आर्थिक तबाही होगी। बढ़ती आर्थिक अस्थिरता एवं बड़े पैमाने पर बेराजगारी के सम्मुख सरकारी निष्क्रियता के पक्ष में वॉन मिज और हायेक के सैद्धान्तिक औचित्य के अभाव में उनके तर्कों को भले ही स्व-रुचि वाली दलीलों के रूप में खारिज कर दिया जा सकता था। पोलान्थी के लिए, सिर्फ यह नहीं था कि वॉन मिज और हायेक ने ऐसी नीतियों की वकालत की जो क्रूर और अनैतिक थी; यह कल्पना करना बेमानी था कि लाखों परिवार, जिनमें से अधिकांश के पास आर्थिक शक्ति का अभाव था, आर्थिक वंचना के साथ निलिप्त भाव से अनुकूलन करेंगे। उन्होंने यह भी देखा कि जब कामकाजी लोगों ने सार्वजनिक प्रावधानों, समुचित मजदूरी एवं बेरोजगारी लाभों के समर्थन में मतदान किया, तब इन प्रयासों को मित्यत्ता के नाम पर रोका गया। इसका तात्कालिक परिणाम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से गहरा मोहभंग था क्योंकि स्वर्ण मानक नियमों ने लोकप्रिय संप्रभुता को बुरी तरह से पछाड़ दिया था। फासीवादी दलों ने इस मोहभंग का लाभ उठाते हुए उस तरह की सुरक्षा का वादा किया जिसे वैश्वीकरण करने वालों ने प्रदान करने से मना किया था। अतः पोलान्थी के लिए, "उदारवादियों (आर्थिक) द्वारा नियोजन, विनियमन या नियंत्रण से जुड़े किसी भी सुधार को बाधित करने से फासीवाद की जीत व्यवहारिक रूप से अपरिहार्य बन गई।" लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद, हिटलर ने स्वर्ण मानक बाधाओं की अवहेलना की। पूर्ण रोजगार बहाल करने के लिए तेजी से कदम रखते हुए नाजी लोकप्रिय समर्थन जीतने और अपनी तानाशाही को पूरी तरह से संगठित करने में समर्थ हुए।

> बाजार कट्टरवाद एवं सत्तावाद

इस वर्तमान क्षण की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। 40 वर्ष के बाजार कट्टरवाद ने स्थाई मितव्ययता के शासन का निर्माण किया जहां सरकारों, को एक बार फिर से, रोजगार के स्तर को बढ़ाने या बाजार की अनिश्चितता से परिवारों को बचाने से प्रभावी रूप से अवरुद्ध किया गया है। एक सरकार के लिए इन मान्यताओं को चुनौती देने पर विचार करना भी सावरेन ऋण की बाजारी बिकवाली और गतिशील पूंजी के अचानक बहिर्वाह के रूप में तत्काल प्रतिक्षेप को ट्रिगर करेगा। ग्रीस में वामपंथी सीरिजा सरकार जो एक गैर मितव्ययता मंच पर निर्वाचित हुई थी, को भी यूरोपीय समुदाय द्वारा कठोर मितव्ययता नीतियों को जारी रखने पर मजबूर किया गया।

एक बार फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्थाई मितव्ययता से राहत प्रदान करने में उनकी विफलता से व्यापक मोहभंग है।

लोकतांत्रिक मानदंडों और संस्थाओं के प्रति इस अवमानना का लाभ उठाकर दक्षिणपंथी दल अधिक मजबूत हुए। अंत में, निर्वाचित अधिनायकवादी नेताओं की एक नई नस्ल ने चुनावी हेरफेर, न्यायिक अधिग्रहण, स्वतंत्र मीडिया के दमन और घृणा की राजनीति जो लोगों को लोगों के "अन्य" से विभाजित करती है की विशेषता वाले "अनुदार लोकतांत्रिक" के मॉडल को अपनाया है।

वास्तव में, आज के अधिनायकवादी बीसवीं सदी के फासीवादियों के समान नहीं है। लेकिन समान वर्दी वाले अर्धसैनिक विन्यास की अनुपस्थिति से आश्वस्त होना मूर्खता होगी। ऐतिहासिक अनुकरण तुलना के लिए सार्थक मापदंड नहीं है। पोलान्थी ने देखा कि अंतरयुद्ध फासीवादी खतरा स्वर्ण मानक की आमोघ सत्ता द्वारा निर्मित लोकतंत्र के एक संकट की प्रतिक्रिया था। एक बार फिर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को शासित करने वाली संस्थाओं द्वारा उत्पन्न संकट का सामना कर रहे हैं। अपने पूर्ववर्तियों की तरह, समकालीन अधिनायकवादियों ने संकट द्वारा निर्मित निर्वात में कदम रखा है और कुछ मामलों में उन्होंने अभी से ही "विस्मृत व्यक्ति" की रक्षा के नाम पर अपने "शत्रुओं" को सताना प्रारंभ कर दिया है।

आज का सबक वैश्विक आर्थिक सुधार की एक परियोजना की अत्यावश्यकता है जो स्थाई मितव्ययता की बाधाओं को तोड़ सके और नपुंसक लोकतंत्र के संकटों को नष्ट कर दे। निश्चित रूप से, एक शक्तिशाली वैश्विक सुधार आंदोलन के निर्माण की चुनौती विशालकाय है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शरणार्थियों की संख्या में नाटकीय वृद्धि और एक अधिकाधिक अव्यवस्थित वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे संकटों का सामना करने के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग को जनना कोई सरल बात नहीं है। लेकिन इस समय, वैश्विक ग्रीन डील की योजना जो वैश्विक उत्तर से वैश्विक दक्षिण में संसाधनों का पुनर्वितरण करेगी, के इर्द-गिर्द विश्व की अधिकांश आबादी को एकजुट करना शायद संभव होगा। यह जलवायु परिवर्तन की आपातक स्थिति को संबोधित करेगी एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं और नियमों को बदल देगी। यह वैश्विक पहल राष्ट्रों और राष्ट्रीय क्षेत्रों के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति के नवीनीकरण एवं सभी लोगों के लिए कार्य करने वाली अर्थव्यवस्था को निर्मित करने वाली सुधारों की लहर के लिए स्थान खोलेगी। ■

सभी पत्राचार फ्रेड ब्लॉक को <fi_block@ucdavis.edu>
और मार्गरेट आर सोमर्स को <peggs@umich.edu>
पर प्रेषित करें।

> स्टेटक्राफ्ट के रूप में बाजार : एक पोलान्यी व्याख्या

एंटोनिनो पालुम्बो, पलेर्मो विश्वविद्यालय, इटली एवं एलन स्कॉट, न्यू इंगलैण्ड विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया और नगरीय एवं प्रादेशिक विकास के समाजशास्त्र पर आईएसए शोध समिति (आर.सी. 21) के सदस्य द्वारा



1950 के दशक के उत्तरार्ध में पिकरिंग, ऑंटारियो में कार्ल पोलांन्यी।
श्रेय: कार्ल पोलांन्यी लेविट

अर्थशास्त्र (रूढ़िवादी) को छोड़कर, सामाजिक वैज्ञानिकों और विशेष रूप से समाजशास्त्री और सामाजिक मानवविज्ञानी काफी समय से इस बात पर सहमत हैं कि शुद्ध प्रतिस्पर्धी बाजार मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति नहीं है। इस सर्वसम्मति से इन्होंने राज्य हस्तक्षेप के विस्तारित रूपों को सही ठहराने के लिए राज्य सम्प्रभुता के अनगिनत बचावों की पहल की है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से इन प्रयासों को दुगुना कर दिया गया है। जीएफसी, जिसे संप्रभु ऋण के संकट के संदर्भ में फ्रेम किया गया और मित्तव्यवस्था उपायों से सम्बोधित किया गया, के बाद से राज्य कार्यवाही की वकालत ने दो मुख्य स्वरूप लिए : (i) कीन्स के सिद्धांतों की रक्षा और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने की तरफ निर्देशित समष्टि अर्थशास्त्र हस्तक्षेपों का आह्वान, (ii) सामाजिक विषमताओं को कमतर करने वाले पुनर्वितरण उपायों का समर्थन करते हुए युद्ध-पश्च कल्याणकारी राज्यों की पुरानी यादों का प्रचार। प्रगतिवादियों के मध्य व्यापक रूप से फैले ये प्रत्युत्तर वैचारिक और प्रमाणिक दोनों आधारों पर विफल हैं। वे अब तक आमतौर पर स्वीकार्य लेकिन बेबुनियाद नवउदार दावा कि राज्यों और बाजारों के मध्य एक अपरिहार्य समंजन है, को चनौती देने और वास्तव में बनाये रखने में विफल रहते हैं।

> बाजार के हिमायती के रूप में राज्य

गत दो शताब्दियों का सामाजिक और राजनैतिक इतिहास राज्य और बाजार के मध्य सम्बंधों के शून्य-राशि विवरण का समर्थन नहीं करता है। कार्ल पोलांन्यी की *द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन* (प्रथम बार 1944 में प्रकाशित) अभी भी सर्वश्रेष्ठ सैद्धान्तिक विवरण प्रदान करती हैं। उदार राजनैतिक अर्थव्यवस्था के शास्त्रीय सामाजिक सिद्धांत की आलोचना का सारांश प्रस्तुत करते हुए पोलांन्यी तर्क देते हैं कि बाजार समाज को लाने हेतु डिजाइन की गई अबंध नीतियां एक राजनैतिक योजना का परिणाम थी जबकि संरक्षणात्मक विनिमय की लहरों का समर्थन करने वाले सामाजिक दबाव इन नीतियों द्वारा उत्पादित तनावों के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थे। बाजार को राजकीय कृत्य बनाने हेतु पोलांन्यी मार्क्सवादी उपागम की तुलना में राजनैतिक आर्थिक सोच की मान्यताओं को अधिक अतिवादी रूप से खारिज करते हैं। वे राज्य को बाजार व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश के सर्जक और

बाजारों को उनके द्वारा उत्पादित चक्रीय संकटों से बचाने वाले चैम्पियन के रूप में देखते हैं। बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारी समिति के होने से कहीं दूर, राज्य बाजार का निर्माण करने में और उसे राजनैतिक कारणों के लिए परिवर्तित करने में सलग्न हैं। ऐसा वे अपनी संप्रभु शक्ति को मजबूत करने के लिए न कि राजनैतिक और तकनीकी आयोजन के मध्य उदार या नवउदार विचारों द्वारा अर्जित आधिपत्य के कारण करते हैं।

बाजार राज्य को अपनी संप्रभु शक्ति को बढ़ावा देने में कैसे मदद कर सकते हैं? पोलान्थी द्वारा प्रदत्त परिवर्तन के विवरण से जो उत्तर हमें मिलता है, वह है कि बाजारों में विभिन्न उपसमूहों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बना कर सामुदायिक जीवन का आधार प्रदान करने वाले सहकारी संबंधों को कमतर करने की क्षमता है। वैसे भी, बाजार सैन्य और दमनकारी ताकतों के समुदायों को एक नर्म-शक्ति विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आंतरिक सुसंगता एवं नियामक स्वायत्तता को कमतर करते हैं जिसके फलस्वरूप राज्य के कर्त्ता एक केन्द्रीकृत, नौकरशाह इच्छाशक्ति को लागू करने के शीर्ष पाद प्रयासों के तरफ सामाजिक विरोध को दूर करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। सामंती प्राधिकारियों, मध्यस्थ निकायों, पेशेवर संघों और निरंकुश राज्य द्वारा प्रारम्भ की गई एवं उदार राज्यों द्वारा जारी रखी गई गिल्ड्स का यह प्राथमिक उद्देश्य था। सोवियत राजनेताओं द्वारा बाजार समाजवाद में दिखाई गई रूचि और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा नव उदार बाजारों को अंगीकार करना इस तर्क को दर्शाता है। हमें न ही उन तरीकों को नजरअंदाज करना चाहिए जिसमें बाजार प्रतिमानों को चुनिंदा और सामरिक तरीके से उन समुदायों और समूहों को कमजोर करने के लिए काम में लिया गया है जिन्होंने राज्य के नौकरशाही अतिक्रमण का सक्रिय रूप से विरोध किया है।

मार्क्स (एवं उनके अनुयायियों) के विपरीत, पोलान्थी की बाजारों की आलोचना श्रमिकों के शोषण और/या अलगाव के प्रश्न से संबंधित नहीं हैं, बल्कि यह उसके विघटनकारी परिणामों : सामाजिक संसर्ग को विनियमित करने और मानक सामंजस्य बनाए रखने की समूहों की क्षमता के क्षरण से संबंधित है।

> एक औपनिवेशिक तर्क

इस केन्द्रीय अभियान को आगे बढ़ाने में राज्य प्राधिकारी घरेलू स्तर (स्वदेशी समुदायों और आंतरिक शत्रुओं को दबाने के लिए) और अंतर्राष्ट्रीय स्तर (विदेशी क्षेत्रों और आबादी पर राज्य के प्रभुत्व को लागू करने के लिए) दोनों पर औपनिवेशिक तर्क को लागू करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखने में, ये दोनों गतिविधियां अंतरंग रूप से जुड़ी हुई हैं। बाह्य विस्तार एक मुख्य तरीका रहा है जिसके माध्यम से राज्य बाजार सुधारों द्वारा उत्पन्न बढ़ते आंतरिक सामाजिक संघर्षों — तथाकथित "सामाजिक प्रश्न", को निरुत्साहित करने में सक्षम हुआ है। उपनिवेशीकरण के आंतरिक और बाहरी स्वरूपों के मध्य समानता को सहकारी संबंधों, जिन्हें राज्य अन्य सामाजिक कर्त्ताओं के साथ स्थापित करना चाहते हैं, में भी देखा जा सकता है। घरेलू स्तर पर राज्य के समेकन की प्रक्रिया ने बोझ और लाभ दोनों को साझा करने को

तैयार विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अभिजनों के साथ कपटपूर्ण गठबंधन की अपेक्षा करी है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपनिवेशिक शक्तियाँ हमेशा से आज्ञाकारी प्रजातीय समूह या सामाजिक कुलीन वर्ग जिसके साथ वे औपनिवेशिक उद्यम के लाभों का साझा करती हैं, के समर्थन पर निर्भर रही हैं। दोनों ही मामलों में, इस तरह स्थापित कपटपूर्ण गठबंधनों की एक प्रतिस्पर्धी प्रकृति है जो अपने सदस्यों को समय-समय पर स्वसेवारत तरीकों से साझेदारी की शर्तों पर पुनः बातचीत करने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार आर्थिक और राजनैतिक संकटों ने अन्य साझेदारों पर जिम्मेदारी हस्तांतरित करने और बाजार प्रणाली को पुनर्जीवित करने के अवसरों का प्रतिनिधित्व किया है जो पोलान्थी द्वारा वर्णित विनियम और अविनियमन के चक्रों का निर्माण करता है।

> सामाजिक और राजनैतिक को पुनः जोड़ना

इस जटिल रणनीतिक संदर्भ और राज्यों एवं बाजारों की परस्परनिर्भरता के आलोक में राज्य संप्रभुता पर जोर और अधिक राज्य एवं कम बाजार के लिए आह्वान केवल सरल नहीं बल्कि विकृत है। राज्य कार्यों के लिए सामाजिक समर्थन वास्तव में उन आपातकालीन उपायों को पारित करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम में लिया जाता है जो, राज्य के कर्त्ताओं को जिस गठबंधन का वह हिस्सा है, के साथ पुनः सौदेबाजी की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह, सावरेन मुद्रा डिफाल्ट, कर वृद्धि और पूंजी के गायब होने के प्रति आशंका को एकाधिकारी आर्थिक शक्तियों और सौदेबाजी की मेज पर बैठे सामाजिक कुलीनों के हाथों को मजबूत करने के लिए शोषित किया जाता है। पिछला दशक जीएफसी द्वारा कमतर किये नवउदार सर्वसम्मति के लिए उत्तरदायी कपटी गठबंधन के सदस्यों द्वारा चली गई चालों और उनके पलटवार का प्रतीक है। पिछली गलतियों को दोहराने से बचने के लिए, हमें ऐसे समाधानों की आवश्यकता है जो निर्धनों की रक्षा के लिए कल्याणकारी उपायों की वकालत से आगे जायें। सामाजिक प्रश्न को राजनैतिक प्रश्न के साथ जोड़ना होगा : बाजार और सरकार दोनों का लोकतांत्रिकरण। सामाजिक अधिकारों और औद्योगिक लोकतंत्र की पोलान्थी की अपील ऐसी आवश्यकता की स्वीकारोक्ति थी। लेकिन नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकतंत्र के विस्तार को अब रोजगार के संदर्भ से आगे जा कर अन्य बातों के मध्य-विस्तारित उपभोक्ता अधिकार, निगरानी (राज्य एवं कार्पोरेट दोनों) पर वैधानिक रूप से प्रतिष्ठापित सीमा, रियल एस्टेट और वित्तीय सट्टेबाजी को रोकने के उपाय और पर्यावरण, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रश्नों को संकीर्ण आर्थिक हितों से दूर भावी पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व की ओर विस्तारित होना चाहिए। इसका विकल्प एक विफल नवउदारवाद के यूटोपिया के वर्तमान और भावी आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिणामों के साथ रहना है। ■

सभी पत्राचार एंटोनियो पालुम्बो को <antonino.palumbo@unipa.it>
और एलन स्कॉट को <ascott39@une.edu.au>
पर प्रेषित करें।

> पोलान्थी, लेखांकन एवं 'जीडीपी के परे'

गैरेथ डेल, ब्रुनेल विश्वविद्यालय, लंदन, यू.के. द्वारा



वियना में कार्ल पोलान्थी, 1923
श्रेय: कार्ल पोलान्थी लेविट

समाजवादी जवाबदेही के प्रश्न पर लुडविग वॉन मिज पर बहस करते हुए कार्ल पोलान्थी ने निम्न टिप्पणी की। “लेखांकन आर्थिक गतिविधियों का एक मात्रात्मक अवलोकन है। उदाहरण के लिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ के ईर्द गिर्द घूमती है इसलिए इसका लेखा-जोखा पूंजी के प्रत्येक तत्व का लाभ से संबंध की समीक्षा प्रदान करता है। सेना की गतिविधि धन और सामान को खर्च कर अपने सैन्य तकनीकी लक्ष्यों को प्राप्त करने तक सीमित रखती है इसलिए इसकी समीक्षा, कुछ अर्थों में एक साध्य बन जाती है : यह नियंत्रण को समर्थ बनाती है...।” वे आगे कहते हैं, अतः लेखांकन की प्रत्येक विशेष प्रणाली का कार्य सिर्फ निम्न है: लेखांकन को हमारे समक्ष

आर्थिक गतिविधियों के बारे में उठने वाले प्रश्नों के मात्रात्मक उत्तर की पेशकश करनी है। इन प्रश्नों का चरित्र उनके उत्तर प्रदान करने वाली लेखांकन प्रणाली के चरित्र का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लाभ को अपना व्यवहारिक लक्ष्य बनाती है, इसलिए इसकी लेखांकन प्रणाली को लाभप्रदता की अनिवार्यता के साथ उसके प्रत्येक चारित्रिक विशेषता के सम्बंध को मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत कर समीक्षा का काम सौंपा जाता है।

इस अवतरण में, पोलान्थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लेखांकन सिद्धांत की पहचान करते हैं: यह लाभ के ईर्द गिर्द घूमता

है। वे एक अलग प्रकार के उदाहरण के रूप में सेना की लेखांकन प्रणाली (यह नियंत्रण को समर्थ बनाती है) का भी उदाहरण देते हैं। आइये संक्षेप में प्रारम्भिक महान लेखांकन बहसों और युद्ध काल के परिवर्तनों से प्रारम्भ कर इसकी जांच करते हैं। एक, समाजवादी लेखांकन बहस थी, जिसमें पोलान्सी ने भाग लिया था। दूसरी, राष्ट्रीय आय लेखांकन में क्रांति थी। यहां अमरीकी संस्थागत अर्थशास्त्री वेस्ले मिशेल अग्रणी थे। वे नव-शास्त्रीय सिद्धांतों के “गुणात्मक” रूप के आलोचक थे और उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रमाणीकरण के संचार का आह्वान किया। अर्थशास्त्र को माप योग्य, और इसलिए, ठोस स्थान पर स्थित होना चाहिए।

> राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्म

पोलान्सी के समाजवादी लेखांकन बहस में हस्तक्षेप करने से पहले ही, 1920 में मिशेल ने राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना की। इसका उद्देश्य आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से एकत्र करना और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का परिशुद्ध सांख्यिकीय विवरण विकसित करना था। मिशेल राष्ट्रीय आय के एक आधुनिक अवधारणा के डिजाइनर में से एक थे। ऐसा उन्होंने वास्तविक आंकड़े जो तथाकथित रूप से इस अवधारणा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रस्तुत कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने जिसे फिलिप मिरोव्स्की ने अपनी पुस्तक *द बर्थ ऑफ बिजनेस साइकिल* में “एक नव सैद्धांतिक ईकाई” कहा, को गढ़ा। इस कार्य ने अर्थशास्त्र में वृहद आर्थिक क्रांति के लिए मंच तैयार किया; कीन्स के सामान्य सिद्धांत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए भी 1932 में, अमरीकी कांग्रेस ने मिशेल के विद्यार्थी साइमन कुजनेत्स को देश के उत्पादन को मापने के तरीके ईजाद करने के लिए अधिकृत किया। कुजनेत्स के काम के फलस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) एवं जीडीपी विकसित हुए। 1930 के दशक में कोलिन क्लार्क द्वारा वार्षिक तौर पर वास्तविक आय की वृद्धि दर “सांख्यिकी तरीके से का अनुमान लगाने के साथ-साथ एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम गतिशील मॉडल”, जिसे जेन टिनबर्गेन ने 1936 में प्रकाशित किया, को विकसित करने का प्रयास किया।

सर्वप्रथम, राष्ट्रीय आय लेखांकन एक सुधारवादी लहर के द्वारा किया गया था। यदि सरकार को मंदी के वर्षों के दौरान होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करना था, तो उसे सांख्यिकीविदों की मदद की जरूरत थी। कुजनेत्स के प्रारम्भिक ड्राफ्ट ने राष्ट्रीय लेखांकन को कल्याणकारी आधार पर विकसित करने की कोशिश करी जिसमें ‘गुडस’ सम्मिलित किये गये लेकिन ‘बेडस’ जैसे युद्धसामग्री को व्यय में से घटाया गया। लेकिन कुजनेत्स और मिशेल का कल्याण की तरफ झुकाव को, जैसा मैरियन फोरकेड *इकोनोमिस्ट्स एण्ड सोसाइटिस* में नोट करते हैं, जब युद्ध योजना और फिर कीन्स के व्यक्ति अर्थशास्त्र एवं मांग प्रबंधन के दबाव हावी हो गये, दरकिनार कर दिया गया। कुजनेत्स स्वयं ने वॉर प्रोडक्शन बोर्ड में सैन्य योजना पर राष्ट्रीय आय लेखांकन तकनीकों, जिन्हें उन्होंने वाणिज्य विभाग में विकसित करने में मदद की थी, पर कार्य किया था। इसी प्रक्रिया में सैन्य व्यय (निजी वेतन एवं हथियारों की खरीद) को जीडीपी में सम्मिलित किया गया। यह तब भी हुआ जब कल्याणकारी भुगतानों (सामाजिक सुरक्षा एवं बेरोजगारी लाभ) ने स्वयं को बाहर पाया।

> जीडीपी के साथ समस्या

साररूप से, जीडीपी वैध रूप से किये गये लेनदेन के विनिमय मूल्य के दृष्टिकोण से आर्थिक गतिविधियों का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह वस्तुकरण को “पुरुस्कृत” करता है : एक गाना गाओं और जीडीपी नहीं बढ़ती है, लेकिन वही गाना गाओ और यह मांग करो कि आपके श्रोता टिकिट खरीदें तो यह बढ़ेगी। जीडीपी उन लेनदेन को बाहर करती है जिसमें किसी प्रकार के धन का लेनदेन नहीं होता है—जैसे घरेलू कार्य, डीआइवाय, एवं स्वैच्छिक कार्य। यह लैंगिक रूप से अंधा एवं वर्ग अंधा है। यह आय वितरण की उपेक्षा करता है। विनिमय मूल्य की तरह, यह प्रकृति के लिए भी अंधा है। यह संसाधनों के क्षरण को अनुपातिक रूप से बिना घटाये, प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री को आय मानता है। यह बाह्यता का कोई हिसाब नहीं रखता है।

जीडीपी फिर विनिमय मूल्य के वर्चस्व वाली दुनिया के लिए उपयुक्त एक विशिष्ट माप है; यह वास्तव में एक पूंजीवादी तरीका है। लेकिन, समान रूप से, यह राज्यों द्वारा विकसित एक सूचकांक है और इसे “भू-राजनैतिक प्रतिस्पर्धा पर नजर रखते हुए “राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था” का विहंगावलोकन प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह एक सूचकांक है जो पूंजीवादी राज्यों की प्रकृति और आवश्यकताओं को दर्शाता है। ये तत्काल ही लाभ में नहीं बल्कि पूंजी के हित में समाजों के प्रबंधन में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि सेना के सांख्यिकीय समीक्षा के रूप तब भी जब उसमें नियोजन शामिल हो, को पूंजीवादी व्यवसाय के पूरक के रूप में नहीं देखना चाहिए।

आज जीडीपी के ईदगिर्द पहले से अधिक बहस हैं। इसका एक परिणाम ‘जीडीपी के परे’ एजेण्डा रहा है। यदि जीडीपी में वृद्धि चाहे वृद्धि संदेहवाद के कारण या इस चिंता के कारण, सुस्त बनी रही तो सरकारों की प्रदर्शन वैधता को भी क्षति पहुंचेगी। राजनेता, लोकसेवक एवं शिक्षाविद—उनमें से निकोलास सरकोजी, जैसिडां अर्डर्न, गसआं डौनेल, जोसफ स्टिग्लिट्ज एवं अमर्त्य सेन—वैकल्पिक मापदंडों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

पोलान्सी राजनैतिक अर्थशास्त्री डेविड यारो के लिए जीडीपी के परे एजेण्डा “अर्थव्यवस्था” के संविधान को एक एकीकृत, बाजार—केन्द्रीत वस्तु के रूप में अस्थिर करने की क्षमता रखते हैं। अगर ऐसा हो तो यह एक स्वागत योग्य घटनाक्रम होगा। हालांकि जीडीपी आर्थिक व्यवस्था के मुख्य लक्ष्य को परिभाषित नहीं करती है। वह लक्ष्य पूंजी का प्रतिस्पर्धी संचय और उसे मार्ग दिखाने वाले लेखांकन सिद्धांत हैं जो राज्य के नहीं अपितु फर्म के स्तर पर हैं। यदि उपरोक्त विश्लेषण सही है, तो जब वृद्धिवाद के आलोचक पूंजी के बारे में संकोची बन पूरी तरह से सिर्फ जीडीपी माप पर ध्यान केन्द्रीत करते हैं, वे गहरे मंतव्य को बाधित कर रहे हैं। ■

सभी पत्राचार गैरेथ डेल को <Gareth.Dale@brunel.ac.uk> पर प्रेषित करें।

> महान रूपांतरण : पूर्वी एशिया का विपणन

जोनाथन डी लंदन, लीडेन विश्वविद्यालय नीदरलैंड द्वारा



कार्ल पोलांसी। श्रेय: कार्ल पोलांसी लेवित

बाजार और बाजार संबंधों का विश्व-स्तरीय विस्तार और गहनता हमारे समय के सबसे परिवर्तनकारी घटनाक्रमों में आते हैं। हम यह प्रतिक्रियाओं को एक सामान्य तरीके, बैडोल नवनिर्मित प्रयोग— बाजारवाद से संबंधित कर सकते हैं। हाल ही की दशकों में वैश्विक स्तर पर पकड़ बना चुकी बाजारीकरण की त्वरित प्रक्रियाएँ गहन रूप से पोलांनियन हैं। वे बाजार विस्तार और रहवास की द्वंद्वत्मकता और विशिष्ट हितों और सहायक लक्ष्यों की पूर्ति करने के इरादे से सामाजिक जीवन को आदेश देने पर आमदा कुलीन राजनैतिक कर्ताओं की सुविचारित राजनीतिक रणनीतियों दोनों को दर्शाती हैं। यह कहने के साथ, जिस तरीके से बाजारवाद प्रकट हुआ है, उसको मिलने

वाले स्थानीय प्रत्युत्तर और कल्याण एवं असमानता पर इसके प्रभाव व्यापक रूप से दुनियाभर और उसके अंतर्गत काफी भिन्न रहे हैं।

वैश्विक रूप से, बाजारीकरण व्यापार और निवेश में वृद्धि, औद्योगिकरण एवं वित्तीयकरण, बड़े पैमाने पर पूंजी संचय और सहयोगी, आय और धन संपत्ति में चाहे असमान वृद्धि; के साथ ही नहीं बल्कि बढ़ती असमानता, व्यापक और व्यवस्थागत आर्थिक असुरक्षा और पारिस्थितिक तबाही के साथ जुड़ा है। इन सभी की अनुमति दी गई है और वे किसी भी कीमत पर संचय के लिए दुनिया को सुरक्षित बनाने के इरादे वाले पूंजीवादी हितों की किस्सों की व्यापक जीत के द्वारा अनुमत और त्वरित किए गए हैं। दुनिया भर में बाजारीकरण का त्वरितकरण “बाजार अनुकूल” सिद्धांतों की आड़ में भ्रष्ट प्रथाओं के प्रसार के साथ-साथ जाता है। इसने तेजी से वैश्विक लेकिन राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य संचय शासनका निर्माण किया है जो धन तो निर्मित करते हैं लेकिन असमानता को भी बढ़ाते हैं। ऐसा वे आर्थिक असुरक्षा को बनाए रख और औसत आय में वृद्धि एवं उपभोग के वृद्धि के बावजूद कष्ट को बनाए रख के करते हैं।

लेकिन क्या यह स्थिति इतनी खराब है? आखिरकार, बाजारीकरण के तहत दुनिया अधिक अमीर हुई है, विशेष रूप से पूर्वी एशिया में, जिसे यहां जापान एवं इंडोनेशिया के मध्य के 20 या कुछ ऐसे देशों के रूप में समझा गया है। पूर्वी एशिया में विपणन और उसकी सहयोगी गतिकी हमारे समय के पोलांन्यी के विश्लेषण में योगदान दे सकती है।

> पूर्वी एशिया में “दोहरी गतिशीलता”

विपणन के गत तीन दशकों के बारे में सबसे व्यापक रूप से उद्धृत आंकड़े वे हैं जो विकासशील देशों, विशेष रूप से पूर्वी एशिया, में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान को उजागर करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार, 1990 और 2016 के मध्य “अत्यधिक गरीबी” में रहने वाली पूर्वी एशिया की आबादी का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक से घटकर 3 प्रतिशत से कम रह गया। हालांकि इन विशिष्ट आंकड़ों में दक्षिण पूर्व एशिया के अपेक्षाकृत निर्धन और धीमी गति से बढ़ते समाज सम्मिलित नहीं हैं और वे संदिग्ध रूप से कम निर्धनता पर और प्रगति के प्रतिनिधित्व पर आधारित है जो हावी बाजार— प्रचारक रुचियों की सेवा करते

हैं। चाहे जैसा भी हो और कितना भी विविध, प्रादेशिक रुझान स्पष्ट हैं। पूर्वी एशिया के उच्च मध्यम और निम्न आय वाले देशों ने वृद्धि और बेहतर जीवन स्तर के साथ-साथ बढ़ती असमानता और कभी-कभी शोषण के चौकानेवाले स्तर को सुगम बनाया है। लेकिन पूर्वी एशिया का विपणन भी पोलान्थी के “दोहरे आंदोलन” के तत्वों को दर्शाता है।

समकालीन विश्व बाजार का एक विशेष पहेलीनुमा पक्ष यह है कि जहां इसके विस्तार को नवउदार विचारों और रुचियों (डेल, 2012) के प्राधान्य द्वारा सुगम बनाया गया, इसका विकास दुनियाभर में मध्यम एवं निम्न आय देशों के पार सामाजिक नीतियों के पैमाने और सारणी में तीव्र वृद्धि के साथ हुआ है। एक प्रति-आंदोलन के बजाय, बाजारीकरण में शामिल निम्न एवं मध्यम आय देशों के मध्य सामाजिक नीतियों का विस्तार वैश्विक बाजार-समाज या सामाजिक व्यवस्था के विस्थापन और संस्थागतकरण को दर्शाता है जो क्रमशः प्रत्येक देश की विशिष्ट सामाजिक संबंधात्मक एवं संस्थागत विशेषताओं से आकारित होता है।

पूर्वी एशिया में, संयुक्त और असमान विकास की पृष्ठभूमि में होने के कारण इन सामाजिक प्रतिक्रियाओं का माप, दायरा, गति एवं स्थानीय जटिलता विशेष रूप से प्रभावशाली रही है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण व्यवस्था का पैमाना और व्यापकता उतनी ही अधिक विस्तारित हुई है जितना कि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी खर्च। कोरिया एवं ताइवान और यहाँ तक कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में सामाजिक नीति विस्तार को चुनावी प्रोत्साहन जो सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने का वादा करने वाले अभिजनों को पुरस्त करता है, के द्वारा तीव्र किया गया है। तुलनात्मक रूप से अमीर सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया में लोकतांत्रिक राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को प्रभावशाली स्तर पर, प्रारंभ किया है, यद्यपि कुछ स्तरीकृत तरीकों से जो बिना वजह निर्धनता को बनाए रखते हैं। चीन और वियतनाम में नाममात्र की पूंजीवादी विरोधी कम्युनिस्ट पार्टियों ने गहन सत्तावादी कार्पोरेट राजनैतिक फ्रेमवर्क को दर्शाने वाले बाजारवादी समाजों की स्थापना की है जिन्होंने तीव्र आर्थिक वृद्धि और सेवाओं का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया है। ऐसा उन्होंने अपनी आबादी का हिस्सा बढ़ाने के लिए किया है चाहे बुनियादी स्तर के परे सेवाओं तक पहुँच के लिए राजनीतिक और आर्थिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कंबोडिया, लाओस और म्यांमार भी विस्तारित सामाजिक नीति समूह का प्रदर्शन करते हैं।

> दोहरे आंदोलन की प्रवृत्ति पर बहस करना

वैश्विक रूप से देखने पर कुछ लोग पूर्वी एशिया के घटनाक्रमों को एक सच्चे डी-कमोडिफाइंग पोलान्थी दोहरे आंदोलन के प्रमाण के रूप में देखते हैं जिसमें पछेती औद्योगिक पूर्व एशियाई समाजों का विस्तृत होते विश्व बाजार के साथ चल रहा एकीकरण घरेलू एवं विश्व बाजार के घुमाव से आबादी की रक्षा करने वाली सरकारी सामाजिक नीतियों की पहल के साथ आता है। इसके साथ ही वह उनके भीतर उर्ध्वगामी गतिशीलता को प्राप्त करने हेतु, प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यक क्षमताओं के विकास का भी समर्थन करता है। सामाजिक नीति के वैश्विक विस्तार को संबोधित करते हुए, हैरिस और स्कली दावा करते हैं कि वैश्विक दक्षिण में कमोडिफिकेशन नवउदारवाद के बहुत पहले आया था

और नवउदारवाद द्वारा बाजारों की भूमिका के विकास एवं विस्तार पर जोर देने के बावजूद इसकी उन्नति ने “राजनैतिक आर्थिक जीवन के डी-कमोडिफिकेशन की तरह स्पष्ट झुकाव” को दुरुह किया है। वास्तव में आईएलओ रिपोर्ट करता है कि 2019 तक विश्व की लगभग आधी आबादी कम से कम एक सामाजिक लाभ से आच्छादित है।

पूर्वी एशिया में सामाजिक नीति के विस्तार के प्रति संशयवादी एक विशिष्ट नवउदार और यहां तक कि फर्जी पोलान्थिन दोहरा आंदोलन, ऐसा जो पूर्व एशियाई लोगों को सार्वभौमिकता और डी-कमोडिफिकेशन के सिद्धांतों से दूर ले जाता है और बाजार संचय को लोकतांत्रिक तंत्रों से बचाने वाले शासन और बाजार नागरिकता के तरीकों की तरफ ले जाता है, को पहचानता है। यह नव उदारवादी दोहरा आंदोलन उस धारणा को दर्शाता है कि कल्याण को बाजार के अंतर्गत और उसके द्वारा सबसे अच्छा प्रोत्साहन एवं निर्धारित किया जाता है। इस हद तक कि सामाजिक नीतियां स्वयं बाजार अर्थव्यवस्था के तर्क को बढ़ावा देती हैं। इस क्षेत्र में बढ़ती समानता और व्यापक वाणिज्यीकरण एवं सेवाओं का स्तरीकरण इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। वास्तव में, इस क्षेत्र में राज्य की सामाजिक नीतियां पूंजी संचय का प्रमुख ठिकाना है। फिर हम पूर्वी एशिया के महान रूपांतरण, जो महत्वपूर्ण लेकिन जीवन स्तर में अत्यधिक असमान सुधार, कुलीन हितों की सेवा करने के लिए निर्मित और पोषित बाजार समाजों के व्यापक रूप से अधीन आबादी, लेकिन सामाजिक नीति के और क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार और बढ़ती आय के साथ जुड़ा है, को क्या समझेंगे।

> सामाजिक व्यवस्था के भीतर संस्थापन

पूर्वी एशिया के रूपांतरण के महत्व को समझने के लिए सामाजिक व्यवस्था के रूप में पूर्वी एशियाई देशों के विश्लेषण की, और उसके साथ, उनके गतिशील सामाजिक संबंधों एवं संस्थागत विशेषताओं के गहन अन्वेषण की आवश्यकता है। सिर्फ कोरिया और ताइवान में ही हमें पोलान्थी द्वारा चित्रित आधारों पर बाजार के वास्तविक पुनः अतःस्थापना के इशारों के संकेत दिखाई देते हैं। चीन और वियतनाम में दोहरा आंदोलन बाजार-लेनिनवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही हुआ है। प्रदेश भर में, बाजारों की तरह सामाजिक नीतियाँ प्रचलित शक्ति संबंधों के भीतर और उनके माध्यम से विकसित हुई हैं। यदि कोई व्यापक प्रवृत्ति है, तो यह है कि पूर्वी एशियाई कुलीन वर्गों ने कमजोर सार्वभौमिक सामाजिक नीतियों की विशेषता वाली सामाजिक व्यवस्था और बाजार नागरिकता के प्रकारों को स्थापित किया है। ये बुनियादी सेवाओं के कमोबेश पर्याप्त धरातल को विस्तृत करते हैं लेकिन पे-एस-यू-गो (जाते हुए भुगतान करो) सिद्धान्त एवं राजनैतिक संपर्कों के कारण इन सेवाओं से परे पहुँच को काफी अनिश्चित बनाते हैं। तब, पूर्वी एशिया में जीवन-स्तर में भारी सुधार, जन उपभोग एवं उपभोक्तावाद और बढ़ती असमानता, निरंतर आर्थिक असुरक्षा एवं पारिस्थितिक तबाही के मध्य विस्तारित होती सामाजिक नीतियाँ वास्तव में एक महान रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। भले ही वे उस तरह का नहीं हो जिसकी पोलान्थी ने कल्पना की हो और जिसकी अन्य अभी भी उम्मीद कर सकते हैं। ■

सभी पत्राचार जोनाथन लंदन को <j.d.london@hum.leidenuniv.nl> पर प्रेषित करें।

> आबादी प्रतिस्थापन का भय

अतिला मेलेघ, कार्ल पोलान्थी केंद्र, कोर्बिनस विश्वविद्यालय, बुडापेस्ट, हंगरी के संस्थापक निदेशक द्वारा

पूर्व यूरोपीय आबादी अपने पुत्र कार्ल पोलान्थी की अंतर्दृष्टि को समझने (पुनः) की प्रक्रिया में हैं। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन लिखने और यह व्याख्या करने के बाद कि बाजार आदर्शवाद क्यों "भौंडी कल्पना" की व्यवस्था के खिलाफ एक सुरक्षात्मक आवरण को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता की तरफ आ जाता है, 1945 में पोलान्थी ने यह तर्क भी दिया कि एक मुक्त बाजार की शुरुआत पूर्व यूरोप में उन्मादी राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त करेगी।

"यदि अंटार्कटिक चार्टर ने वास्तव में वहाँ, जहाँ से वे गायब हो गए हैं, मुक्त बाजारों को पुनर्स्थापित करने का वादा किया तो हम इस तरह ऐसे क्षेत्रों में जहाँ से ये गायब हुए एक उन्मादी राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के लिए द्वार खोल रहे हैं।" (पोलान्थी "सार्वभौमिक पूंजीवाद या श्रेणीय नियोजन")

क्रिस हैन ने अपनी नवीनतम पुस्तक *रिपेटिटिव पोलान्थी* में यह दावा भी किया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के गहरे कारण "वैश्विक नवउदार व्यवस्था" की संस्थाएं हैं। इस संक्षिप्त आलेख में मैं तर्क देता हूँ कि वैश्विक नवउदार युग में जनसांख्यिकी परिवर्तनों ने मानव जाति और यूरोप के भीतर पूर्वी यूरोपीय और (एक परीक्षण की तरह), महत्वपूर्ण रूप से हंगेरियन समाजों में— बाजार के यूटोपिया के खिलाफ किसी तरह की सुरक्षा को देखने के लिए धकेला है। ये समाज पड़ोसी देशों के बाहर के क्षेत्रों से विस्थापित प्रवासियों से लापता या निर्गामी घरेलू आबादी को बदलने में पूंजी की रुचि को अस्वीकार करते हैं।

> वैश्विक स्तर के कारक

1980 के दशक के उत्तरार्ध में प्रारंभ होने वाले नवउदार युग ने वैश्विक जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का देखा है जो पहले के काल की तुलना में प्रवासन को अधिक विवादास्पद मुद्दा बना सकते हैं।

- वैश्वीकरण की अवधि के दौरान, आबादी की तुलना में प्रवासन अधिक तेजी से बढ़ रहा है जबकि प्रजनन क्षमता में लगातार गिरावट आ रही है जिससे आबादी के प्रौढ़ होने की गंभीर समस्या

बढ़ रही है। इस बीच मृत्यु दर में सुधार पिछली अवधि की तुलना में धीमा हो गया है।

- प्रवासन में वृद्धि के पीछे पूंजी की बढ़ी हुई गतिशीलता की मुख्य भूमिका है जिसने वैश्विक स्तर पर समाजों के बड़े क्षेत्रों असम्बद्ध और उखाड़ा है। नतीजतन आर्थिक पुनर्गठन और स्थाई नौकरियों ने रोजमर्रा के काम और व्यापारिक जीवन को बहुत कम स्थिर और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है।

- बढ़ते कल्याण लाभों और श्रम प्रतिस्पर्धा के कारण प्रवासन पर बहस (नियंत्रण बनाम प्रवासन को प्रोत्साहित करने के ऐतिहासिक विरासत में मिले असंबद्ध पैटर्न पर आधारित) अधिक तीव्र हो गई है। ये निम्न परस्पर संबंधित कार्यों से जुड़ी हैं: प्रजनन क्षमता में गिरावट से वैश्विक आबादी की निरंतर बढ़ती प्रौढ़ता; सक्रिय आयु समूहों में श्रमबल भागीदारी दर में अवलोकनीय गिरावट; मजदूरी का गौण अभिसरण जिसमें पश्चिम के विशेषाधिकार प्राप्त समूह ने कम या कोई वेतन वृद्धि का अनुभव किया, और जैसा बोरास्ज ने 2016 में एक लेख "पुनर्वितरण में वैश्विक असमानता" में समझाया, 1990 के दशक के मध्य के बाद से पुनर्वितरण स्तरों का समग्र ठहराव।

> यूरोपीय स्तर के कारक

वैश्विक औसत में तुलना में यूरोप की ऐतिहासिक धीमी प्रजननता और महाद्वीप पर मृत्यु दर के लाभों को खोते हुए निरंतर औसत से अधिक प्रौढ़ता, जनसांख्यिकी कारकों की बढ़ती महत्ता की तरफ इशारा करती है। ये कारक बताते हैं कि समूचा यूरोप क्यों प्रवासन के बारे में इतना चिंतित हो गया है। यह नवउदार युग में विरोधाभासी प्रवासन बनाम कल्याण प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। पूंजी की गतिशीलता काफी उच्च रही है (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शुद्ध प्रवाह वैश्विक स्तर से ऊपर रहा है)। यूरोप की जटिल रूप से सन्निहित समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को इस गतिशीलता के लिए विघटित किया गया जिसके कारण बड़े पैमाने पर नौकरियों की हानि और एक खुले लेकिन असमान रूप से विकसित स्थान में विशाल जनसंख्या गतिशीलता हुई। हम यह भी देखते हैं कि एक प्रति व्यक्ति आर्थिक कल्याण के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्र के

रूप में यूरोप उच्च और वैश्विक से ऊपर प्रवासन के स्तरों के बावजूद वैश्विक महत्व में गिरावट को महसूस कर रहा है।

> क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर के कारक

यदि हम दीर्घकालिक रोजगार की तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि अब तक सर्वाधिक वैश्विक स्तर से कहीं ऊंचे—1980 के दशक में पूर्वी यूरोपीय देशों में श्रम बल भागीदारी दर 2010 के दशक में पुनः चढ़ने से पहले 1990 और 2000 के दशकों में यूरोपीय और यहां की वैश्विक स्तर के कहीं नीचे गिर गई थी। अतः दो खोए हुए दशक थे जिनका इन समाजों पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

शॉक अर्थशास्त्र के इस दौर का मतलब व्यापक व्यवस्था और उथल-पुथल था। जैसा हैन बहस करते हैं, इसका अर्थ था कि वृहद स्तर के अतिवादी बदलाव “बाजार समाज” में परिवर्तन हो रहे लोगों के प्रतिमानों एवं दैनिक व्यवहारों के खिलाफ गए। आव्रजन के संबंध में, प्रमुख विशेषता यह है कि हंगरी सहित सम्पूर्ण क्षेत्र, लोगों के बड़े प्रवाह को पश्चिम भेजता है लेकिन वह सिर्फ पड़ोसी क्षेत्रों से ही प्रवासियों को प्राप्त करता है; आगे के लिंग दुर्लभ और अपेक्षात कमजोर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2015 में पूर्वी यूरोप के छोटे राज्यों में जन्में 25 मिलियन से अधिक लोग अपने जन्म के देश में नहीं रहते थे; इस बीच में प्रवासियों की कुल संख्या, मुख्य रूप से आसपास के क्षेत्रों से, सिर्फ 10 मिलियन से अधिक थी जो व्यापक स्तर पर आबादी की हानि का संकेत देते हैं।

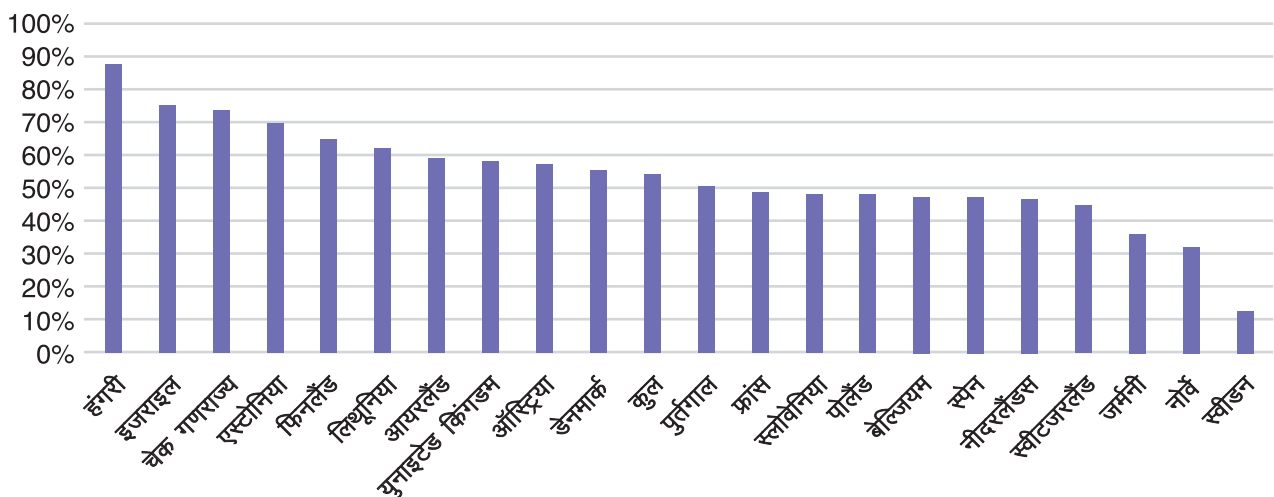
पश्चिमी देशों के साथ असमान विनिमय (पूंजी अंदर आती है और श्रम बाहर जाता है), श्रम और कौशल की हानि, श्रम मांग और श्रम आपूर्ति में बढ़ता बेमेल और सामाजिक और कर भुगतान की हानि, विशेष रूप से प्रौढ़ता की प्रक्रिया के भीतर—राष्ट्र—राज्य एवं उसके सामाजिक कल्याण प्रणाली के प्टिकोण से गंभीर है। यह

बहस करना संभव हो सकता है कि— स्थिर जनसंख्या वृद्धि की वैश्विक प्रवृत्ति और कुछ हद तक यूरोपीय—के खिलाफ एक खतरा है कि पूर्व यूरोप के कुछ देश उनके पहले ही कटौती किए हुए सामाजिक कल्याण व्यवस्था में भारी तनाव के बिना जनसांख्यिकी प्टिकोण से कार्य करने में असमर्थ होंगे। यह व्याख्या कर सकता है कि कुछ पूर्वी यूरोपीय आबादी, आबादी विनिमय के डर के लिए इतनी खुली क्यों हैं।

हम बहस कर सकते हैं कि व्यवसाय और पूंजी की रुचि स्पष्ट तौर पर “प्रवासी श्रम के काल्पनिक आदान-प्रदान” में है। एक उदारवादी ढांचे में वे श्रम को बाहर भेजने और प्रेषक क्षेत्रों को समान रूप से अमूर्त श्रम के आयात का अवसर पेश कर प्रसन्न होते हैं। यह स्थानीय समुदाय और कुछ राष्ट्रवादी सरकारों द्वारा जनसांख्यिकीय नाजुकता के मध्य एक विनाशकारी विकल्प होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। विरोधाभास के रूप में और कुछ मायनों में दुखद रूप से यह घबराहट विशेष तौर पर तब प्रभावी होती है जब मुद्दा गत 30 वर्षों से नवउदारवाद के तनाव और युद्ध द्वारा उपजे हाल के शरणार्थी संकट का हो। लेकिन इन तनावों और विरोधाभासों का कोई भी राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी उत्तर नहीं हो सकता है। केवल एक वैश्विक दोहरा आंदोलन ऐसा उत्तर तैयार कर सकता है जो राष्ट्रीय या स्थानीय जनसांख्यिकी निकाय के यांत्रिक सत्तावादी बचाव के बजाय वर्तमान संकट से निकलने का एक मार्ग दिखा सके। नवउदार व्यवस्था से बाहर निकलना शायद एकमात्र तरीका हो सकता है जो एक साथ विश्व भर के प्रवासियों और गैर प्रवासियों की गरिमा का आश्वासन दे सके। ■

सभी पत्राचार अतिल्ला मेलिंग को <melegh@demografi.a.hu> पर प्रेषित करें।

यूरोप के बाहर के निर्धन देशों से थोड़े या बिल्कुल नहीं प्रवासियों को अनुमति दें,
यूरोपीय सामाजिक सर्वेक्षण 2014 (तथाकथित शरणार्थी संकट के पूर्व)



स्रोत : यूरोपीयन सोशल सर्वे (ई.एस.एस.), 2014/2015 राउण्ड, https://www.europeansocialsurvey.org/download.html?file=ESS7e02_2&y=2014, अक्टूबर 15, 2019 को लिया गया।

> लोकलुभावनवाद की तरफ मार्ग

किस हैन, मेक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जर्मनी द्वारा



2015 में केलेती रेल स्टेशन, बुडापेस्ट, हंगरी में प्रवासी।
श्रेय: क्रिस हैन

कार्ल पोलान्थी के द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की पुच्छ, लंदन में मार्च 1944 में प्रकाशित फ्रेडरिख हयेक की द रोड टू सर्फडम है। दोनों में किसी को भी पेशेवर समाजशास्त्र या समाज विज्ञान के कृत्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ये विद्वानों द्वारा लोकप्रिय पुस्तकें हैं जिनका लक्ष्य व्यापक दर्शकों तक पहुँचना है। लेकिन जहां हयेक की पुस्तक ने अपना लक्ष्य बहुत तेजी से हासिल किया (अमरीकी पत्रिका रीडर्स डाइजेस्ट में प्रकाशित एक संक्षिप्त विवरण के लिए आंशिक धन्यवाद), पोलान्थी की थोड़ी अधिक लंबी पुस्तक ने केवल मामूली बिक्री का आनंद लिया। यद्यपि पोलान्थी और हयेक दोनों ही आस्ट्रियाई अर्थशास्त्र में जुड़े हुए हैं, वे शैली और सार दोनों में बहुत भिन्न हैं। पोलान्थी ब्रिटिश आर्थिक इतिहास और औपनिवेशिक नृवंशविज्ञान के लिए विस्तृत विवरण में घुसकर लोकतांत्रिक समजावाद के लिए तर्कों के साथ समाप्त करते हैं।

हयेक की कृति काफी अमूर्त और तीखी है। वे पोलांन्यी द्वारा समर्थित उदारवाद के आर्थिक सिद्धांतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ आर्थिक दक्षता की कुंजी के रूप में फासीवाद की तबाही के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हयेक के लिये, समाजवादी नियोजन अधिनायकवाद की ओर ले जाता है। वे न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप के मुक्त बाजारों की सिफारिश करते हैं। यह लेख 1944 के प्रकाशनों से पूर्व की जटिल बौद्धिक इतिहास को नहीं अपितु इन विपरीत आर्थिक दर्शन की अनुगूँज की प्रासंगिकता और 75 वर्ष पश्चात्, आज के विश्व-समाज की स्थिति की खोज करता है।

> एम्बेडेड (सन्निहित) उदारवाद का उदय और पतन

युद्ध पश्चात् के पहले दशकों को आमतौर पर एक ऐसा युग माना जाता है जहां अर्थव्यवस्था समाज में “पुनः एम्बेड” होती है। (द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन का परिचित रूपक का उपयोग करके)। पोलांन्यी के “दोहरे आंदोलन” के तनाव (एक तरफ बाजार के सिद्धांत का भेदन और दूसरी तरफ समाज की आत्म संरक्षण) उच्च रोजगार को बनाये रखने और कल्याण राज्यों को संगठित करने के लिए कीन्स के आर्थिक प्रबंधन के सिद्धांतों द्वारा कम किये जाते हैं। समाजवादी कार्ल पोलांन्यी इन समझौतों से प्रभावित नहीं थे, स्कैंडिनेविया के मजबूत कल्याणकारी राज्यों से भी नहीं। फिर भी, इस काल की मिश्रित अर्थव्यवस्था और ब्रेटन वुड्स पर तय किये गये वित्तीय प्रणाली ने उदार लोकतंत्रों को इस पीढ़ी में समृद्ध होने के लिए सक्षम किया।

ये घटनाक्रम 1970 के दशक में हाइड्रोकार्बन राजनीति और ब्रेटन वुड्स के ध्वंस द्वारा कमतर किये गये। 1980 के दशक तक, राष्ट्रपति रीगन और प्रधानमंत्री थैचर (हायेक को उनका गुरु कह कर) एम्बेडेड उदारवाद के व्यावहारिक संतुलन पर हमला कर रहे थे और इनकी बजाय मुक्त बाजार के गुणों का ढिंढोरा पीट रहे थे। सोवियत संघ के पतन के बाद नवउदारवाद सिद्धांतों का वैश्विक स्तर पर प्रसार किया जा रहा था। केन्द्रीय नियोजन के खत्म होने के साथ, अतिवादी निजीकरण और बाजारीकरण ने अत्यधिक विस्थापन का नेतृत्व किया। अधिकांश समाजवाद-पश्च के पूर्वी यूरोपीय राज्यों को अंततः यूरोपीय संघ में भर्ती किया गया। पूर्व के नये अभिजन पश्चिम के पुराने अभिजनों के साथ जुड़ गये और उन्होंने मास्ट्रिच संधि के सामाजिक अध्याय को गुमनामी में भेज दिया। यूरो के सृजन ने सुनिश्चित किया कि, बाजार के सिद्धांत के हावी होने से जन्मी पूंजी और श्रम की पहले से अधिक गतिशीलता के प्रभाव के रूप में, ‘सामाजिक यूरोप’ के पहले के आदर्शों को दरकिनार कर दिया गया। 2007 में प्रारम्भ हुआ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के मितव्ययिता प्रत्युत्तरों ने एक बार फिर तेजी से डिसएम्बेडेड प्रतीत होने वाले पूंजीवाद के विरोधाभासों को प्रदर्शित किया।

> संस्थागत बाजार और लोकलुभावन राजनीति

चाहे वह बचत करने का या उपभोग करने का, उच्च मजदूरी की तलाश में प्रवास करना या अपनी किस्मत (हेयत) में जो मिला है उसे स्वीकार करने का निर्णय हो, आर्थिक जीवन ऐसे संदर्भों में चलता है जो सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत रूप से निर्मित होते हैं। डिसएम्बेडिंग के रूपक की बहुत शाब्दिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है: हमें, जिसे पोलांन्यी ने ‘स्थापित प्रक्रिया’ कहा

है, को जांचने की आवश्यकता है। नजदीकी निरीक्षण से पता चलता है कि मुक्त बाजारों का शासन गंभीर रूप से सम्पत्ति अधिकारों की रक्षा और सामान्य रूप से पूंजीपतियों के हितों को लागू करने हेतु मजबूत राज्य पर निर्भर है। यदि पोलांन्यी आज लिख रहे होते तो वे शायद उन तरीकों पर ध्यान देते जिनमें सबसे मजबूत राज्यों की शक्तियां भी ट्रांसनेशनल निगमों द्वारा समझदारी से कराधान से बच कर एवं सिर्फ अपने शेरधारकों के प्रति जवाबदेह हो कर, पलट दी गई है। वे उन तरीकों से अंचभित होंगे जहां नव-पितृसत्तात्मक शासन, उल्लेखनीय रूप से उनके गृहदेश हंगरी में, संस्थाओं (जैसे यूरोपीय संघ के तंत्र) में अपनी आबादी के हितों की सेवा के लिए व्यावहारिक योजना के लिए नहीं बल्कि एक अर्ध-एकाधिकारवादी शासन दल के भीतर ग्राहकीय निर्भरता के लिंक को पक्का करने के लिए हेरफेर करते हैं।

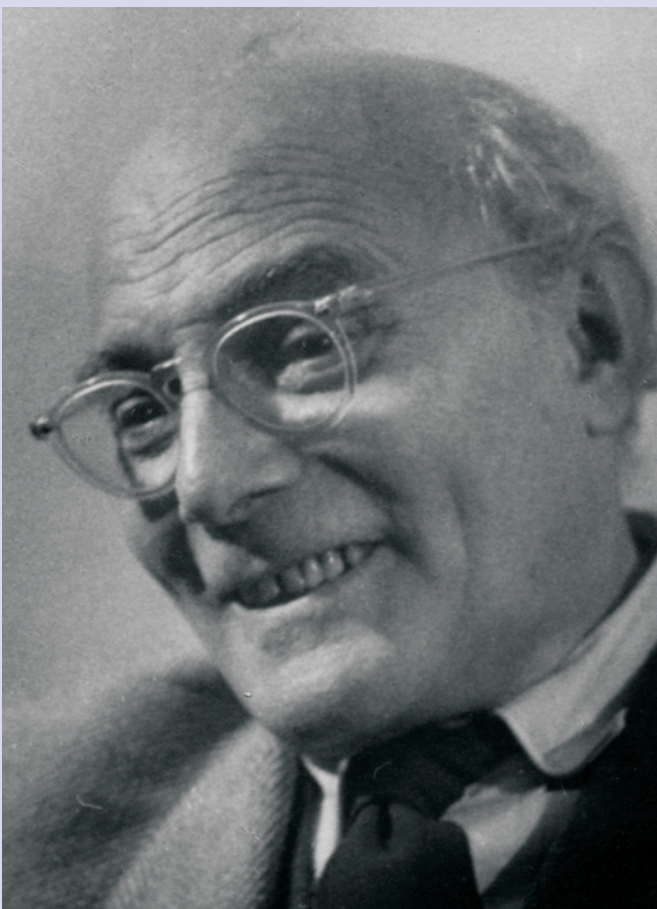
अर्थव्यवस्था का नवीन संस्थाकरण दुनिया भर में लोकलुभावन राजनीति के खतरनाक उभार के साथ आया है। हंगरी में ओरबान या अमरीका में ट्रम्प जैसे नेता पूंजवाद और लोकतंत्र की बुनियादी संगतता पर सवाल कर रहे हैं। इस संयोजन में कार्ल पोलांन्यी के दोहरे आंदोलन के तनावों का विश्लेषण भविष्यदर्शी है। जब हंगरी जैसा समाज, जो 1960 के दशक के मध्य से “एम्बेडेड समाजवाद” में काफी सफल प्रयोगों का अनुशीलन कर रहा था, अचानक वैश्विक अबंध नीति के हवाओं के संपर्क में आता है तो यह नये वैश्विक बाजार में संकट में दिखाई होते मूल्यों को पुनः प्रभावकारी बना कर अपना बचाव करते हुए जवाब देता है। व्यवहार में, इसका अर्थ जातीय-राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर नये वर्गीय-विभाजनों को छिपाना है। जहां रोमा और यहूदी देश के अंदर सुपरिचित बलि का बकरा थे, ब्रुसल्स (नव उदार इ.यू.की सीट) ने मांस्को (केन्द्रीय नियोजन की व्यवस्था की पुरानी सीट) को प्राथमिक बाह्य शत्रु में प्रतिस्थापित कर दिया है। विस्तृत विवरण भिन्न हो सकते हैं लेकिन लोकलुभावनवाद सांठ-गांठ ऐसी है जिसे पोलांन्यी, यूरोपीय फासीवाद की जड़ों के समान होने के कारण पहचान लेते हैं।

जहां *द रोड टू सर्वडम* के समाजवाद विरोधी अबंध नीति जाती है, *द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन* उसका कड़ा विश्लेषण है। दोनों पुस्तकें कई बार पुनः मुद्रित हो चुकी हैं और इनका व्यापक अनुवाद हुआ है लेकिन पोलांन्यी के संदेश को कभी भी *रीडर्स डाइजेस्ट* प्रारूप में संकुचित नहीं किया गया है। हयेक की बिक्री ने हमेशा पोलांन्यी की बिक्री को पीछे छोड़ा है और ऐसा करना जारी है। इन सबसे उपर, एंग्लो सैक्सन देशों में, शीत युद्ध के अंत के तीस वर्ष पश्चात्, समाजवाद को शैतान बनाना एक आदत है जिसे छोड़ना मुश्किल है। कार्ल पोलांन्यी मुक्त बाजारों की सहजता व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी है की सरल धारणा का एक विशद विकल्प की पेशकश करते हैं। हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हायेक की विचारधारा के वर्तमान संकट को कीन्स के उदारवाद के और पुनरुत्थान द्वारा हल किया जा सकता है, या क्या यह वास्तव में पूंजीवाद के लिए “खेल समाप्ति” है। आशावादी पोलांन्यी परवर्ती की उम्मीद करेंगे। ■

सभी पत्राचार क्रिस हैन को <hann@eth.mpg.de> पर प्रेषित करें।

> कार्ल पोलान्थी की चिरस्थायी विरासत

एंड्रयू नोवी, विएना यूनिवर्सिटी ऑफ़ इकोनोमिक्स एंड बिज़नेस, (डबल्यू यू) ऑस्ट्रिया



1964 में कार्ल पोलान्थी।
श्रेय: कार्ल पोलान्थी लेविट

उपयोग किया, जबकि पोलान्थी ने सामान्यतया बाजार आधारित समाज के अस्तित्व पर सवाल उठाए। पोलान्थी मानते थे कि बाजार समाजों में सामाजिक व्यवहार्यता में कमी इनमें संचालन में आजादी के कारण है — और इससे भी बुरी स्थिति है यहाँ अर्थव्यवस्था के हितों और प्रतीकों को राजनैतिक हितों और सामाजिक सरोकारों पर मिली तरजीह।

> पोलान्थी का विशेष अध्ययन

कार्ल पोलान्थी सहकारिता आन्दोलन के बड़े समर्थक थे और आन्दोलन के शुरुआती प्रणेता रोबर्ट ओवेन के विशेष प्रशंसक थे। वैश्वीकरण विरोधी आन्दोलन, सामाजिक अर्थव्यवस्था और एकजुट अर्थव्यवस्था, इस सभी समकालीन जमीनी आंदोलनों का उद्देश्य आम नागरिकों, किसानों और मजदूरों के व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन को बेहतर करके उन्हें सशक्त करना था। उन्होंने स्व-प्रबंधन और शासन में भागीदारी के प्रयोग किए और वे अक्सर लोगों और समुदायों की अपनी जिंदगी को ठीक रखने की क्षमता में दृढ़ विश्वास से प्रेरणा पाते थे। उनका विचार था कि अर्थव्यवस्था और समाज का तालमेल बेहतर हो। यह सम्बन्ध भौतिकतावादी जरूरतों और इच्छाओं से अधिक सहकारिता के मूल्यों पर आधारित हो। इसलिए उन्होंने सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्रीकरण को प्रोत्साहित किया, जिसका मूल उद्देश्य था लोकतंत्र के राजनैतिक दायरे से इतर फैलाव और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना। उनके लिए वित्त पोषण, उत्पादन और कल्याणकारी गतिविधियाँ इतनी महत्वपूर्ण थीं कि इन्हें निर्णय लेने की सामूहिक प्रक्रिया, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और सह-प्रबंधन से अलग नहीं किया जा सके। इनमें से कई सामाजिक आन्दोलनों, हाल ही में हुए सामुदायिक अधिकार हस्तांतरण के आन्दोलन सहित, ने जमीनी सामाजिक नवाचारों को भी प्रोत्साहित किया। लेकिन ये अक्सर स्थानीयता के जाल में फंसकर शिकार हो गए और अपने कार्यस्थल अथवा आस-पड़ोस से दूर संस्थानिक तथा संरचनात्मक बदलाव लाने में विफल रहे।

इससे कार्ल पोलान्थी के सिद्धांत के लगभग अनछुए लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू के बारे में पता चलता है, वह है उनका

वर्ष 1964 में मौत के बाद कार्ल पोलान्थी की पहचान मुख्यतया मानव शास्त्र तक ही थी, जबकि वह अर्थशास्त्र को 'आजीविका के प्रबंधन' के सही सन्दर्भ में समझने के कट्टर समर्थक थे। एक समाज विज्ञानी के रूप में उनकी खोज 1970 के दशक से हुई। अर्थशास्त्र में, डगलस नार्थ, जिन्हें आर्थिक विकास में संस्थानों के महत्व पर जोर देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, के शोध के माध्यम से पोलान्थी को ख्याति मिली। हालाँकि, पोलान्थी से इतर नार्थ ने बाजार, संपत्तियों और समझौतों पर फोकस किया। समाजशास्त्र में मार्क ग्रानोवेट्टर ने पोलान्थी के सहकार के सिद्धान्त को प्रसिद्धि दिलाई और इसका बाजार के बोलबाले वाले समाज में बाजार के संचालन को समझने के लिए

निर्विवाद स्थानिक विश्लेषण। पोलान्स्की की अकसर उद्धृत की जाने वाली स्व-नियंत्रित बाजार की आलोचना सभी प्रकार के बाज़ार को खारिज नहीं करती। यह उस 'बड़े बाज़ार' के उभार की आलोचना है, जो पूरी तरह सुसज्जित है और जहाँ सब कुछ – वो वस्तुएं भी, जो बेचने के लिए नहीं बनी हैं – को खरीदा जा सकता है। 1930 के दशक तक जिस मुख्य उत्पाद ने 'एक बड़े बाज़ार' को बचाए रखा वह था शुद्ध सोना। इसके कारण पूरी दुनिया में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को तुलना और फिर व्यापार के योग्य बना दिया। पोलान्स्की के नजरिये से आर्थिक उदारवाद का यह संसार एक भ्रम है। यहाँ तक कि 20वीं सदी की समाप्ति काल में 'वैश्वीकरण' शब्द के चलन से भी पहले पोलान्स्की ने 'वैश्विक पूँजीवाद' और मशीन के युग में टेक्नोलॉजी के अनियंत्रित विस्तार की कड़ी आलोचना की थी।

> नव उदारवाद और विकल्प की आवश्यकता

वर्ष 2000 में डॉटकॉम के बुलबुले के फूट जाने और 2008-09 के आर्थिक संकट के बाद ही उनकी 'मुक्त बाजारवादी अर्थव्यवस्था' के भयावह सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की आलोचना को गंभीरता से लिया गया और इस बात पर विचार किया गया कि जीवन को व्यापार की वस्तु बना देने पर समकालीन समाज क्या प्रतिक्रिया देंगे। योजनाबद्ध नव उदारवाद और जीवन के सभी पहलुओं का आर्थिकीकरण होने के चार दशक बाद यह वृहद् और गहन अनुसंधान का विषय बना है। समाजशास्त्र में माइकल बुरावे ने प्रकृति, ज्ञान और सूचनाओं के बाजारीकरण के वर्तमान में चल रहे अभियान को समझने के लिए पोलान्स्की के सिद्धांत का उपयोग किया है। मजदूरों में लिंग भेद से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के बाजारीकरण तक नव उदारवाद के दैनिक जीवन पर पड़ रहे प्रभावों को वित्तीय बाजारों के बढ़ते दखल ने और गहरा दिया है।

नव उदारवाद के खिलाफ दुनिया भर में अकादमिक और राजनैतिक संघर्ष के कारण 'बाजार के तर्क' से चलने वाली दुनिया को समझने और बदलने वालों ने पोलान्स्की को प्रेरणास्पद व्यक्ति मान लिया है। कई विख्यात शोधकर्ताओं ने नव उदारवाद और वैश्वीकरण की आलोचना की है। डानी रोड्रिक ने इसे 'हाइपर ग्लोबलाइजेशन' और कारी पोलान्स्की लेविट ने 'ग्रेट फाइनैसियलाइजेशन' कहा। वोल्फगैंग स्ट्रीक इस पर जोर देते हैं कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से लोकतंत्र, कल्याणकारी शासन और राष्ट्रीय स्वायत्तता को खतरा है। इसके विकल्प के रूप में आर्थिक एकीकरण, राष्ट्रीय नीति निर्धारण और लोकतंत्र को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास कांफ्रेंस ने हाल ही में एक अन्य 'नए वैश्विक समझौते' (न्यू ग्लोबल डील) के लिए अपने आग्रह में इन मुद्दों को जगह दी है। इस समझौते में मितव्ययता, वित्तीय बाजारों के पुनर्गठन की आवश्यकता के साथ-साथ आर्थिक

शक्तियों, विशेषकर वित्तीय बाजार तथा डिजिटल प्लेटफार्म की ताकत, पर अंकुश लगाने का जिफ्र है। दकियानूसी पाखंडी अर्थशास्त्रियों की आर्थिक समाजशास्त्र को यह बड़ी देन हो सकती है, क्योंकि ग्रानोवेट्टर के शोध के बाद से ही इसे नजरअंदाज किया गया। दूसरी तरफ, संस्था, सत्ता, सन्दर्भ और व्यवस्था पर शोध का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण 'आजीविका के प्रबंधन' के रूप में पोलान्स्की की अर्थव्यवस्था की परिभाषा को बेहतर रूप दे सकता है। इससे अर्थव्यवस्था की स्थान-आधारित समझ बढ़ेगी, जिसके सिद्धांत विशेष संस्थानों में तैयार किए गए और जिससे आर्थिक समानता के बजाय पूँजीवाद को बढ़ावा मिलेगा।

मेरी समझ में, 'हाइपर ग्लोबलाइजेशन' का विकल्प अधिक संदर्भित और संवेदनशील अर्थव्यवस्था के साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने में है। पोलान्स्की ने क्षेत्रीय राष्ट्रवादी योजना के निर्माण पर जोर दिया है। भूगोलवेत्ता बताते हैं कि आजीविका निश्चित रूप से आस-पड़ोस, शहरों और क्षेत्रों पर निर्भर करती है। और राजनैतिक अर्थव्यवस्था इस बात पर जोर देती है कि लोकतान्त्रिक उत्तरदेयता और सामाजिक सुरक्षा अभी भी राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं। लोकतान्त्रिक, टिकाऊ और एकजुट शासन के लिए कई स्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

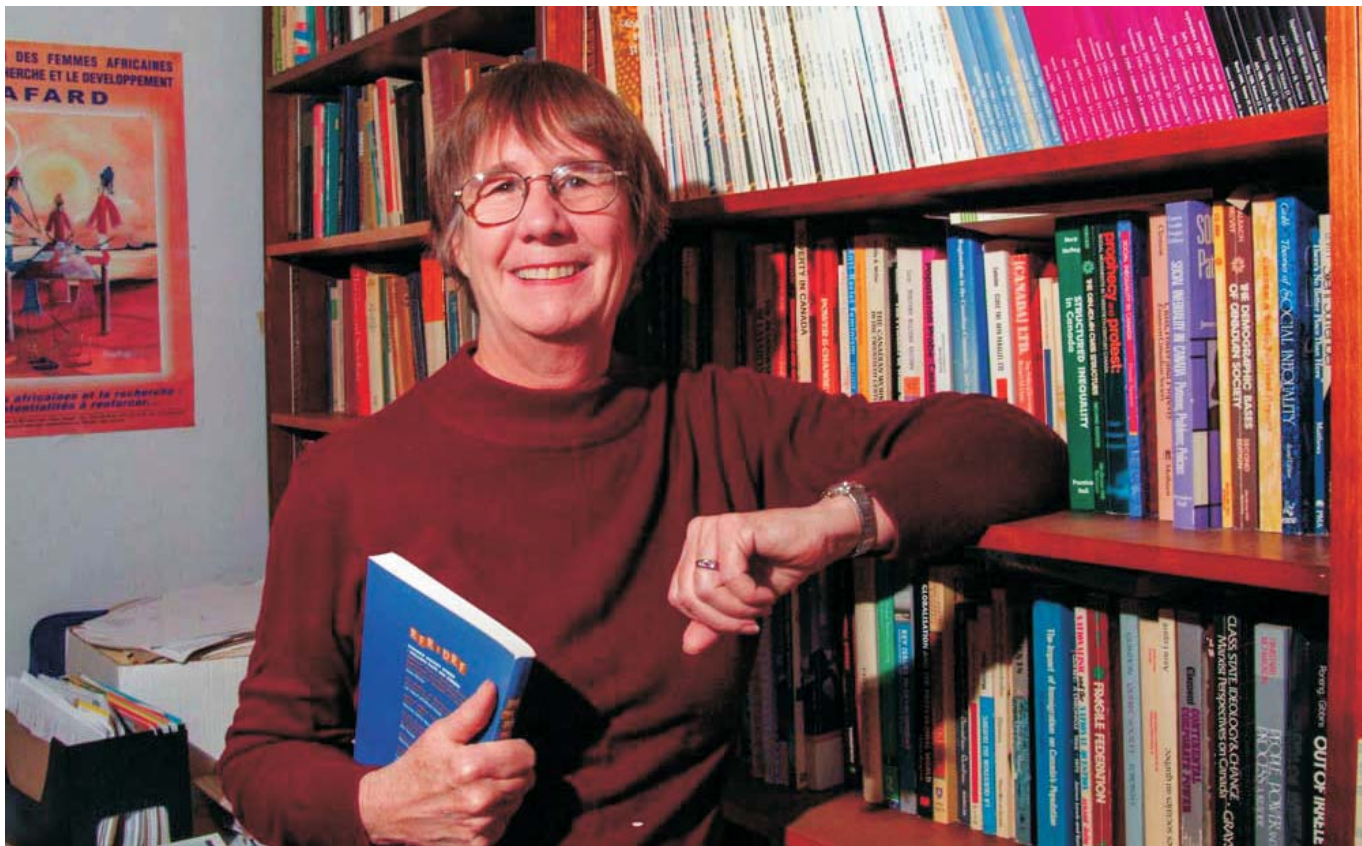
अन्त में, एकदम आधारभूत स्तर पर पोलान्स्की की विरासत उनकी वह प्रेरणा है, जो वर्तमान बाजार आधारित समाज – जिसमें बाजार, संपत्ति और प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है – को सभ्यता में बदलाव का विकल्प देती है। पोलान्स्की के अनुसार, आर्थिक प्रगति के कारक, आर्थिक तरक्की तथा आर्थिक-सांस्कृतिक सुरक्षा पूँजीवादी बाजार समाज के साथी हैं। जो सभ्यताएं केवल आर्थिक सुधार पर फोकस करती हैं, वे नष्ट होती हैं, जैसे कि 1930 के दशक में उदारवादी सभ्यता समाप्त हो गई थी। भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण से बढ़ रहे पर्यावरणीय संकट भी एक नए आपातकाल की आहट हैं। जैविक और भौतिक सीमाएं ही सामाजिक सीमाएं बनती हैं, जो संसाधन-संपन्न अमीरों को वंचितों से अलग करती हैं। इस अंतर को वैश्विक उत्तर (ग्लोबल नार्थ) और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के बीच का फर्क भी कहा जाता है। जैसे-जैसे असमानता और अपवर्जन बढ़ता है, अधिनायकवाद तथा सांस्कृतिक विरोध की राजनीति भी बढ़ती है। लेकिन असमानता और अपवर्जन के खिलाफ संघर्ष उन आन्दोलनों को सशक्त करता है, जो आपसी सद्भाव, सुरक्षा और सह-अस्तित्व के वातावरण के निर्माण के भाव को पुनर्स्थापित करें। पोलान्स्की के अनुसार, व्यक्तिगत आजादी और उत्तरदायित्व सभी तरह की आशंकाओं से रहित अच्छे भविष्य के रास्ते खोलते हैं। ■

सभी पत्राचार एंड्रयू नोबी को <Andreas.Novy@wu.ac.at> पर प्रेषित करें।

> एन बार्देन डेनिस :

सराहना में

लिंडा क्रिस्चियनसेन-रफमैन, सेंट मैरी विश्वविद्यालय; एंजेला माइल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो;
और मर्लिन पोर्टर, मेमोरियल यूनिवर्सिटी, कनाडा द्वारा



एन बार्देन डेनिस। श्रेय: यू.एस.सी कनाडा।

फरवरी 5, 2019 को अचानक दिल का दौरा पड़ने से एन बार्देन डेनिस का निधन हो गया। वह केवल 73 वर्ष की थीं। एन ने अपने जीवन का अधिकतर समय समाजशास्त्र के लिए, विभिन्न विषयों की छात्रवृत्ति के लिए, समाज में समानता के लिए, और मतभेदों के इतर आदरपूर्वक सामाजिक रिश्तों के लिए समर्पित कर दिया था। वह कई साथियों, विद्यार्थियों, दोस्तों, और गुरुजनों को दुखी करके चली गईं। ये सब लोग उनके शांत और ख्याल रखने वाले स्वभाव के साथ-साथ उनकी सहयोगात्मक, विश्लेषक, और कर्मशील होने की योग्यताओं, ज्ञान, और भरोसे को हमेशा याद करेंगे।

हाल ही में एन ने अपने माँ के परिवार को सम्मान देने के लिए मध्य नाम बर्देन का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उन्होंने अपनी दादी और माँ के बड़े तथा पितृसत्तात्मक फ्रेंच कनाडाई परिवारों में बीते जीवन के अनुभवों से आई बुद्धिमानी और व्यवहारिक ज्ञान वाली सलाह को तरजीह दी। इन दोनों औरतों से एन ने मदद की दुनिया में एक औरत के अपनी आजादी के लिए संघर्ष में शिक्षा और रोजगार की महत्ता की सीख ली। यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे इन व्यक्तिगत और सामाजिक ताकत से जुड़े मुद्दों ने एन को उनकी निजी और सामाजिक नेतृत्व की भूमिकाओं में ताकत तथा विश्वास दिया। इनसे उन्हें एक महिला अधिकारवादी बनने और फिर जीवन भर उस भूमिका में बने रहने में मदद

मिली। हालांकि यह लेख एन की सार्वजनिक पहचान और अकादमिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप योगदान पर फोकस करता है, उन्होंने सामाजिक रूप से व्यस्त तथा दूसरों का ख्याल रखने वाली जिन्दगी जी और हमेशा एक स्वतंत्र महिला के रूप में रही।

एन का जाना उन कई बड़े संस्थानों के लिए संकट जैसा है, जिनको उन्होंने समर्थन दिया, उनको तैयार किया और अपने काम के माध्यम से ताकत दी। उन्होंने असाधारण कैनेडियन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एसोसिएशन (सीएसएए), अब सीएसए, और इसके फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी रिसर्च सेंटर; इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन (आईएसए) और इसकी दो शोध समितियों आरसी 05 (जिसे उस समय एथनिक, रैस एंड माइनोंरिटी कमिटी कहा जाता था और वर्तमान में रैसिस्म, नेशनलिज्म इनडीजीनेनिटी एंड एथनिसिटी कमिटी कहा जाता है) तथा आरसी 32 (तब वीमेन इन सोसाइटी और वर्तमान में जेंडर एंड सोसाइटी); और कैनेडियन रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन (सीआरआईएडब्लू-आईसीआरआईएफ) में बेहतरीन प्रशासनिक और अकादमिक भूमिका, विशेषकर हाल के समय में, निभाई।

इन सभी संगठनों और समितियों में, और उनकी दो भाषाओं वाली

>>

यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में, एन्न ने बेझिझक नेतृत्वकारी भूमिकाओं (अधिकतर बार अध्यक्ष) में और कई बार संगठन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक, अकादमिक तथा व्यवहारिक प्रासंगिकता के अनुरूप कम महत्त्व वाले पदों पर काम किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, खुलेपन, समावेशन आदि मूल सिद्धांतों के संरक्षण और पोषण के लिए काम किया। इससे भी अधिक, उन्होंने अनेक पुस्तकों, जर्नल, विशेष संस्करण, जमीनी तथ्य रिपोर्ट और न्यूजलेटर के प्रकाशन में योगदान देकर लेखक और संपादक के रूप में अपने कौशल का इस्तेमाल किया। वह लम्बे समय तक कनाडा 'ज एंड टू स्कोलरली पब्लिकेशंस तथा अन्य शोध पत्रिकाओं के बोर्ड में लम्बे समय तक सलाहकार के रूप में रहीं। कनाडा तथा अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र और महिलावादी शोध संबंधों को उनके महिलावादी नेतृत्व और प्रशासनिक चातुर्य का खूब लाभ मिला।

एन्न लम्बे समय तक सीएसएएलएफ, सीएसएए के समकक्ष संस्था, कैनेडियन स्टडीज एसोसिएशन (सीईएसएडूएससीईई) और वीमेन एंड जेंडर स्टडीज इत रेचेर्वेस फेमिनिस्तेस (डब्ल्यूजीएसआरएफ) की तो इसकी पहली बैठक से ही, सदस्य रहीं। उनकी फ्रेंच और इंग्लिश समाज वैज्ञानिक समुदायों में गहरी पैठ थी और उन्होंने अपने उपनाम में फ्रेंच शब्द 'डेनिस' बरकरार रखा। अपने नाम में 'एस' की ध्वनि को अनुच्चरित (मूक) रखने की जिद के माध्यम से वह कनाडा में अंग्रेज समाजशास्त्रियों के बीच अपने करियर की शुरुआत से ही फ्रेंच भाषा और नस्लीय समानता के मुद्दे उठा सकीं। बाद में, वह फ्रेंच समर्थकों की बैठकों में कुएबेकोइस तथा अन्य कनाडाई सहकर्मियों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रेंच भाषा और संस्कृति के पक्षधर के रूप में ख्यात हुईं।

वर्ष 2011 में, एन्न ने कैनेडियन कांग्रेस ऑफ द ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंसेज में फेमिनिस्ट इंटर-डिस्प्लिनरी सेशंस की शुरुआत की और वर्ष 2013 में सीएसए'ज फेमिनिस्ट क्लस्टर की स्थापना की। इन दोनों एक दूसरे से जुड़े कार्यक्रमों के प्रशासन और सह-संचालन के दौरान फ्रेंच लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयं क्लस्टर दस्तावेजों का फ्रेंच में अनुवाद किया और दो भाषाओं में सत्रों का आयोजन करवाया। उनके जीवन भर तल्लीनता से किए गई कार्यों और प्रयासों के परिणामस्वरूप सीएसए और सीएसएएस में द्विभाषावाद पर विशेष ध्यान दिया गया और यह आज भी हो रहा है।

एन्न के समाजशास्त्रीय और नारीवाद की सम्पूर्णता से भरे प्रशासनिक तौर-तरीकों ने महिलाओं पर हो रहे शोध तक महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहुँच बढ़ाने के लिए वर्ष 1976 में स्थापित सीआरआईएडब्लू-आईसीआरआईएफ संस्थान को बचाने में भूमिका निभाई। वर्ष 2009 से 2015 तक एन्न इसके बोर्ड की सदस्य और पदाधिकारी (उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष) रहीं। यह वो दौर था तब सीआरआईएडब्लू और अन्य नारीवादी संगठनों को अस्तित्व समाप्ति का खतरा था। सरकारी सहायता घटाने की इस सजा की अवधि के दौर में, एन्न ने सीआरआईएडब्लू के संगठनात्मक अस्तित्व के पुनर्निर्माण के लिए अपनी क्रियाशील उपस्थिति के साथ स्वयंसेवी समितियों की पुनर्स्थापना सहित आवश्यक भूमिका निभाई। अपने वैश्विक हितों और प्रशासनिक क्षमताओं के चलते वह संयुक्त राष्ट्र में सीआरआईएडब्लू की पहचान की पुनर्स्थापना की आवश्यकताओं को समझ पाई। संयुक्त राष्ट्र में सीआरआईएडब्लू की प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महिला मुद्दों पर सहयोगी गैर-सरकारी संस्था की भूमिका में संगठनकर्ता और संचालक के रूप में महत्वपूर्ण काम किए और संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों के बारे में कनाडाईयों के साथ संवाद स्थापित किया।

एन्न की संवेदनशीलता और बहुमुखी प्रतिभा का एक उदहारण वर्ष 1994 में आईएसए में देखने को मिला। किसी दूसरे शहर में कांग्रेस से

पहले आरसी32 बैठक के बाद, हमारा समूह आइएसए पहुँचा, जहाँ हमारे समूह के ठहरने के लिए एकमात्र पहले से ही तय व्यवस्था की गई थी। आइएसए के अधिकारियों ने हम में से एक वरिष्ठ एशियाई शोधार्थी को अलग निकाल दिया। समूह को विभाजित करने के विरोध में वार्तालाप के दौरान एन्न से सभी पहलुओं को समझा। उन्होंने स्थिति को संभाला और सभी के लिए स्वीकार्य निर्णय तक पहुँचने में मुख्य भूमिका निभाई। अगली सुबह उन्होंने हमारे समूह की अलग हो गई सदस्य के रहने की व्यवस्था को दुरुस्त किया और संस्थान के अधिकारियों को इस पर सहमत होने के लिए तैयार किया। उनके प्रयास से हम अपने सहकर्मी से मिलने गैर-श्वेत प्रतिभागियों के लिए संरक्षित आवासीय परिसर में जा सके। हम, आइएसए के अन्य सदस्य तथा निर्णय लेने में समर्थ लोग इस नस्लभेद से डर गए थे। इस गंभीर घटना के दौरान एन्न द्वारा की गई कार्यवाही से आइएसए अधिक समान अधिकारवादी और सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन पाई।

निस्संदेह एन्न एक अच्छी शोधकर्ता थीं और वह शोध लेखन की एक बेहतरीन विरासत छोड़ गई हैं। उनका पीएचडी शोधकार्य 'द चेंजिंग रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज (1935-1968)' उनकी समाजशास्त्रीय कल्पनाशीलता, शोध को विशेष रूप से ऐतिहासिक सत्ता संरचनाओं के बीच जीवन की वास्तविकताओं पर टिकाने, का पूर्वाभास है। उनकी बाद की छात्रवृत्ति मुख्यतया कैनेडियन थी, जिसमें शिक्षा, महिलाओं के काम-काज, मजदूर वर्ग, इंटरनेट, और महिलाएँ, वर्ग और जातीयता पर फोकस किया गया। उनका शोध 1986 की आईएसए कांग्रेस के बाद भारत में और अंग्रेजी बोलने वाले कैरेबिआई क्षेत्रों विशेषकर बारबाडोस में अधिक महत्वपूर्ण हो गई। उन्होंने '(इन)इक्वलिटी, आइडेंटिटी एंड इंटरनेट यूज़ बाय माइनोंरिटीज इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड: यंग पीपल'स इंटरनेट यूज़ इन बारबाडोस एंड फ्रंकोफोन ओन्टारियो' (वैश्विक दुनिया में अल्पसंख्यकों के बीच (अ)समानता, पहचान और इंटरनेट का इस्तेमाल: बारबाडोस और फ्रंकोफोन ओन्टारियो में नौजवानों द्वारा इंटरनेट का उपयोग) पर एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल का नेतृत्व किया।

आईएसए की उपाध्यक्ष शोध (2002-06) के रूप में एन्न ने इसकी शोध समिति की कांग्रेस आयोजित करवाई। आईएसए की कार्यकारिणी में फिर से निर्वाचन के बाद उन्होंने 'द आएसए हैंडबुक इन कंटेम्प러리 सोशियोलॉजी: कनफिलक्ट, कम्पटीशन, कोऑपरेशन और 'द शेप ऑफ सोशियोलॉजी फॉर द 21 सेंचुरी' का सह-संपादन किया। ऐसी पहल के साथ-साथ एन्न ने आईएसए में रोजमर्रा के तथा दीर्घकालीन मुद्दों के साथ-साथ काफी समय से लंबित समस्याओं, जैसे कुछ शोध समितियों में अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा भाषाई और भौगोलिक विविधता की कमी, का भी समाधान किया।

एन्न की कनाडा और अंतर्राष्ट्रीय समाज शास्त्र के विकास और संचालन में प्रारम्भिक और विशेषकर नारीवादी और जातीय अध्ययनों में योगदान अतुलनीय है।

आज उनकी कमी महसूस की जा रही है, उनकी याद आ रही है और उनकी सराहना की जा रही है। ■

सभी पत्राचार

लिंडा क्रिश्चियनसेन-रफमैन को <ruffman@smu.ca>

एंजला माइल्स को <angela.miles@utoronto.ca>

और मर्लिन पोर्टर <mporter2008@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> प्रवासन आगे बढ़ते हुए

करिन शेरशेल, राइन मेन यूनिवर्सिटी ऑफ़ एप्लाइड साइंसेज, जर्मनी द्वारा



श्रेय: निक यंगसन
(क्रियेटिव कामन्स 3)

वैश्विक स्तर पर लोगों का एक स्थान छोड़कर दूसरी जगह प्रवास सामान्यतया सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक अधिकारों के वितरण में असमानता का परिणाम होता है। यदि आधुनिक वैश्विक दुनिया विभिन्न राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं में बंटी नहीं होती, तो हम प्रवास पर विचार या चर्चा नहीं करते। आधुनिक विश्व की राजनैतिक व्यवस्था, राष्ट्रीय और अति-राष्ट्रीय संरचनाओं से बनी है, जो नागरिकता और क्षेत्रीय नियंत्रण के निर्णय के अधिकार का दावा करते हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे पर जाने को नियंत्रित करने के प्रतिबंधात्मक कदम, विशेषतः शरण मांगने वालों को रोकने के प्रयास, प्रवासन पर हो रही चर्चा का प्रमुख विषय हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका) या यूरोप के लम्बे सीमा क्षेत्र के माध्यम से सीमा पर प्रवासन के सर्विदित उदाहरण हैं।

एक तरफ, नागरिकता आधुनिक समय की बड़ी उपलब्धि है। वहीं, दूसरी ओर, यह सामाजिक असमानता का सबसे बड़ा कारक और वाहक है। लोगों को पढ़ने के लिए, काम करने के लिए और आजीविका की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सीमाएं पार करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि प्रवासन एक पुराना चलन है, मानव इतिहास के आरम्भ से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसते रहे हैं। अपने लेख 'यूरोपियन इमेजिनेशन्स एंड अफ्रीकन मोबिलिटी रियलिटीज' में गर्दा हेक हमें लम्बे और विस्मृत कर दिए गए प्रवासन के इतिहास की याद कराती हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीकी महाद्वीप बेहतर जीवन के लिए यूरोप से बाहर निकलने और शरण माँगने वाले हजारों शरणार्थियों और आर्थिक प्रवासियों के लिए सुरक्षित स्थान रहा है।

इन दिनों, एक जगह दूसरे स्थान पर प्रवास या विस्थापन का मुख्य कारक वैश्वीकरण है। इस कारण का चलते भौगोलिक दूरियों का प्रभाव कम हो गया है। वर्तमान में प्रवासन की प्रक्रिया में जुड़े देशों और व्यक्तियों की संख्या विश्व इतिहास के किसी अन्य कालखंड के मुकाबले सबसे ज्यादा है।

प्रवासन से जुड़ी पुरानी और समकालीन नीतियां प्रवासियों के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूँजी, वस्तुओं, सूचनाओं और लोगों के देशांतर प्रवाह के अंतरसंबंध भी इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। एक देश से दूसरे में प्रवास की प्रक्रिया कई कारणों पर निर्भर है और प्रवासन के एक तरीके को चिन्हित करना असंभव है। प्रवासन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारणों से हो सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मानना है कि अगले कुछ वर्षों तक जलवायु परिवर्तन बड़ी संख्या में शरणार्थी प्रवासन का कारण रहेगा। इसी प्रकार, भूमि अधिग्रहण बार-बार विस्थापन का मुख्य कारण है।

लोगों का प्रवासन एकांत में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उपरोक्त सभी कारणों का अंतरसंबंध है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन मात्र यह नहीं है कि लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर बस रहे हैं, बल्कि इसे भौगोलिक और मानसिक सीमाओं के पार जाकर हमेशा के लिए होने वाली प्रवासन प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। कार्लोस सैंडोवल ने अपने लेख 'द सेंट्रल अमेरिकन कारावैन: ए ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी एक्सहोडस' में ऐसे प्रवासन अभियानों के सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इस यात्रा में कई कारणों को सम्मिलित किया गया है: गरीबी की दर, बिजली, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन की बढ़ती कीमतें होंडुरस और अल साल्वाडोर से लोगों के सामूहिक विस्थापन के शुरुआती कारण रहे। लोग अक्सर समूह में एक स्थान छोड़ते हैं और एक साथ सीमा पार करते हैं। एक साथ रहने से न केवल अपहरण और अवैध वसूली जैसी हिंसा से बचाव होता है, बल्कि प्रवासन के सामूहिक क्षणों को भी दर्शाता है।

वैश्वीकरण ने सीमाओं को पार करने में आसानी कर दी है तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। पूँजीवाद की वैश्विक पुनर्संरचना के चलते प्रवासी मजदूरों की मांग खूब बढ़ी है। प्रवासी मजदूर मेजबान देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेदिज़ यिल्माज़ तुर्की के सम्बन्ध में दर्शाते हैं कि आम तौर पर ये काम अनौपचारिक होते हैं। 36 लाख सीरियाई लोग युद्ध से बचकर अब तुर्की में रह रहे हैं। तुर्की के अधिकारी इन सीरियाई कामगारों के बड़े स्तर पर शोषण को बर्दाश्त कर रहे हैं। यिल्माज़ के लेख 'रिफ्यूजीज एज अनफ्री लेबर फ़ोर्स: नोट्स फ्रॉम तुर्की' में इन मजदूरों के शोषण की स्थिति का आकलन किया गया है।

हम सामयिक और भौगोलिक सीमाओं के पार अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन की निरंतरता और वृद्धि का अध्ययन कर रहे हैं। कई प्रवासियों ने अब दो या अधिक समाजों में रहने का प्रबंध कर लिया है: उनका गृह देश और उनका मेजबान देश। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासियों ने एक सामूहिक परिवेश निर्मित किया है, जो उनका राष्ट्र-राज्य की सीमा के पार सांकेतिक और सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है।

विविधता आधुनिक प्रवासन आन्दोलनों की बड़ी विशेषता है। प्रवासियों के कई वर्ग हैं: राजनैतिक शरण चाहने वाले, शरणार्थी, अवैध प्रवासी और प्रवासी मजदूर (इनमें बुद्धिमान और व्यावसायिक उच्च वर्ग तथा घरेलू नौकर दोनों शामिल हैं)।

बेहतर आवागमन और संचार सुविधाओं के चलते प्रवासियों का समकालीन प्रवाह वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया है। हम आसानी से सीमाओं के पार संपर्क कर लेते हैं और संचार के अन्तर्राष्ट्रीय चैनलों का उपयोग कर लेते हैं। हाल ही में मैंने इटली के खूबसूरत शहर वेर्काना की यात्रा की। वहां मैं एक मित्र से मिला जो यमन में पली-बढ़ी और अर्देन पर मिसाइल हमले के समय तीन सप्ताह के लिए वापस चली गई। वह अपने परिवार से मिली और उसने अकाल तथा मारे गए लोगों के बारे में लिखा। उसने गिरती हुई मिसाइलों की आवाज के बारे में लिखा। नई सूचना एवं संचार तकनीकों ने संभव और असंभव के अंतर को पाट दिया। हम अब अन्याय, शोषण और युद्ध के सामाजिक प्रभावों को तत्काल, जब ये अनुभव हो रहे हैं, महसूस कर सकते हैं। मीडिया न केवल अन्याय को प्रचारित करता है, बल्कि जीवन की बेहतर स्थितियों, प्रवास के रास्तों और घरेलू अधिकारों के हालात की भी जानकारी देता है।

प्रसिद्ध समाज विज्ञानी ज़िग्मंत बौमन ने कहा है: 'धन-दौलत वैश्विक वस्तु है और दुःख-परेशानी स्थानीय'। लोगों के पास प्रवास का अधिकार और अवसर है या नहीं, यह उनके आर्थिक सामर्थ्य, नागरिकता और लिंग पर निर्भर करता है।

लोगों के लिए पलायन की सुविधा और उसे रोकने के बीच निसंदेह एक विशेष तंत्र काम करता है। डोनाल्ड ट्रम्प की मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की बीच दीवार बनाने की तेज-तर्रार राजनीति और यूरोप की किलेबंदी का विचार इसके सर्वविदित उदाहरण हैं। हम देखते हैं कि दक्षिणपंथी आन्दोलन और नव राष्ट्रवाद तथा एकजुटता का एक साथ उभार हो रहा है। मानव अधिकारों पर आधारित विचारों के वैश्विक प्रसार के कारण प्रतिबंधात्मक नीतियों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुए हैं। सराह सिल्लिंगर अपने लेख 'अनड्रूइंग बॉर्डर्स इन सॉलिडेरिटी सिटीज' में 'शहरों के बीच एकजुटता' के विचार के बारे में बताती हैं। किसी भी शहर का राजनैतिक परिदृश्य उस शहर के जीवन के लोकतंत्रीकरण का केंद्र बन गया है। अब नागरिकता का विचार सम्बद्धता और अधिकारों तक पहुँच के लिए मोलभाव की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है।

आज की आधुनिक असमान और वैश्विक दुनिया में प्रवासन के बारे में सोचने का अर्थ है, सीमाओं की विशेष आवश्यकताओं, सम्बद्धता और अधिकारों को हासिल करने के लिए जरूरी कार्यवाही पर विचार करना। ■

सभी पत्राचार करिन शेरशेल को <Karin.Scherschel@hs-rm.de> पर प्रेषित करें।

> यूरोपीय कल्पना

और अफ्रीकी गतिशीलता का यथार्थ

गेर्दा हेक, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन काहिरा, मिस्र

जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल द्वारा बर्लिन में अक्टूबर 2018 में बुलाए गए अफ्रीकी नेताओं के एक शिखर सम्मलेन में उन्होंने अफ्रीका में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए एक बिलियन यूरो की नई विकास निधि की स्थापना की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण अफ्रीका से यूरोप की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। यह अफ्रीकी पलायन के बारे में यूरोपीय मानस में अभी भी प्रचलित दो मिथकों की ओर इशारा करता है: कि अधिकतर अफ्रीकी जो सागर पार पलायन कर रहे हैं, वे गरीब, अनपढ़, या अर्द्ध-कुशल हैं, और कि अफ्रीका महाद्वीप पलायन का गढ़ है। ऐसा लगता है कि यूरोप अफ्रीकी महाद्वीप की ओर स्वयं अपने प्रवास और अपनी औपनिवेशिक विरासत की ऐतिहासिक जड़ता का शिकार है। और यह औपनिवेशिक विरासत तथा अफ्रीकी देशों के साथ उसके जटिल रिश्तों का यूरो-अफ्रीकी विस्थापन नीतियों और उससे जुड़े संवाद पर गहरा प्रभाव रहता है।

यूरो-अफ्रीकी विस्थापन में ऐतिहासिक नजर डालने पर एक उपेक्षित इतिहास दिखाई देता है। पिछली दो सदियों के कई कालखंडों के दौरान अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप से निकले उन हजारों आर्थिक प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए सुरक्षित शरणगाह बना रहा, जो इस महाद्वीप में आश्रय और/अथवा बेहतर जीवन के लिए आए थे। 19वीं सदी के बाद के वर्षों में रूसी यहूदी उन पर हो रहे धार्मिक अत्याचार के कारण भागकर मिस्र में घुसे, जबकि यूनानी और इतालवी दिहाड़ी मजदूर स्वेज नहर के निर्माण कार्य में काम मांगने के लिए पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड, यूनान और युगोस्लाविया से 40,000 से अधिक शरणार्थियों ने मिस्र, फलस्तीन और सीरिया में शरणार्थी शिविरों में शरण ली। बड़ी संख्या में लोग तंज़ानिया, केन्या और यूगांडा भी पहुंचे।

> यूरोपीय विस्थापन नियंत्रण

वैश्विक स्तर पर लोगों के आवागमन को रोकना 21वीं सदी की शुरुआत के सबसे बड़े राजनैतिक मुद्दों में से एक बन गया है। वर्ष 2015 में लगभग 8 लाख शरणार्थियों के पहुँचने के जवाब में यूरोपियन संघ ने नवम्बर 2015 में 3.4 करोड़ यूरो के साथ 'ईयू इमरजेंसी ट्रस्ट फंड फॉर अफ्रीका' (ईयूटीएफ) का गठन किया। इसका उद्देश्य 'अनियमित प्रवासन के मूल कारणों' (यूरोपियन

कमीशन 2017) का हल निकालना था। ईयू के नेताओं ने पूरे अफ्रीका के देशों के साथ गहनता से काम करना शुरू किया, इन देशों के यूरोप से लोगों को वापस लौटाने की इच्छा दर्शाने पर विकास निधि देने और पलायन से जुड़े विस्थापन को रोकने के वायदे के बदले में नई सहायता राशि देने का सुझाव दिया।

यह सब नई बात नहीं है। 1980 के दशक के अन्त से ईयू ने अपनी आब्रजन और वीसा नीतियों को कड़ा करने के लिए कई गतिविधियां और तरीके अपनाए हैं। इसी क्रम में, विभिन्न देशों से होने वाले अनियमित प्रवासन के संभावित खतरों के आधार पर उन देशों की सूची स्वीकृत की गई है, जिनके नागरिकों को शरण क्षेत्र में प्रवेश के लिए वीसा की आवश्यकता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कुछ अफ्रीकी देशों के नागरिकों के लिए निरस्तीकरण दर सर्वाधिक है। 2014-17 की अवधि में, कैमरून के याओंडे स्थित जर्मन दूतावास में 45 वीसा आवेदन अस्वीकार किए गए।

इससे भी अधिक, ईयू और अफ्रीका के पड़ोसी देशों के बीच वार्तालाप में सीमाओं और प्रवासियों की हलचल पर नियंत्रण 2000 के शुरुआती काल से ही एक मुद्दा रहा है। वर्ष 2004 के बाद से, लीबिया से लोगों का प्रवास बढ़ने के कारण इटली और लीबिया के बीच कई समझौते हुए। इनके परिणामस्वरूप, उदाहरण के लिए, इटली के लम्पेदुसा द्वीप पर पहुंचे लोगों को लीबिया वापस भेजा गया, जहाँ उन्हें विशेष क्षेत्रीय शिविरों में रखा गया। वर्ष 2008 में, इतालवी प्रधानमंत्री सिलवियो बर्लुस्कोनी ने मुअम्मर गद्दाफी के साथ एक 'दोस्ती, सहभागिता और सहयोग समझौते' पर हस्ताक्षर किए थे। कई वर्ष तक लीबिया ने इटली से उपनिवेश काल के अपराधों के लिए हर्जाना राशि के रूप में करोड़ों के भुगतान की मांग की थी। इटली ने अब लीबिया में तटीय हाईवे के निर्माण और वित्तीय सहयोग का वादा किया है, जिस पर 20 वर्ष तक 25 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष खर्च होंगे। वर्ष 2011 में, लीबिया में क्रांति और लीबिया के विद्रोही आन्दोलन को नाटो का समर्थन मिलने पर गद्दाफी ने इटली के साथ सहयोग को खत्म कर दिया था, और बदले में लोगों के प्रवासन को ईयू के विरुद्ध हथियार के रूप इस्तेमाल किया। इस दौरान गद्दाफी के प्रति समर्पित सुरक्षाकर्मियों ने बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासियों को नावों में बैठने को मजबूर किया जो यूरोप नहीं जाना चाहते थे।

यूरोप अफ्रीकी महाद्वीप और उसकी औपनिवेशिक विरासत अपने स्वयं के उत्प्रवास के प्रति ऐतिहासिक जड़ता से ग्रसित प्रतीत होता है।

अप्रैल 2012 में अरब बसंत आन्दोलन के बाद इटली और लीबिया प्रवास पर नियंत्रण पर फिर से सहयोग करने पर सहमत हुए। 2 फरवरी, 2017 को इटली फिर से लीबिया की सेना और सीमा नियंत्रण बलों के साथ 'अवैध प्रवासियों की बाढ़ को नियंत्रित करने' पर काम करने को राजी हुए, ताकि प्रवासियों और शरणार्थियों को यूरोप पहुंचने से रोका जा सके। तब से, इटली की सरकार और ईयू ने लीबियाई तट रक्षा बल को समुद्र में निगरानी करने और समुद्र पार कर यूरोप पहुंचने के लिए प्रयासरत शरणार्थियों तथा प्रवासियों को वापस करने के लिए नावें, प्रशिक्षण और अन्य सहयोग उपलब्ध कराया है। लीबियाई तट रक्षा बल द्वारा 38,000 लोगों को रोका जा चुका है और उन्हें लीबिया में डिटेंशन केन्द्रों में ले जाया गया है।

वर्ष 2015 में, यूरोप और अफ्रीकी देशों के बीच 'प्रवासन नियंत्रण, पुनः प्रवेश के लिए सहमति, सीमा नियंत्रण' के सम्बन्ध में समझौतों का एक वृहद् संजाल, जो विकास के लिए सहयोग तथा अधिक वीसा स्वीकृतियों के आश्वासन से सीधे जुड़ा है बन चुका है। ये समझौते उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका तक हुए हैं। अफ्रीका के लिए ईयू इमरजेंसी ट्रस्ट फण्ड के गठन के बाद अफ्रीकी महाद्वीप में गतिविधियों का फोकस एक नई अवधारणा की ओर हो गया है, जिसके अनुसार अनियमित सीमापार गतिविधियों की 'बुराई' को इसके मूल स्थान पर ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। ईयू इमरजेंसी ट्रस्ट फण्ड की 63 राशि विकास परियोजनाओं पर खर्च हो रही है, 22 राशि प्रवासन प्रबंधन की योजनाओं पर और 14 सुरक्षा तथा शांति-स्थापना कार्यों के लिए। इसलिए ईयू इमरजेंसी ट्रस्ट फण्ड का अधिकतर हिस्सा यूरोपियन राष्ट्रीय संगठनों के पास जाता है। ईयू इमरजेंसी ट्रस्ट फण्ड के एक सहयोगी जर्मनी की संस्था जीआईजेड है, जो पूर्वी अफ्रीका में 'बेहतर प्रवासन प्रबंधन' कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न मानव अधिकार संगठनों द्वारा सूडान के पुराने लड़ाकों के साथ सहयोग के लिए इस संस्था की कड़ी आलोचना की जाती है।

> अफ्रीका की वास्तविकताएं

अफ्रीका महाद्वीप पर ईयू इमरजेंसी ट्रस्ट फण्ड के प्रभावों पर अभी अनुसंधान की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से यूरोपीय संघ अफ्रीकी सरकारों पर अपनी सीमा चौकियों को नियंत्रित करने और लौटाए गए प्रवासियों को वापस लेने का दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, इसे दो महाद्वीपों के बीच एक साथ गुंथे हुए और ताकत की असमानताओं, औपनिवेशिक नियंत्रण, शोषण और नस्लभेद के चलते उतार-चढ़ावों से भरे लम्बे इतिहास के एक अन्य अध्याय की तरह देखा जा रहा है। इसी दौर में, अफ्रीकी सरकारें यूरोप के अपने क्षेत्र से बाहर की गई हरकतों की खामोश पीड़ित बनी हुई हैं, क्योंकि अधिकतर नियम लचीले हैं। साथ ही, वर्षों के शोध से हम जानते हैं कि सीमाओं पर नियंत्रण से प्रवासन

की घटनाओं को आसानी से नहीं रोका जा सकता।

वास्तव में, अस्मिता परशोतम (2018) ने दर्शाया है कि अफ्रीका दुनिया में सबसे कम प्रवासन वाला क्षेत्र है, और अफ्रीका के अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी इसी महाद्वीप में रहते हैं। वर्ष 2017 में, 1.94 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी विस्थापित तथा अफ्रीका के बाहर से 50 लाख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अफ्रीका महाद्वीप में ही रह रहे थे। यूएनएचसीआर के अनुसार, कैमरून, चाड, डीआरसी, इथियोपिया, केन्या, सूडान, और यूगांडा आदि देश पूरी दुनिया के एक तिहाई (49 लाख) शरणार्थियों का घर हैं। हालांकि महाद्वीप से बाहर रह रहे अफ्रीकी विस्थापितों के संख्या वर्ष 1990 में 69 लाख से बढ़कर वर्ष 2017 में 1 करोड़ 69 लाख हो गई है, लेकिन ये आंकड़े यूरोपीय तटों पर पहुँचने वाले प्रवासियों की यूरोप के मीडिया द्वारा दिखाई गई छवियों से शायद ही मेल खाते हैं।

इसके अतिरिक्त, इनमें से सभी प्रवासी यूरोप में रहते भी नहीं हैं। उदहारण के लिए, मिस्र के 80 प्रतिशत से अधिक प्रवासी मजदूर सऊदी अरब, जॉर्डन और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। हाल ही में, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अन्य खाड़ी देशों के बीच प्रवासन से जुड़े सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। पिछले 30 वर्षों में, गुआनझोऊ, हांगकांग, दुबई और इस्तांबुल में भी अफ्रीकी प्रवासी समुदाय इकट्ठे हुए हैं। ये प्रवासी समूह अफ्रीकी व्यापारियों की विभिन्न महाद्वीपों के बीच आवागमन की उच्च चलायमानता से गहराई से जुड़े हैं। हालांकि यूरोप अप्रासंगिक नहीं है, लेकिन यह निश्चित तौर पर इस प्रकरण के केंद्र में नहीं हैं, जैसा कि अफ्रीकी प्रवासन के बारे में आम धारणा और अकादमिक जगत में दर्शाया जाता है। वास्तव में, अफ्रीका से न केवल यूरोप की सीमाओं, बल्कि महाद्वीप के अन्दर भी प्रवास गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यूरोप ने सूचनाओं के उत्पादन में भारी निवेश किया है। इसके जवाब में, दर्शनशास्त्री अशिल्ले म्बेम्बे ने हाल ही में सीमा रहित अफ्रीका महाद्वीप के विचार का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यूरोप द्वारा अफ्रीका के अन्दर ही प्रवास को नियंत्रित करने के प्रयासों के जवाब में अफ्रीका के उपनिवेशीकरण के खात्मे के अगले चरण में इस महाद्वीप के सभी लोगों को घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उनकी नागरिकता एक ऐसे राजनैतिक तथा सांस्कृतिक समूह के रूप में निर्धारित होनी चाहिए कि वह एक राष्ट्र-राज्य तक सीमित न रहे। ■

सभी पत्राचार गर्दा हेक को <gerda.heck@aucegypt.edu> पर प्रेषित करें।

> मध्य अमरीकी कारवाँ : 21वीं सदी का पलायन *

कार्लोस सैंडोवाल, कोस्टा रिका विश्वविद्यालय, कोस्टा रिका द्वारा



2018 में ग्वाटेमाला – मेक्सिको सीमा पर पुल पार करते प्रवासी।
फोटो: बोइवि/पिलकर। कुछ अधिकार सुरक्षित।

अक्टूबर 2018 के बाद से, मध्य अमरीकीयों द्वारा उनके गृह देशों, विशेषकर होंडुरास और अल-सल्वाडोर से हुए सामूहिक पलायन पर काफी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिया गया है। प्रवासियों का यह तथाकथित “कारवाँ” पहले ग्वाटेमाला और फिर मैक्सिको के रास्ते आगे बढ़ा और जून 2019 में कई अमरीका/मैक्सिको सीमा पर स्थित तिजुआना में उम्मीदपूर्ण रूप से इंतजार कर रहे थे।

> कारवाँ या पलायन ?

इस स्थिति का एक पहला तत्व जो चर्चा के लायक हो सकता है, वह है, “कारवाँ” की अवधारणा। कम से कम स्पेनिश के सामान्य उपयोग में, और संभवतः अन्य भाषाओं में भी “कारवाँ” शब्द आवश्यक रूप से खतरनाक अथवा जोखिम भरे प्रस्थान के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं होता है। “एक्सोडस” या “पलायन” एक वृहत् इतिहास से जुड़ा संप्रत्यय है, जो विशेषकर बाइबिल ग्रंथों से जुड़ा है। ये मध्य अमरीकी मामलों में लागू हो सकता है क्योंकि यह जबरन प्रवास की प्रकृति को इंगित करता है। आज, मध्य अमरीका में, कोई भी प्रवास का चयन नहीं करता है – यह अनिवार्य स्थिति बन गयी है। विचारणीय दूसरा बिन्दु यह है कि हम वास्तव में किस हद तक होंडुरन प्रवास में वृद्धिका सामना कर रहे हैं। अमरीकी सेंसस आंकड़ें हमें इस घटना को सही परिप्रक्ष्य में रखने हेतु सहायता प्रदान करते हैं। यदि हम 2000 और 2010 की जनगणना में गिने गए मध्य अमरीकीयों की तुलना करते हैं, तो यह देखा जा

सकता है कि 10 वर्षों में 136 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। होंडुरन प्रवासी आबादी में 191 प्रतिशत की वृद्धि हुई ; ग्वाटेमाला 180 प्रतिशत और साल्वाडोर की आबादी में 150 प्रतिशत। इसमें नई बात उन लोगों की संख्या नहीं है जो पलायन हेतु बाध्य हुए, बल्कि सामूहिक रूप से अपने देश को छोड़ने का निर्णय है।

> होंडुरन्स से सामूहिक प्रवास की व्याख्या

यहां, प्रवास कर रहे लोगों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है ; जितना यह, कि यह एक सामूहिक प्रवास है। ये सामूहिक गतिशीलता अस्थायी के साथ संरचनात्मक कारकों द्वारा प्रेरित मानी जा सकती हैं। बिजली, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन के साथ विभिन्न खाद्य उत्पादनों की लागत में वृद्धि आदि कुछ कारक हैं जो प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं। समूह में प्रवास, कम से कम अपहरण व जबरन वसूली के खतरे को कम करता है। कोस्टारिका को छोड़ कर, मध्य अमेरीका के देशों के लोगों को मैक्सिको में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। यह प्रवासियों को अनाधिकृत रूप से सीमा पार करने के लिए बाध्य करता है, जो उन्हें संगठित अपराधियों के साथ-साथ स्वयं मैक्सिकन पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्व्यहार के लिए असुरक्षित बना देता है। सोशल मीडिया के उभरते प्रभाव के संदर्भ में, कई लोग एक-दूसरे से संपर्क बना पाने में सक्षम हैं और यदि वे रात की बस में अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो एक साथ यात्रा करना अधिक उपयुक्त है।

गरिमापूर्ण रोजगार की कमी, प्रेरक कारकों के बीच निर्णायक है जिसे अधिक संरचनात्मक कहा जा सकता है। कुल मिलाकर सम्पूर्ण जनसंख्या के बीच गरीबी की दर 64.3 प्रतिशत है तथा इससे हिंसक संरचनात्मक परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनसे निपटना बहुत मुश्किल है, विशेषकर उन युवाओं के लिए, जो हर रात देश को त्यागने वाली जनसंख्या का मौन बहुमत बनाते हैं।

राजनीतिक शब्दों में, होंडुरन तख्तापलट ने निःसंदेह सामाजिक ताने-बाने को और भी नाजुक बना दिया है। जून 2019 तख्तापलट की दसवीं वर्षगांठ होगी और नवम्बर 2017 में, विरोध, संदेह तथा चुनावी धोखधड़ी के दावों के मध्य हुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज पुनः निर्वाचित हुए। हर्नांडेज संविधान में बदलाव करने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति मिली; विडंबना यह है कि 2009 के तख्तापलट के प्रेरक कारकों में से पुनः चुनाव का विरोध एक था।

कारकों का तीसरा संयोजन सामाजिक है। होंडुरास में भारी मात्रा में आपराधिक हिंसा होती है। 2016 में, काराकास के बाद, सैन पेद्रो सुला दुनिया में सबसे अधिक हिंसक शहर था, जिसमें नर-हत्या दर प्रति 100,000 निवासियों पर 111 थी।

> मार्ग एवं अभिग्रहण

उत्तर की ओर कूच करने में शामिल होने वालों में से अधिकांश लोगों ने यूएस-मैक्सिको सीमा पर जाने के लिए सबसे लंबा रास्ता चुना। इस निर्णय ने यात्रा को और भी थका देने वाला बना दिया। यह निर्णय संभवतः मैक्सिको की खाड़ी के साथ मार्ग से बचने की इच्छा से प्रेरित था जहां संगठित अपराध की स्पष्ट उपस्थिति है, तथा इस तरह जबरन वसूली तथा हत्या की स्पष्ट संभावनाएं हैं। सैन पेद्रो सुला, होंडुरास और तमुलिपास, मैक्सिको (खाड़ी क्षेत्र पर) के बीच 2700 किलोमीटर की दूरी है। फिर भी अधिकांश प्रवासियों ने लगभग 4,348 किलोमीटर दूरी पर स्थित तिजुआना, जो मैक्सिको के प्रशांत क्षेत्र तरफ है, को यात्रा के लिए चुना।

वर्तमान में, आव्रजन अधिकारियों द्वारा यह आवश्यक किया गया है कि तथाकथित "कारवां" के रूप में सीमा पर पहुंचने वाले लोग मैक्सिकन अधिकारियों द्वारा नियंत्रित सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं। यह सूची प्रवासियों को अमरीका में शरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।

अमरीकी सरकार शरणार्थियों से प्राप्त हुए आवेदनों में से बमुश्किल 10 प्रतिशत को ही मंजूरी देती है। इस परिस्थिति में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (यू.एन.एच.सी.आर.) किसी भी नेतृत्व की भूमिका को निभाता नहीं नजर आ रहा है। अमेरीका यू.एन.एच.सी.आर. के लिए बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करता है और इसका सबसे बड़ा वित्तीय समर्थक है।

> जारी रखने हेतु

समापन में, विशेष रूप से तीन महत्वपूर्ण विचारों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। पहला यह कि 6 नवम्बर 2018 को अमरीका में मध्यावधि चुनाव हुए थे और मैक्सिको की सीमा वाले चार राज्यों में, नौ में से आठ कांग्रेस जिलों ने डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए मतदान किया। अप्रवासियों के प्रति घृणा को प्रोत्साहित करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक वृहत चुनावी लहर पैदा नहीं हुई, यह इस संभावना की उम्मीद जगाती है कि अप्रवासी घृणा को राजनीतिक रूप से हराया जा सकता है।

दूसरा, दिसम्बर 2018 की पहली तारीख को, आन्ड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें अपने सामने विभिन्न मुश्किल एवं जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से मध्य-अमरीकी प्रवास भी आवश्यक मुद्दा होगा। मोरक्को के मरक्केच में आयोजित प्रवास पर हालिया शिखर सम्मेलन के दौरान, मैक्सिकन सरकार ने अनुमानित 200,000 मध्य अमरीकियों को रोजगार की पेशकश की जो हर साल मैक्सिको से गुजरते हैं। हालांकि, जून 2019 में, लोपेज ओब्राडोर ने ट्रम्प को अमरीका के लिए मैक्सिकन निर्यात कर लगाने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने से रोकने के रूप में आव्रजन नियंत्रण को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है।

अंत में, परन्तु महत्वपूर्ण रूप से, ट्रम्प का पुनः निर्वाचन और मैक्सिको में एक नए राष्ट्रपति और विधायी कार्यकाल की शुरुआत से परे, मध्य अमरीका में प्रवास न करने के अधिकार की गारंटी देना, बड़ी चुनौती है। मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में इस क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई भारी अनुचितता एवं असमानता से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। यह एक बड़ी बाधा है, जिसे दुर्भाग्य से, शासक वर्ग द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है। इस तरह की अनुचितता और असमानता की स्थिति को कैसे सुधार जाए, बेशक मध्य अमरीका में प्रगतिशील विचार और क्रिया के लिए परीक्षा है।

अक्टूबर 2018 में मैक्सिको की ओर प्रवास करते हुए दो होंडुरन महिलाओं का बीबीसी ने साक्षात्कार किया, जिसमें उन्होंने इस अन्याय और असमानता को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया। उनमें से एक ने कहा— 'अगर संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति होंडुरास की मदद नहीं करते हैं तो यह मुझे चिंतित नहीं करता है क्योंकि मुझे उनसे कोई मदद नहीं मिलती है'। दूसरी महिला ने, निष्कर्ष रूप में कहा 'हम ट्रम्प की धमकियों से डरने वाले नहीं, हम अपने देश से भाग रहे हैं क्योंकि हम अपने ही देश से बहुत डरे हुए हैं।' ■

* यह मूल रूप से वेबपेज www.madrimas.org पर स्पेनिश में छपे आलेख का एक सम्पादित संस्करण है।

सभी पत्राचार कार्लोस सेन्डोवल को <carlos.sandoval@ucr.ac.cr> पर प्रेषित करें।

> पराधीन श्रम बल के रूप में शरणार्थी : तुर्की से टिप्पणी

बेदिज यिल्माज, आईएमआईएस-ओसनाब्रुक विश्वविद्यालय, जर्मनी और माया एसोसिएशन-मर्सिन, तुर्की द्वारा



मर्सिन की परिधि पर ग्रीनहाउस डंडों के आसपास खेल रहे बच्चे, अदनालिग्लू ग्रामीण क्षेत्र, तुर्की के दक्षिण में, 2015।
फोटो : ए. ऑनर कुर्त।

लगभग 3.6 मिलियन सीरियाई और अन्य राष्ट्रीयताओं से 600,000 के साथ, तुर्की अब तक दुनिया में सबसे बड़ा शरणार्थी आबादी वाला देश है। यह तुर्की अधिकारियों के लिए शेखी बघारने वाला तथ्य है तथा अन्य देशों, में जो तुर्की को एक मॉडल के रूप में देखते हैं एड्स की सराहना की जाती है।

इस लघु पत्र में, मैं एक मध्य आकार के शहर के उदारहण के साथ तुर्की मॉडल की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करूंगा जिनमें मैं प्रवास से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान तथा सक्रियतावाद दोनों में शामिल रहा हूँ। परन्तु सर्वप्रथम मैं शरणार्थी-शब्द के उपयोग के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। 1951 के जिनेवा कन्वेंशन पर तुर्की द्वारा लगाई गई भौगोलिक सीमा के कारण तुर्की में सीरियाई लोग “अस्थायी संरक्षण” के अधीन हैं। यह प्रस्थिति उन्हें कई अधिकार, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक बेशर्त पहुंच आदि प्रदान करती है, परन्तु यह उनकी शरणार्थी प्रस्थिति के आश्वासन तथा भविष्यवाणी प्रदान करने में विफल रहती है। इस प्रकार यह अपने लाभार्थियों को एक अनिश्चित और असुरक्षित स्थिति में रखता है, जो मुख्य रूप से अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मनमानी के कारण होता है, जो राजनीति पर अत्यधिक निर्भर है। उन्हें शरणार्थी कहकर, मैं अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था की इन विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ और साथ

ही, इस तथ्य को रेखांकित कराना चाहता हूँ कि यद्यपि वे शरणार्थी स्थिति में हैं, परन्तु उनमें इस प्रस्थिति का अभाव है।

> अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था की विशेषताएँ

यह कमी तुर्की में सीरियाई लोगों की नियति को परिभाषित करने के लिए निर्धारक है और एक बड़ी शरणार्थी और शरणार्थी आबादी वाले विभिन्न देशों के बीच अंतर को बताती है। इस पत्र में, मैं शरणार्थियों के श्रम-पहलू, विशेष रूप से कृषि में काम करने वालों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। यह बताना गलत नहीं होगा कि तुर्की वर्तमान में शरणार्थी श्रमिकों पर निर्भर है; जहां तुर्की में 3.6 मिलियन सीरियाई लोगों में से लगभग आधे कामकाजी उम्र के हैं, परिमित प्राप्त करने की कठिनाईयों के कारण, उनमें से केवल 31,000 को ही कार्य परमित मिले हैं। परिणामस्वरूप, शरणार्थियों की कामकाजी स्थितियों को अनौपचारिकता द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसलिए मैं यह तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा कि तुर्की में पहले ही बहुत व्यापक अनौपचारिकता (कुल मिलाकर लगभग 50 प्रतिशत तथा कृषि में 85 प्रतिशत से अधिक), ही वह स्थिति है जो तुर्की मॉडल को कार्यान्वित करती है। दूसरे शब्दों में, श्रम में अनौपचारिकता के उच्च स्तर के बिना, सभी द्वारा स्वीकृत, अधिकारियों द्वारा सहनीय

तथा नियोक्ताओं द्वारा फायदा उठाए जाए बिना, इतनी संख्या में सीरियाई इस देश में नहीं रह सकते थे। श्रम में सीरियाई लोगों का शोषण और उनके साथ रोजमर्रा की भाषा में भेदभाव उनकी राजनीतिक संबद्धता के बावजूद, समाज के लगभग सभी सदस्यों के लिए आम हो गया है।

इस परदृश्य में कृषि की विशिष्टता है। कार्य परमिट, अन्य क्षेत्रों में मुश्किल से प्राप्त तथा जो सस्पर्म्पर्थियों को शोषण के चरम स्तरों में कार्य करने को बाध्य करते हैं, की कृषि में आवश्यकता नहीं है, जिससे अग्रिम शोषण के द्वार प्रशस्त होते हैं। रेगुलेशन ऑन वर्क परमिट्स फार फोरनरस अण्डर टेम्परी प्रोटेक्शन (2016/8375) के अनुच्छेद 5(4) के अनुसार, अस्थायी संरक्षण के तहत विदेशी और जो कृषि और पशुपालन में काम करते हैं, उन्हें वर्क परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। तुर्की के एक पूर्वी भूमध्यसागरीय शहर मर्सिन के बाहरी इलाके में एक कृषि क्षेत्र अदनलीओग्लू में एक कार्यकर्ता-शोधकर्ता के रूप में मैं अपने अवलोकन के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत करूंगा कि कृषि क्षेत्र में सस्पर्म्पर्थी-पराधीन श्रमिकों के एक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेखक निकोला फिलिप्स द्वारा समकालीन पराधीन श्रमिकों को परिभाषित करने के लिए पराधीन श्रमिकों पर उनके 2013 के लेख की योजना का पालन करूंगा।

> सस्पर्म्पर्थी-पराधीन श्रमिकों के रूप में

इस योजना के पहले आयाम में ऋणग्रस्तता [...] के आधार पर अनौपचारिक, मौखिक और अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं जो "ऋणग्रस्तता के आधार पर श्रमिक को अनुशासित करने, उन्हें संबंधों की श्रृंखला में बांधने, एवं अक्सर चलने ताकि श्रमिकों के शोषण को अधिकतम किया जा सके" के लिए काम में लिए जाते हैं। उन कृषि क्षेत्रों में जहां हमने अवलोकन किया, कृषि में उत्पादन संबंधों में श्रमिक बिचौलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी सर्वव्यापी भूमिका सीरियाई लोगों के साथ बड़ी है, जिनके पास स्थानीय भाषा का अभाव है। बिचौलियों को प्रत्येक दैनिक भुगतान से एक हिस्सा मिलता है, आमतौर पर 10 प्रतिशत। वे श्रमिकों को नौकरी, आवास और भुगतान संबंधी सेवाओं को खोजने में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे कार्य पूरा करने और नियुक्ताओं के लिए किसी भी श्रमिक-संबंधी मुद्दों के निपटान को सुनिश्चित करते हैं। यह सस्पर्म्पर्थी-श्रमिकों के लिए कृषि मध्यस्थों पर पूर्ण निर्भरता लाता है।

दूसरा, पराधीनता "मुख्य रूप से जबरन प्रवेश द्वारा नहीं बल्कि पहले से बंद निकासी द्वारा गठित होती है ; ये स्थितियां अक्सर ऋणग्रस्तता और/अथवा एक अनुबंध के अंत तक भुगतान पर रोक द्वारा स्थापित होती हैं।" हमारे मामले में, प्रत्येक उत्पाद के लिए

फसल के मौसम के अंत में भुगतान किया जाता है जो छह से सात महीने तक का हो सकता है। सीजन के दौरान, श्रमिकों को या तो कुछ खर्च दे दिया जाता है या वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं और स्थानीय बाजार से बंधते हैं, जो आमतौर पर मध्यस्थ के स्वामित्व में होता है।

तीसरा, पराधीन श्रम के समकालीन रूपों में आमतौर पर भुगतान के बिना कार्य शामिल नहीं होता है तथा धन के लिए श्रम का आदान-प्रदान होता है ; हालांकि "मजदूरी किसी भी तरह से इन स्थितियों के तहत विनियोजित श्रम द्वारा जोड़े गए मूल्य के बराबर नहीं होती है।" हमारे अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि श्रमिकों को स्थापित मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है और कभी-कभी भुगतान ही नहीं किया जाता है। लेकिन उनके पास छोड़ के जाने का विकल्प नहीं होता है क्योंकि अक्सर उनका "पैसा अंदर" होता है, जिसकी उन्हें आंशिक प्राप्ति की उम्मीद रहती है।

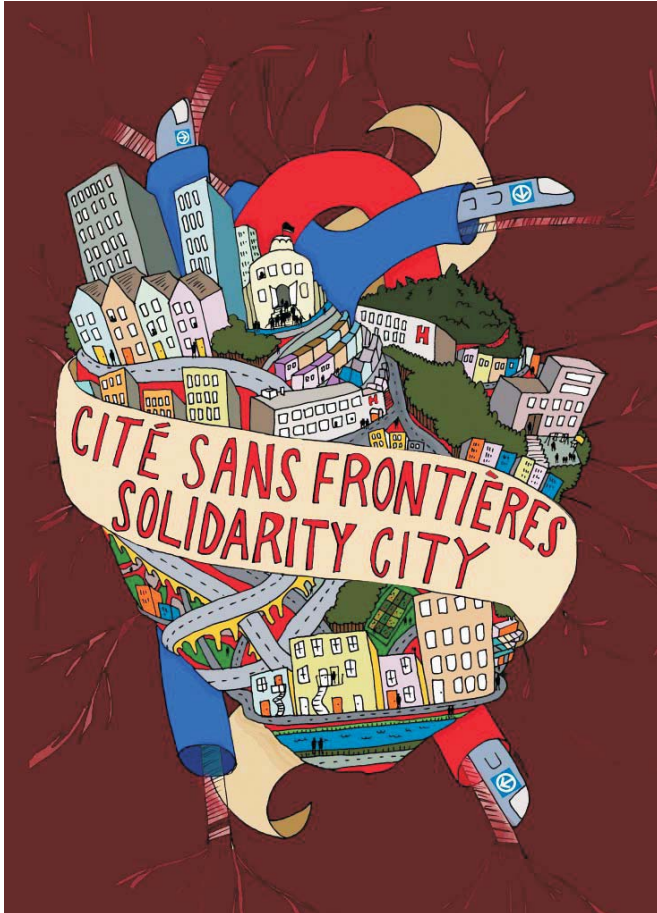
अंततः, पराधीनता को उन शोषणकारी परिस्थितियों में गठित किया जाता है जो "कठोर, अपमानजनक और काम की खतरनाक स्थितियों, श्रमिकों के श्रम (और अक्सर मानव) अधिकारों के उल्लंघन और श्रमिकों को अधिक मेहनत, अधिक समय और कम पैसों के लिए कार्य करने हेतु डिजाइन किये गये दबाव के स्वरूप और छलकपट से समबद्ध हैं।" यथार्थ में, सस्पर्म्पर्थी-श्रमिक इस प्रयोजन के लिए मध्यस्थों द्वारा किराए पर दिए गए खेतों पर बने टेंटों में रहते हैं, (श्रमिक टेंट लगाने के लिए किराए का भुगतान भी करते हैं); मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और वे पानी के लिए भुगतान करते हैं और बिजली का वे खेतों के उपर से जा रहे तारों के उपर केबल बिछाकर अवैध रूप से उपयोग करते हैं। कृषि मध्यस्थ विशेष फसलों के लिए मौसम के अनुसार कार्य-स्थल का निर्णय करता है; श्रमिक केवल कुछ दिन पूर्व ही यह जान पाते हैं कि उन्हें एक नए स्थान पर जाना है।

यह सच है कि तुर्की सबसे बड़ी सस्पर्म्पर्थी-आबादी है, लेकिन यह उन्हें एक गरिमामय जीवन, एकीकरण का मार्ग, तथा भविष्य के लिए वादा प्रदान नहीं करता है; इसके बजाय आंतरिक और विदेशी राजनीतिक आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित अंतरचित और दैनिक उपाय, मॉडल को आकार प्रदान करते हैं। यह बेहद असंभव है कि यह मॉडल तुर्की के लोगों को एक साथ रहने का पारदर्शी और संरचित मॉडल प्रस्तुत करेगा। क्या तुर्की सरकार विश्वसनीय, जवाबदेह, जिम्मेदार है ? क्या यह वास्तव में एक मॉडल हो सकता है ? ■

सभी पत्राचार बेदिज यिल्माज को <bedizyilmaz@yahoo.com> पर प्रेषित करें।

> एकजुट शहरों में सीमाओं को खोलना

सारा शिलिंगर, बेसल विश्वविद्यालय, स्विटजरलैंड द्वारा



दुनिया भर में शहर न केवल प्रवासन शासन के भविष्य के आसपास संघर्ष और प्रयोग के स्थान बन गये हैं, बल्कि नगरीय जीवन के लोकतांत्रिकरण हेतु सभी के लिए शहर के अधिकार के सन्दर्भ स्थान भी बन गये हैं।
श्रेय : एकजुटता शहर।

विभिन्न यूरोपीय शहरों की नगरपालिका सरकारें अपने शहरों को “सॉलिडेरिटी सिटीज” (एकजुट शहर) घोषित कर रही हैं, जबकि यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के नेता प्रवास नीति प्रतिबंधों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे भूमध्य सागर में हजारों लोगों की मौत को स्वीकार कर रहे हैं तथा संकटग्रस्त शरणार्थियों की सहायता करने वालों का अपराधीकरण कर रहे हैं। इस प्रकार शहर न केवल प्रवासन शासन के भविष्य के आसपास संघर्ष और प्रयोग का एक स्थान बन गए हैं, बल्कि नगरीय जीवन के बुनियादी लोकतांत्रिकरण हेतु सभी के लिए शहर के अधिकार के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। नगरीय “शहरी नागरिकता” के लिए ये संघर्ष, शहरों की राष्ट्र-राज्यों की राष्ट्रीय सीमाओं को खींचने व बनाए रखने की क्षमता को न केवल चुनौती देने की संभावनाएं दिखाते हैं, बल्कि नागरिकता के मूल अर्थों को भी प्रकट करते हैं।

> समुद्र से शहरों की ओर पुल

“शरणार्थी शहरों” के प्रति प्रतिबद्धता में स्थानीय स्तरों पर राजनैतिक हस्तक्षेप सम्मिलित है। इटली (जैसे नेपल्स, पलेर्मो) और स्पेन (बार्सिलोना) के तटीय शहरों में प्रगतिवादी महापौरों ने अपने बंदरगाहों को खोलने के साथ-ही-साथ समुद्र में बचाए लोगों के स्वागत के प्रस्ताव के पक्ष में विचार व्यक्त किये हैं। सिसली तटरेखा की सीमा में हजारों लोगों के डूबने के पश्चात, सिसली की राजधानी पलेर्मो के मेयर लेओलुका ऑरलैंडो ने अपने शहर को “शरणार्थी शहर” घोषित किया। ऐसा करने वाले वे यूरोप भर में प्रथम थे। लेओलुका ऑरलैंडो ने यूरोप भर में अपने इस वाक्य के साथ व्यापक ध्यान उत्पन्न किया : “यदि आप यह पूछें कि पलेर्मो में कितने शरणार्थी रहते हैं, तो मैं यह जवाब नहीं दूंगा: 60,000 या 100,000। बल्कि : बिल्कुल नहीं। जो कोई भी पलेर्मो आता है, वह एक पलेरमोइटन (पलेर्मो निवासी) है।” उनके द्वारा स्थापित “पलेर्मो चार्टर” यह मांग करता है कि नागरिक अधिकार विशेष रूप से लोगों के निवास स्थान से जुड़े हों।

जर्मनी में भी, नगरीय सरकारों ने सुरक्षित घरों की तलाश में लोगों को शरण देने की इच्छा व्यक्त की है। नागरिक समाज के हजारों लोगों के साथ गठजोड़ो (जैसे “सीब्रुके” और “अनटेलबार”), जिनके निरंतर प्रदर्शनों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सुरक्षित हार्बर्स (आश्रमस्थलों) का निर्माण संभव हो पाया है, ने पुनर्वास कार्यक्रम के समान ही शरणार्थियों के लिए सुरक्षित निकलने के मार्गों, समुद्री बचाव-कार्यों का गैर-अपराधीकरण, और शरणार्थियों के प्रत्यक्ष और मानवीय स्वागत आदि की बात रखी है।

> नगरीय आधारभूत संरचना तक भयविहीन पहुँच

उत्तरी अमरीका के अनुभव, विशेष रूप से अभ्यारण्य शहरों का आंदोलन जो 1980 के दशक से विकसित हो रहा है, यूरोप में सॉलिडेरिटी सिटी आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। अभ्यारण्य शहरों (सैंक्चुरी सिटीज) के प्रस्थान का केंद्र शहर के अवैध निवासी हैं। अप्रलेखित प्रवासियों के लिए सीमा, रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे स्कूल में भाग लेने, अस्पतालों में जाने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने आदि में पुनर्उत्पादित की जाती है। जो लोग यह साबित नहीं कर सकते हैं कि उनके पास सही कागजात है, उन्हें बुनियादी सामाजिक सेवाओं तक की पहुँच से बाहर रखा जाता है तथा उनका अपराधीकरण, गिरफ्तारी व निर्वासन किया जा सकता है।

नगरीय निवासियों को निर्वासन से बचाने और शहरी बुनियादी ढांचे और सामाजिक अधिकारों तक पहुँच प्रदान करने के लिए

>>



सीमापार प्रवासी न्याय नेटवर्क
एकजुटता का बैनर।
श्रेय: सीमापार एकजुटता।

सामाजिक आंदोलनों और शहर की सरकारों के बीच सहयोग के विभिन्न रूपों का परीक्षण किया गया है, जो एक साथ राष्ट्रीय अधिकारियों और उनकी प्रवास नीतियों का विरोध करते हैं। एक "डोन्ट आस्क, डोन्ट टेल (मत पूछो, मत बताओ) नीति (जैसी कि टोरंटो में प्रारम्भ की गई), सार्वजनिक सेवा प्रदान करने वाले शहरी कर्मचारियों को, प्रवास की प्रस्थिति के बारे में पूछने पर रोक लगती है और यदि पता चल जाता है, तो इसे अन्य राज्याधिकारियों तक पारित करने पर रोक लगाती है ("मत बताओ")। न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ शहरों में हर कोई जो शहर में अपनी पहचान और निवास को साबित कर सकता है, एक अधिकारिक नगरपालिका पहचान पत्र का हकदार है जो नियमित निवास के बिना रह रहे लोगों को अपने रोजमर्रा के शहरी जीवन में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही, शहरी संसाधनों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है।

वर्तमान में न्यूयॉर्क के उदाहरण के बाद, सॉलिडैरिटी सिटी आंदोलन के कार्यकर्ता विभिन्न जर्मन भाषी शहरों (जैसे हैम्बर्ग, ज्यूरिख, बर्न) में सिटी आईडी कार्ड लाने की मांग कर रहे हैं। बर्न की शहरी सरकार ने पहले ही इसके पक्ष में बात की है, यद्यपि कार्ड की विषयवस्तु तथा पहुंच मापदंडों पर अभी भी चर्चा जारी है।

> सीमाओं को खोलना

नगरीय सरकारें (आंतरिक) सीमा व्यवस्थाओं में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं क्योंकि कल्याणकारी सेवाओं का विकास और उनका कार्यान्वयन राष्ट्रीय नियमों की शहरी व्याख्या पर निर्भर करता है। जहां अनिश्चित स्थिति वाले प्रवासियों के लिए सामाजिक अधिकारों पर प्रतिबंध आंतरिक प्रवासन नियंत्रण का एक रूप है, स्थानीय स्तर पर अनियमित प्रवासियों के लिए कल्याणकारक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना राष्ट्रीय सीमाओं की मौजूदा अवधारणा को चुनौती दे सकता है।

यह नागरिकता की अवधारणा के विस्तार को दर्शाता है : नागरिकता को न केवल एक प्रस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है अपितु एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में, जिसमें अधिकारों तक पहुंच और उनका उपयोग शामिल है। यह व्याख्या कानूनी नियमों को कम महत्व देती है; इसके विपरीत विशिष्ट सामाजिक संबंधों, मानदंडों, एकजुटता की प्रथाओं तथा संबद्धता के लेन-देन आदि पर अधिक केंद्रित है। अतः यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन सभी वास्तविक स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जहां नागरिकता संबंधी लेन-देन की प्रक्रिया दिन-प्रतिदिन के जीवन में की जाती है, तथा जहां शहरी समुदायों के भीतर एकजुटता के नए रूपों का प्रयोग किया जाता है।

यहां पर उठाई गई समस्या मुख्य रूप से प्रवास नहीं है, बल्कि सामाजिक अधिकारों का असमान वितरण और संसाधनों तक

असमान पहुंच है। यह वर्तमान में प्रचलित प्रवास के "एकीकरण अनिवार्यता" के संभाषण में बदलाव कर इसे असमानताओं को संबोधित करने हेतु सामाजिक भागीदारी के सवालों की ओर मोड़ता है। इसके अन्तर्गत वर्तमान के शहरों के अधिकार संघर्ष जुड़े हैं जिसके मूल में उच्च कुलीनता तथा सार्वजनिक स्थानों का वस्तुकरण का प्रतिरोध निहित है। साथ ही, शहरी बुनियादी ढांचे के सामूहिक विनियोग व भागीदारी के अधिकार शामिल हैं।

> ठोस काल्पनिक आदर्श

सॉलिडैरिटी सिटी के नारे के साथ जुटने वाले इन विभिन्न पहलों के साथ सामान्य बात ठोस आदर्शवाद का आह्वान है। इस ठोस कल्पनालोक में एक दूसरे से भिड़ने के बजाय प्रवासन और सामाजिक नीति के मुद्दों को जोड़कर राजनीतिक बाधाओं से बाहर निकलने की क्षमता है।

इसके अलावा, सॉलिडैरिटी सिटी की अवधारणा सामाजिक आवास, शहरी बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक व लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए निर्धनता के खिलाफ व्यापक गठजोड़ को सक्षम बनाती है। शहरी स्थलों में अत्यंत ठोस आवश्यकताओं और वास्तविकताओं से शुरू होकर विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के रोजमर्रा के संघर्ष, जो अन्यथा अक्सर अलग-अलग संचालित होते हैं, एक साथ आ सकते हैं एवं संयुक्त रूप से शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव के अनुभवों के खिलाफ विविध शहरी अस्थिरता में एक नई जागरूकता पैदा कर सकते हैं।

अक्सर ऐसी ठोस पहलें तथा जमीनी आंदोलन ही कुछ राजनीतिक प्रयोगों के लिए नींव रखते हैं। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए कार्यकर्ताओं, प्रगतिवादी शहरी राजनेताओं और स्थानीय अधिकारियों/प्रशासन के मध्य सेतु बनना आवश्यक है। हालांकि शहरी स्तर को अधिक भी नहीं आंका जाना चाहिए : कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए स्थान के बावजूद, शहरों को वैश्विक शक्ति संरचना में एकीकृत किया गया है तथा राष्ट्र-राज्य राजनीतिक संघर्षों के लिए महत्वपूर्ण मैदान बना हुआ है।

अंत में, यह अवधारणा, संबद्धता की एक नई समझ को बनाने का अवसर भी शामिल करती है। यह वास्तव में इस बारे में नहीं है कि एक "अन्य" कौन है अथवा उसे कैसा होना चाहिए। बल्कि यह सामूहिक रूप से एक नए "हम" की कल्पना करने की संभावना प्रदान करता है। यह प्रवास-पश्च के समाज की वर्तमान वास्तविकता का एक लंबा अतिदेय समायोजन है, जिसमें प्रवास को एक तथ्य के रूप में मान्यता दी जाती है। ■

सभी पत्राचार सारा शिलिंगर को <sarah.schilliger@unibas.ch> पर प्रेषित करें।

> भविष्य के लिए विद्यार्थी पारिस्थितिकी वर्ग राजनीति

जूलिया कैसर, लिपजिग विश्वविद्यालय, जर्मनी तथा जैस्पर स्टैंज, हम्बोल्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन, जर्मनी द्वारा



लिपजिग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एक साधारण सभा के लिए मिलते हैं। श्रेय : जूलिया कैसर

एक सदी में हमारी दुनियां कैसी दिखेगी ? हाल ही के अध्ययनों के अनुसार, वैश्विक आबादी की अधिकांश जनसंख्या को प्रति वर्ष कई सप्ताह तक मानव उत्तर जीविता से परे ताप परिस्थितियों के अधीन होना होगा। शुष्कीकरण से दुनिया की 30 प्रतिशत से अधिक भूमि की सतह प्रभावित होगी। उष्णकटीबंधीय क्षेत्रों से एक अरब से अधिक लोग विस्थापित होंगे। जर्मन भौतिक विज्ञानी हैराल्ड लेस हाल ही में इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि शायद मानवता इस बात को स्वीकार करेगी कि वह केवल तबाही से ही सीखती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दृष्टिकोण से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद हम इस स्थिति को विज्ञापित करने में कोई गंभीर दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।

हालांकि ग्रेटा थुनबर्ग के साप्ताहिक स्कूल धरनों से प्रेरित आज दुनिया भर के युवा, सड़कों तक अपना गुस्सा लेकर जा रहे हैं तथा जलवायु राजनीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यह वैश्विक आंदोलन फ्राइडे फॉर फ्यूचर के रूप में विकसित हुआ है। साप्ताहिक स्कूल धरनों, प्रदर्शनों और विरोध के अन्य रूपों के माध्यम से वे मुख्य रूप से पेरिस समझौते में वर्णित 1.5°C लक्ष्य का अनुपालन करने के लिए राजनेताओं पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं।

जर्मनी में इस आंदोलन को व्यापक स्वीकृति मिली है। इससे 250 से अधिक स्थानीय अध्याय स्थापित किए गए हैं तथा 55 प्रतिशत जनसंख्या ने आंदोलन की चिंताओं के लिए समर्थन व्यक्त किया है। स्कूल के विद्यार्थियों की मांगों के एकजुटता में “भविष्य के लिए वैज्ञानिक” (साइंटिस्ट फॉर फ्यूचर) और “भविष्य के लिए कलाकार” (आर्टिस्ट फॉर फ्यूचर) जैसे संगठनों का गठन किया गया है। अपने सामाजिक आधार का इतना व्यापक होना आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक उद्देश्यों में से एक है। इसके पीछे

तर्क यह है कि आंदोलन का आकार जितना बड़ा होगा, उत्तरदायी व्यक्तियों पर उतना ही अधिक दबाव डाला जा सकता है। अपनी राजनीतिक संबद्धता से परे, हर किसी को इस आसन्न जलवायु संकट को खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया जाता है, तथा कई लोग इससे संबद्ध भी हुए हैं। यह रणनीतिक दृष्टिकोण पिछले दशकों में जलवायु सक्रियता में मुख्य प्रवृत्तियों के विपरीत है। सड़क विरोधों में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करने के अपने आग्रह में एफएफएफ में मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है।

जर्मनी में विद्यार्थी 2019 की शुरुआत में “भविष्य के लिए छात्र” के रूप एसएफएफ में से सम्मिलित हुए। निम्नलिखित में, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एसएफएफ जलवायु आंदोलन के राजनीतिक चरित्र पर एक व्यवस्थित और वर्ग-आधारित दृष्टिकोण को प्रमुखता से जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यहां हम संक्षेप में एसएफएफ के संक्षिप्त इतिहास का सारांश देंगे, इसके बाद जलवायु राजनीति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भिन्नता का विश्लेषण किया जाएगा। अंत में, मानवता के सामने आने वाले संकट के खिलाफ आंदोलन में अपनी भूमिका व समर्थन प्रदान कर सकते हैं; इस संबंध में कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।

> एफएफएफ की विश्वविद्यालयों पर जीत

फ्राइडे फॉर फ्यूचर के तेजी से विकास के बाद 2019 के वसंत में जर्मनी भर के छात्र कार्यकर्ताओं ने उभरते जलवायु आंदोलन में अपने विश्वविद्यालयों को शामिल करने के तरीकों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। शुरुआत से ही इसका लक्ष्य “एक नाउ ! अधिक जलवायु न्याय हेतु, विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन करें!” जैसे

नारों के तहत खुली बैठकों की मेज़बानी करके अधिक से अधिक छात्रों को संगठित करना था। इन प्रत्येक खुली बैठकों ने करीब 300 छात्रों को आकर्षित किया, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि इस बिन्दु पर सार्वजनिक संभाषण में एफएफएफ का पहले ही महत्वपूर्ण प्रभाव था। कुछ महीनों के भीतर, राजनीतिक रूप से विविध, कार्यकर्ताओं और छात्रों के इन समूहों ने पूरे देश में बीस से अधिक विश्वविद्यालयों में छात्र सभाएं आयोजित की जो अक्सर इन विश्वविद्यालयों ने वर्षों में देखी सबसे बड़ी राजनीतिक बैठकें थी। यह सफलता इस तेजी से कैसे आई?

चूंकि पूर्व जर्मन शहर लिपजिग में उपयोग किए जाने वाले तरीकों को कई अन्य शहरों में अपनाया गया है, इसलिए हम उन्हें एक प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में यहां उपयोग करेंगे। अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचने के लिए संघ के आयोजन में विकसित अवधारणाओं को लिपजिग कार्यकर्ताओं द्वारा लागू किया गया था। एक अधिकारिक महासभा को लागू करने के लिए, यह लक्ष्य रखा गया कि चाहे जैसे हो अन्य छात्रों तक इस व्यवस्थित साधारण महासभा की जानकारी पहुंचे तथा वे सक्रिय रूप से तय करें कि इसका समर्थन करना है या नहीं। इस प्रकार, एक याचिका परिचालित की गई, जिसने एफएफएफ से संबद्धता व्यक्त की तथा एक सामान्य सभा की मांग की ताकि सतत विश्वविद्यालय एवं शहर की ओर कदम उठाए जा सकें। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने याचिका को सभी संकायों और मुख्य परिसर में व्यवस्थित रूप से फैलाया और छात्रों को व्याख्यानों में अक्सर शिक्षण स्टाफ के समर्थन से इसकी जानकारी दी। एक सप्ताह के भीतर 2500 छात्रों ने याचिका पर हस्ताक्षर किये थे।

सभा में, विश्वविद्यालय एवं संघों के वक्ताओं द्वारा परिस्थितिकी और सामाजिक राजनीति के परस्पर संबंध पर जोर दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने मांगों की एक सूची पर सहमति व्यक्त की। बर्लिन जैसे अन्य शहरों में, मांगें न केवल विश्वविद्यालयों अपितु संघों एवं शहरी राजनीति पर भी लक्षित थी। संघों को “जलवायु धरनों” के लिए आमंत्रित किया गया था तथा बर्लिन सीनेट से यह आग्रह किया गया था कि वे अधिक विस्तारपूर्ण तथा मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की स्थापना की दिशा में कदम उठाएं।

> राष्ट्रव्यापी विनिमय और तरीकों का सामान्यीकरण

लिपजिग और बर्लिन जैसे शहरों में कार्यकर्ताओं द्वारा लागे किए गए तरीकों को विस्तार देने के लिए, जून 2019 में एफएफएफ कार्यकर्ताओं की एक राष्ट्रव्यापी सभा आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक शहरों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विश्वविद्यालयों में गतिशीलता हेतु सफल दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए तथा उन पर चर्चाएं हुई। अमरीकी संघ की आयोजक और लेखक जेन मैकएल्वे को कार्यकर्ताओं को अनुभूत आयोजन विधियों को सिखाने तथा जलवायु आंदोलन के अगले चरणों पर चर्चा करने हेतु आमंत्रित किया गया था। यह सभा छात्र जलवायु कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय समन्वयन में प्रथम निर्माण खंड थी। इन तरीकों से लैस, कार्यकर्ताओं ने ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के अंत तक चौदह शहरों में सामान्य सभाओं का आयोजन किया।

समावर्ती रूप से, छात्रों ने एफएफएफ द्वारा शुरू की गई यूनियनों के साथ संवादों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होना

शुरू कर दिया। इस तिथि तक जर्मनी में लगभग हर प्रमुख संघ ने राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर एफएफएफ और एफएफएफ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। यूनियनों और सामाजिक आंदोलनों के ऐसे अभिसरण पिछले वर्षों में जर्मनी में दुर्लभ रहे हैं। कुछ संघ, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले, अपने कई अतिव्यापी हितों के कारण जलवायु आंदोलन के स्वाभाविक सहयोगी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, एफएफएफ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद, सर्विस वर्कर यूनियन के प्रमुख फ्रैंक बसीरस्के, ने सार्वजनिक रूप से Ver.di सदस्यों को 20 सितंबर 2019 को वैश्विक हड़ताल दिवस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन यहां तक कि आई जी मेटाल जैसे शक्तिशाही संघ भी, अर्थव्यवस्था के कार्बन-संघन औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए तथा इस तथ्य के बावजूद कि उनके कार्यस्थल अर्थव्यवस्था के पारिस्थितिक पुनर्गठन से सबसे अधिक प्रभावित होंगे, वे एफएफएफ के साथ वार्ता में सम्मिलित हुए। जलवायु आंदोलन को संघों के साथ वास्तविक सहयोग की संभावनाएं बनाने के लिए कई सवालों के जवाब देने होंगे। बावजूद इसके, ये सम्मिलन वास्तविक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन बनाने के लिए पर्याप्त रूप से बड़े पैमाने पर जलवायु आंदोलन की ओर ले जा सकते हैं, जैसा कि हम निम्नलिखित तर्कों में देखेंगे।

> एक नए प्रकार का जलवायु आंदोलन

स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर की अब तक की दिशा के उपरोक्त चित्रण से हम कुछ विशेषताओं को निकाल सकते हैं, जिन्हें यदि व्यापक जलवायु न्याय आंदोलन में एक साथ रखा जाए तो निश्चित ही वे यदि अद्वितीय नहीं तो दुर्लभ अवश्य हैं।

सर्वप्रथम, एफएफएफ का लक्ष्य जलवायु संकट के खिलाफ संघर्ष करना है जो समाज के अधिकांश लोगों द्वारा किया गया संघर्ष है। इस संबंध में यह अन्य कार्यवाही (कम प्रासंगिक नहीं) रूपों भिन्न है, जो यह मांग करती है कि प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण शारीरिक और कानूनी जोखिमों को स्वीकार करना पड़ेगा—जैसे सतही खानों या जंगलों पर कब्जा करना। कार्यवाही के यह प्रारूप अनिवार्य रूप से पहले से कुछ हद तक कटटरपंथी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से आकर्षित करते हैं, जिन्हें जेन मैकएल्वे ने सीमित परिवेश में “चयनित कार्यकर्ताओं” के रूप में संबोधित किया है। इसके विपरीत, फ्राइडे फॉर फ्यूचर ने अपनी साप्ताहिक “हड़तालों” में समाज की अधिकांश जनसंख्या के लिए एक स्थान प्रदान करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर बल दिया है। इस भावना को एफएफएफ साझा करता है। बहुमत दृष्टिकोण से छात्रों के बीच कार्य करने तथा अन्य कर्ताओं के साथ गठजोड़ निर्माण दोनों के ही निहितार्थ हैं। विश्वविद्यालयों के भीतर, एफएफएफ का लक्ष्य स्वयं को पहले से ही जलवायु सक्रियता में शामिल छोटे आयोजनों तक ही सीमित रखना नहीं है, अपितु जलवायु संकट के मुद्दों पर संपूर्ण छात्र निकाय का सामना करना है। इसका परिणाम पिछले महीनों में युवाओं का भारी संख्या में हुआ राजनीतिकरण है। इस रणनीति ने मूल कार्यकर्ताओं के बीच कौशल और आत्मविश्वास का तेजी से विकास किया है; यहां तक कि जो पहले कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे वे भी अब सैकड़ों छात्रों के सामने बोलते हैं⁴, प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं तथा संघीय वार्ताओं में आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन कार्यकर्ताओं में अधिकांश युवा महिलाएं हैं।

दूसरा, जब स्कूलों और विश्वविद्यालयों के परे आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक बनाने की बात आती है, तो कम-से-कम व्यवहार में एसएफएफ (साथ ही एफएफएफ के हिस्से) एक वर्ग-विशिष्ट अवधारणा के रूप में "बहुसंख्यक" वास्तविकता में क्या चाहते हैं, को साझा करता है। एफएफएफ के प्रमुख चेहरों ने आंदोलन के लिए अधिक समर्थन जुटाने हेतु ज्यादातर राजनीतिक दलों, व्यवसायों और यहां तक कि बैंकों से संपर्क किया है, और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ जैसे संस्थानों में मजबूत विश्वास व्यक्त किया है। कई एसएफएफ कार्यकर्ता इन प्रवृत्तियों के प्रति आलोचनात्मक हैं। आंदोलन में आगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने के उनके प्रयास में, विशिष्ट कार्यबलों की स्थापना की गई, जो कि बहुसंख्यक मजदूरों को संगठित करने के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए समर्पित थे। यह केवल आपसी संबद्धता को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है, बल्कि धरनों में उन संभावित सहयोगियों का साथ हासिल करने लिए होता है ताकि सामाजिक एवं पारिस्थितिकी सुधार प्राप्त करने हेतु आर्थिक सौदेबाजी की शक्ति को काम में लाया जा सके। ट्रेड यूनियनों के प्रति यह दृष्टिकोण न केवल संगठित श्रमिकों की आर्थिक शक्ति की स्वीकृति से प्रेरित है, बल्कि विशेष रूप से उद्योगों की कार्बन-सघन शाखाओं में, वैश्विक जलवायु और श्रमिकों के हितों के बीच कथित विरोधाभास को दूर करने का एक प्रयास भी है। राजनीतिक केंद्र तथा दक्षिण पंथ अथकरूप से और अक्सर सफलतापूर्वक इस कथात्मक को सुदृढ़ करते हैं, विशेषकर उन लोगों के बीच, उस दुखती रंग को छोड़कर जो अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन से प्रभावित हैं, जैसा कि पूर्वी जर्मनी के पूर्व-खनन क्षेत्र लुसटिया में देखने को मिलता है। जबकि मूलभूत सवाल आज भी खुले हैं, एसएफएफ कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियनों के बीच हाल के संवादों से यह जाहिर हुआ है कि वैश्विक जवायु तथा बस चालकों के साथ-साथ इस्पात श्रमिकों के हित अक्सर संरेखित होते हैं।

> निकट भविष्य के लिए परिप्रेक्ष्य

भविष्य के सामरिक दृष्टिकोण के लिए छात्रों की ये दो विशेषताएं—जलवायु आंदोलन में समाज बहुसंख्यकों की सक्रिय भागीदारी और इस बहुमत के संगठन के लिए एक वर्ग-विशिष्ट दृष्टिकोण हेतु लक्ष्य ने ऐसे कार्यों के प्रारूपों के दरवाजे खोले हैं, जिसमें बहुसंख्यकों की स्व-गतिविधि के माध्यम से अधिक धारणीय समाज के निर्माण हेतु संरचनात्मक परिवर्तन को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जर्मनी में, सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक आगामी राष्ट्रव्यापी सामूहिक सौदेबाजी जलवायु कार्यकर्ताओं, यूनियनों और समुदायों के बीच एक गठबंधन बनाने का अवसर प्रदान कर सकती है। जिस तरह स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में, सार्वजनिक परिवहन न केवल नृविज्ञान जलवायु परिवर्तन पर एक छोटा सा प्रभाव डालता है, बल्कि यह पूरे शहर और क्षेत्रों के सामाजिक प्रजनन और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। इसके आधार पर एसएफएफ और आस-पड़ोस और विश्वविद्यालयों में खुले समूहों का आयोजन कर सकता है, जो कर्मचारियों के साथ संबद्धता से खड़े होंगे। संभावित रूप से हड़ताल में उनका समर्थन करेंगे आदि। सामाजिक आंदोलनों जैसे एफएफएफ/एसएफएफ द्वारा बाहरी राजनैतिक दबाव, सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया का राजनीतिकरण कर सकता है तथा समाज के लिए इन वार्ताओं के दूरगामी महत्व को प्रकट कर सकता है। यूनियनों और जन जलवायु आंदोलन का एक संयुक्त

प्रयास सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति और उच्च वेतन प्राप्त करा सकता है, जो उन लोगों के जीवन स्तरों में सुधार लाएगा जो सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं वि-वस्तुकरण के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं और कारों जैसे व्यक्तिगत परिवहन को त्याग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर, कार्बन-उत्सर्जन में कमी करते हैं।

फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कार्यकर्ताओं के बीच प्रमुख नायकत्व-रणनीति जैसे-आसन्न जलवायु संकट को हल करने हेतु राजनीतिक दलों, व्यवसायों और राज्य संस्थानों में विश्वास पैदा करना, एक तरह से मृत-अंत तक पहुंच गई है। जबकि यह नीति जर्मनी में ग्रीन-पार्टी के तेजी से उदय में खेती गई है और महीनों तक सार्वजनिक संभाषण में जलवायु परिवर्तन के कारण हावी रही है, बावजूद इसके, यह जर्मन अर्थव्यवस्था और समाज में बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक पुनर्गठन की दिशा में कोई ठोस कार्यों का परिणाम नहीं दे पायी है। पारिस्थितिकी वर्ग राजनीति के प्रति अभिविन्यास, साथ ही संघों द्वारा पारिस्थितिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए जलवायु आंदोलन हेतु लड़ाई ही शायद इस सामरिक गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता दे सकती है।

> हमसे जुड़ें !

हमारा विश्वास है, कि विश्वविद्यालय व्यापक, वर्ग-आधारित और वैश्विक जलवायु आंदोलन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए एक संगठित छात्र निकाय के साथ-साथ आलोचनात्मक वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी जो सक्रिय रूप से संगठनात्मक प्रक्रिया को सहयोग प्रदान करें तथा जलवायु संकट के कारणों और संभावित समाधानों की गहन समझ के लिए सैद्धान्तिक योगदान प्रदान करें। ये केवल तकनीकी या प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित मुद्दों नहीं हैं, अकेले धारणीय प्रौद्योगिकी मानव जनित जलवायु परिवर्तन को नहीं रोक पाएगी। इसके लिए हमारी समस्त अर्थव्यवस्था और समाज का पुनर्गठन करना होगा। इसके किस रूप में व क्या परिणाम होंगे, वे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब सामाजिक वैज्ञानिकों को देना होगा।

अधिक विशिष्ट रूप में, छात्र, जलवायु आंदोलनों में संगठित हों। वैज्ञानिक अपने अनुसंधान कार्यों को मानवता के सामने खड़े प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने हेतु उपयोग करें तथा अपने परिणामों को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाएं। अंत में, आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे साथ काम करें। वर्तमान में, एसएफएफ एक सप्ताह की छात्र-जलवायु धरने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। एक सप्ताह के लिए हम विश्वविद्यालयों को जनता के लिए खोलकर, जलवायु संकट और इसके संभावित समाधानों के बारे में व्याख्यान और चर्चा आयोजित कर सकते हैं। जर्मन रेक्टर सम्मेलन ने विश्वविद्यालयों की भूमिका को — "लोकतांत्रिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिभाषित किया है जो समाज की प्रमुख चुनौतियों के बारे में उत्पादक चर्चा में योगदान करते हैं।" दुनिया की वर्तमान स्थिति और निकट भविष्य के प्रकाश में, हम सोचते हैं, इस जिम्मेदारी को पूरा करने का समय आ गया है। ■

सभी पत्राचार जूलिया केसर को <julaidakaiser@gmail.com>
और जैस्पर स्टेंज को <jasper.stange@hotmail.de>
पर प्रेषित करें।

> सेनेगल में निजी कैथोलिक शिक्षा

मुस्तफा तांबा, शेख अन्ता डियोप ऑफ डकार विश्वविद्यालय, सेनेगल द्वारा

सेनेगल में निजी कैथोलिक शिक्षा आज महत्वपूर्ण बनी हुई है। 1816 में, औपनिवेशिक प्रशासन ने फ्रेंच शिक्षण का काम चर्च को सौंपा, विशेष रूप से सभाओं को जैसे कि क्लूनी के सेंट जोसेफ की ननों को, प्लोरमेल के ब्रदर्स को, होली स्पिरिट की मिशनरियों को, कैस्ट्रेस के इमेकुलेट कंसेप्शन की ननों को और मैरी के होली हार्ट की डॉटर्स को। बीसवीं सदी में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कैथोलिक शिक्षा का विकास 1946 से 1960 तक मोंसिगर मारसेल लेफेब्रे, विकर एपोस्टोलिक के प्रोत्साहन के तहत एक निर्णायक कदम लेते हुये आगे बढ़ा। अन्य सभायें जैसे सेंट गेब्रियल के ब्रदर्स, सेक्रेड हार्ट के ब्रदर्स, यूसुलीन सिस्टर्स, एंगर्स के सेंट चार्ल्स की सिस्टर्स, और मेरिस्टस स्थापित हुयी।

1960 में आजादी के बाद, चर्च ने 1970 में शिक्षण का काम कैथोलिक शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया। 1976 में, एक राष्ट्रीय समन्वय संरचना को स्थापित किया गया जिसे आज एक राष्ट्रीय सचिवालय में बदल दिया है। 2003 से, निजी कैथोलिक

शिक्षा का एक संघ के रूप में गठन कर दिया गया है जिसे “नेशनल ऑफिस ऑफ कैथोलिक एजुकेशन ऑफ सेनेगल” कहा जाता है।

हालांकि, निजी कैथोलिक शिक्षा को धर्मप्रदेश निदेशालयों के निर्माण के माध्यम से विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। यहां पर सात धर्मप्रदेश हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अपनी डाइरेक्ट यानि कि “डियोसेन डाइरेक्टोरेट ऑफ कैथोलिक एजुकेशन” है। बिशप के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा, धर्मप्रदेश निदेशक एक धर्मप्रदेश में सभी कैथोलिक विद्यालयों के लिये जिम्मेदार हैं।

यह अध्ययन के लिये मात्रात्मक आंकड़ें प्राप्त करने के लिये, हमने कैथोलिक निजी शिक्षा के लिये जिम्मेदार लोगों की ओर रुख किया, विशेष रूप से डकार के आर्कडियोसेज के धर्मप्रदेश निदेशालय के प्रमुख और “नेशनल ऑफिस ऑफ कैथोलिक एजुकेशन ऑफ सेनेगल” के सचिव की ओर। दोनों कार्यालय सेंट पीटर्स चर्च के सामने एसणआईएनसीएणपीए बाओब्स डकार जिले में स्थित हैं, जहां हमने

हमें उपलब्ध कराये गये अभिलेखागारों का प्रयोग करते हुए अभिलेखीय सर्वेक्षण किया।

अध्ययन के परिणामों को क्रॉस. टेब्युलेशन या डबल. एंट्री सोर्टिंग तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1 से पता चलता है कि डकार के आर्कडियोसेज अकेले ही कुल विद्यालयों के करीब 50 प्रतिशत विद्यालयों से बना है। यह दो एपोस्टोलिक क्षेत्रों से बना है, पहले में ला प्लेट्यू, ग्रांड डकार.योफ और लेस नियास और दूसरे में साइन और पेटिटकॉट शामिल है। कुल मिलाकर, आर्कडियोसेज 41 पैरिशोज से बना है। थ्रीइस और जिउंगचार के धर्मप्रदेश क्रमशः 16 प्रतिशत और 11 प्रतिशत संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोल्डा और टेंबोकोडा के धर्मप्रदेशों में कम संस्थान हैं।

डकार के आर्कडियोसेज कुल छात्रों की आबादी के 57 प्रतिशत के साथ अग्रणी हैं। डिडेक के आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्र, विशेषतः डकार और इसके उपनगरों में

तालिका 1 : 2018–19 में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर कैथोलिक विद्यालयों का वितरण

डिओसिज	स्तर					
	प्री-स्कूल	प्राथमिक	माध्यमिक	सैकेण्डरी	कुल	%
डकार	58	54	23	14	149	48.5%
थिस	22	24	3	1	50	16%
केऑलक	12	13	2	1	28	9%
जिउंगचार	11	15	8	1	35	11%
सेंट लुई	8	6	3	1	18	6%
कोल्डा	6	6	3	1	16	5%
तेंबोकोडा	4	5	1	1	11	4.5%
कुल	121	123	43	20	307	100%

स्त्रोत : सेनेगल की कैथोलिक शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यालय, मार्च 2019।

तालिका 2 : 2018–19 में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर निजी कैथोलिक विद्यालयों में छात्रों का वितरण

डिओसिज	स्तर					
	प्री-स्कूल	प्राथमिक	माध्यमिक	सैकेण्डरी	कुल	%
डकार	6,442	36,304	16,467	6,696	65,909	57%
थिस	2,268	5,735	1,856	491	10,350	9%
केऑलक	1,983	11,080	2,665	836	16,564	14%
जिरंगचार	1,441	5,326	733	248	7,748	7%
सेंट लुई	970	3,519	1,212	262	5,963	5%
कोल्डा	656	3,465	958	245	5,324	4.5%
तैम्बोकोड़ा	417	2,630	479	143	3,669	3.5%
कुल	14,177	68,059	24,370	8,921	115,527	100%

स्त्रोत : सेनेगल की कैथोलिक शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यालय, मार्च 2019।

प्राथमिक शिक्षा में कुल 25,360 विद्यार्थी हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों (पेटिटकॉट और साइन) में 10,944 विद्यार्थी हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी, आर्कडियोसेज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमशः 14002 और 2456 विद्यार्थियों के साथ अपनी रैंक बनाये रखता है। माध्यमिक शिक्षा में, निजी क्षेत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के 75 प्रतिशत पर ध्यान देते हुए आर्कडियोसेज प्रथम बना हुआ है। 2018.19 में 1059 विद्यार्थियों के कुल दाखिले के साथ द कॉलेज सैकेकोयर सबसे बड़ा निजी कैथोलिक विद्यालय बना हुआ है।

इसके अलावा, डकर के आर्कडियोसेज के डिडेक के अनुसार, सभी स्तरों पर

कैथोलिक आस्था की तुलना में मुस्लिम आस्था के विद्यार्थी अधिक हैं। उदाहरण के लिये, प्राथमिक स्तर पर 2018.19 में, 72 प्रतिशत छात्र मुस्लिम हैं, 26 प्रतिशत कैथोलिक हैं, और 2 प्रतिशत अन्य आस्था के छात्र हैं। यह सेनेगलवासियों के बीच में अंतर्धार्मिक संबंधों का प्रमाण है।

निष्कर्ष के रूप में, यह कहा जा सकता है कि निजी कैथोलिक शिक्षा का प्रसार ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से आगे रहा है। उन्नीसवीं सदी में, यह पहले से ही सेंट लुइस, गोरे, डकर और रूफीस्क की चार नगरपालिकाओं में मौजूद था। और यहां आज पूरे देश में पाया जा सकता है,

हालांकि अधिकांश बुनियादी ढांचा और विद्यार्थी नामांकन डकर के आर्कडियोसेज में स्थित है, जिसमें डकर, पेटिटकॉट और साइन के सभी पेरिशेज शामिल हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि निजी कैथोलिक शिक्षा क्षेत्र में अधिकतर छात्र कैथोलिकों की तुलना में मुस्लिम हैं। ■

सभी पत्राचार मुस्तफा तांबा को
<moustapha.tamba@ucad.edu.sn> पर प्रेषित करें।

> सेनेगलीज विद्यालय व्यवस्था का समाजशास्त्र

सौलेमन गोमिस, शेख अन्ता डियोप ऑफ डकार विश्वविद्यालय, सेनेगल द्वारा



अर्बु द्वारा चित्रण

सेनेगल शिक्षा व्यवस्था के समाजशास्त्रीय आयाम पर चिंतन करना विस्तृत और व्यवस्थित विश्लेषण का एक अवसर है। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक युग से वर्तमान समय तक इसकी संरचना और प्रकार्यों की ताकतों और कमजोरियों को दिखाना और इसकी संभावनाओं की पहचान करना है। यहां यह ध्यान देना सही

होगा कि सेनेगल लंबी शैक्षिक परंपरा वाले अफ्रीका के कुछ देशों में से एक है। वास्तव में, यूरोप के संपर्क में आने से बहुत पहले, सेनेगल ने काले महाद्वीप के इस्लामीकरण के युग में कुरानिक शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की मेजबानी की थी।

एल हदजी मैलिक साई, शेख अहमदौ बाम्बा, और शेख इब्रा निआसा जैसे प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्तियों ने सेनेगल और उसके बाहर कुरानिक शिक्षा को फैलाने में मदद की। अरबी में स्कूली शिक्षा की इस परंपरा ने फ्रांसीसी आक्रमण के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, फ्रांसीसी उपनिवेशक औपनिवेशिक स्कूली व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये वास्तव में सेनेगलवासियों की अरबी बोलने की परंपरा का लाभ उठाने में कामयाब रहे। 1960 में, जब सेनेगल ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उपनिवेशवादियों से विरासत में मिली फ्रेंच-भाषा स्कूली व्यवस्था को राष्ट्र-राज्य निर्माण के एक उपकरण के रूप में बना रहा। नये अधिकारियों द्वारा फ्रेंच को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में बनाये रखा गया है।

हालांकि, आज भी आवर्ती बहस जारी है कि क्या सेनेगलवासियों ने अपनी शैक्षिक व्यवस्था का पर्याप्त स्वामित्व ले लिया है। सेनेगलवासी खुद को अभी भी इस स्कूली व्यवस्था के उपयोगकर्ता मात्र के रूप में देखते हैं। स्कूल में द्विभाषीय शिक्षा को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय भाषाओं को आरंभ करने में समस्या होना इसको प्रमाणित करता है।

> सेनेगल में स्कूली व्यवस्था की उत्पत्ति

काले अफ्रीका का पहला फ्रेंच-भाषा स्कूल 1817 में सेंट लुइस, सेनेगल में एक युवा 27-वर्षीय फ्रांसीसी शिक्षक जीन डर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। तब से, और अधिक स्कूल स्थापित किये गये, वे पहले

तटीय कस्बों और शहरों में और फिर अंतर्देशीय समुदायों में धीरे धीरे फैल गये। देश के बाकी हिस्सों में स्कूलों का विकास औपनिवेशवाद के द्वारा वाणिज्यिक और राजनीतिक आदान-प्रदानों को सहूलियत देने के लिये तेजी से हुआ।

अफ्रीका के अधिकांश पूर्व उपनिवेशों की तरह, सेनेगल ने 1960 में अपनी स्वतंत्रता तक पाठ्यक्रम का फ्रांसीसीकरण, फिर 1970 के दशक से इसके अफ्रीकीकरण, और 1990 में इसके राष्ट्रीयकरण को अनुभव किया। हालांकि, समय के साथ इस उद्विकास में, सेनेगलीय स्कूली व्यवस्था संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक रूप से पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के आधार पर ही ढली रही। छः और सोलह वर्ष की आयु के बीच के सभी लड़कों और लड़कियों के लिये शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है।

यूनेस्को के मानकों का पालन करते हुये, प्रत्येक देश की जनसंख्या की 2 प्रतिशत जनसंख्या को उच्च शिक्षा के स्तर तक पहुंचना चाहिये। यह देखते हुये कि सेनेगल की वर्तमान जनसंख्या अनुमानित 15 मिलियन है, देश में करीब 300,000 विद्यार्थी उच्च-शिक्षा में होने चाहिये। परंतु वास्तविक संख्या, निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों दोनों में, 150,000 विद्यार्थी है। एक अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा पाठ्यक्रम और सेनेगल के लोगों की उम्मीदों के बीच में बेमेलता है।

> ताकतें और कमजोरियां

सेनेगल की सार्वजनिक स्कूली व्यवस्था

विज्ञान, चिकित्सा, कानून, साहित्य, और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में विश्व के ऐतिहासिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये सफलता का एक मॉडल माना जाता है, जैसे कि साहित्य में लियोपोल्ड सेडर सेनघोर और इतिहास और भौतिकी में शेख अन्ता डियोप जिनके कार्यों ने मानवता के आधुनिक इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। सेनेगल की स्कूली व्यवस्था की एक ताकत शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में निहित है। राज्य की अपने स्कूली और उच्च शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्धता और दृढसंकल्प भी उल्लेखनीय है, और वैसा ही परिवारों की भागीदारी और निवेश भी है। लोग अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा के वित्तपोषण में योगदान देने के लिये स्वतंत्र अनेक विभिन्न सीमाओं को।

हालांकि, यह भी ध्यान देना चाहिये कि ना तो राज्य, और ना ही शिक्षक, ना शिक्षक यूनियन, ना तकनीकी और वित्तीय भागीदार अभिभावकों को स्कूल के पाठ्यक्रम विकास में भागीदार बनाने पर विचार कर रहे हैं। आबादी को स्कूली शिक्षा व्यवस्था और इसकी सेवाओं का सिर्फ उपभोक्ता बना दिया है।

सेनेगल शिक्षा व्यवस्था राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, वित्तीय, और मानवीय स्तर पर अनेक विभिन्न सीमाओं को अनुभव करती है। उदाहरण के लिये, सेनेगल शिक्षा नीति के संदर्भ में अपने लक्ष्य और अभिविन्यास को परिभाषित करने में यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है: यह विश्व बैंक और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे भागीदारों की तकनीकी और वित्तीय बाधाओं के अधीन है।

मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से, हम देखते हैं कि स्कूली संस्थायें सेनेगल में लंबी उपस्थिति और पहले के समय से ही अनिवार्य प्रकृति के बावजूद लोगों की मानसिकताओं में अभी भी पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं हो पायी हैं। स्कूलों को सेनेगलवासियों के द्वारा अभी भी फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से विरासत में मिले एक उपकरण के रूप में देखा जाता है जो पूर्ण रूप से उनका खुद का नहीं बन सकता है।

परियोजना के स्तर पर, शिक्षण की सामग्री कुछ विषयों में मामूली बदलाव के साथ हमेशा से फ्रांसीसी पाठ्यक्रम मॉडल से जुड़ी रही है। नया पाठ्यक्रम, यद्यपि देश के नागरिकों द्वारा डिजाइन और पढाया जाने वाला, सही मायने में स्थानीय सांस्कृतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता बल्कि इसकी जगह औपनिवेशिक प्रतिमानों को पुनर्त्पादित करता है।

सामग्री के स्तर पर, सेनेगल की स्कूली व्यवस्था गहराई से संसाधनों की कमी से ग्रस्त है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, सभी स्तरों पर अस्थायी आश्रयों में कक्षाएँ लगाना, आज भी मौजूद है।

इन असंगत कठिनाईयों के बावजूद, यह तर्क दिया जा सकता है कि सेनेगल में एक अच्छी स्कूली व्यवस्था है। ■

सभी पत्राचार सोलीमेन गोमिस को

<Souleymane.gomis@ucad.edu.sn> पर प्रेषित करें।

> सेनेगल में फ्रेंको-अरब शिक्षा में सामरिक समायोजन

एल हदजी मैलिक साइ कमारा, शेख अन्ता डियोप ऑफ डकार विश्वविद्यालय, सेनेगल द्वारा



सेनेगल में प्राथमिक शिक्षा अरबी एवं फ्रेंच में साक्षरता प्राप्त करने पर फोकस करती है।
श्रेय : ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एजुकेशन/
फिल्कर। कुछ अधिकार सुरक्षित।

इस्लाम की शुरुआत के साथ, सेनेगल में अधिकाधिक घर अरबी भाषा से परिचित हो गये। वास्तव में, अरबी भाषा जनसंख्या के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसमें 95 प्रतिशत मुस्लिम हैं। सेनेगलीय मुस्लिमों के बीच अरबी भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया जाना प्रतीत होता है क्योंकि यह वह भाषा भी है जिसके माध्यम से कुरान का खुलासा हुआ। वास्तव में, कुरान के गहन ज्ञान वाले व्यक्ति को शिक्षित और एक अच्छा मुस्लिम माना जाता है। हालांकि, शुरुआत से ही उपनिवेशवाद ने फ्रांसीसी भाषा के शिक्षण पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थोपी।

दो शिक्षा प्रणालियों के मध्य सह-अस्तित्व बहुत मुश्किल साबित हुआ। आबादी के एक बड़े हिस्से की जरूरतों को पूरा करने के लिये, निजी और सार्वजनिक फ्रेंको-अरब स्कूल फ्रांसीसी और अरबी दोनों में दोहरी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।

इस्लाम वास्तव में सेनेगल के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है क्योंकि यह उनकी सामाजिक उत्पत्ति, शिक्षा के स्तर, और सांस्कृतिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि की परवाह किये बिना लोगों के जीवन की नस्लीय और क्षेत्रीय विशिष्टताओं और संरचनाओं तक खुले तौर पर पहुंचता है।

साहित्य की समीक्षा पर आधारित, यह लेख उद्धरित करता है कि कैसे सेनेगल के लोग फ्रेंको-अरब शिक्षा को औपनिवेशिक प्रशासन की कमियों से बचने के एक अवसर के रूप में उपयोग करने में सक्षम रहें हैं।

> फ्रेंको-अरब स्कूलों में सीखने के मॉडल

फ्रेंको-अरब स्कूलों की कम से कम दो श्रेणियों की पहचान की जा सकती है: वे जो इस्लामिक पाठ्यक्रम (कुरान, फिक, सुन्नाह, आदि) के मजबूत प्रभुत्व की विशेषता वाले और वे जो फ्रांसीसी और

अरबी इस्लामिक शिक्षा के बीच ज्यादा और कम संतुलन की विशेषता रखते हैं। आज, फ्रेंको-अरब स्कूलों के मालिकों ने प्री-स्कूली और प्रारंभिक शिक्षा में गहनता से निवेश किया है।

फ्रेंको-अरब स्कूलों की पहली श्रेणी में, प्राथमिक स्कूल के पहले दो वर्षों के दौरान शिक्षा अरबी में साक्षरता प्राप्त करने और कुरान और हदीसे सीखने पर केंद्रित हैं। फ्रांसीसी कक्षाएँ वर्णमाला के परिचय और संचार कौशल विकसित करने तक सीमित हैं। इन दो वर्षों में, विद्यार्थियों से कुरान से अधिक से अधिक सूरतें याद करने की अपेक्षा की जाती है। परंतु तीसरे साल से, उनसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रमों को "पकड़ने" की उम्मीद की जाती है। उनकी प्राथमिक शिक्षा के छठे और अंतिम वर्ष में, शिक्षार्थियों को दोनों भाषाओं में अपनी बुनियादी स्कूल पास करने की योग्यता (नेशनल कुरिकुलम एंड सर्टिफिकेट ऑफ कंपलीशन ऑफ द अरब इस्लामिक करिकुलम) हासिल करने के लिये फ्रांसीसी और अरबी में परीक्षा देनी होती है।

दूसरी श्रेणी के फ्रेंको-अरब स्कूल धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक शिक्षा और अरब मुस्लिम शिक्षा के बीच एक संतुलन बनाते हैं। अल फलाक एंड जमातौ इबादौ रहमाने (जेआइआर) आंदोलनों के निर्माण ने फ्रेंको-अरब शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक क्षेत्र जो राज्य द्वारा पूर्ण रूप से उपेक्षित है जिसने फ्रांसीसी भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में चुना था।

अरब-मुस्लिम शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक शिक्षा को संयोजित करने या कम से कम संतुलित करने का यह विकल्प मुख्य रूप से ऐसे भविष्य के नागरिकों को बनाने या प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से था जो गहराई से (इस्लामिक) धार्मिक मूल्यों से निहित हों परंतु वो सब हासिल करने के क्षमता के साथ हों जो सार्वजनिक स्कूल में प्रशिक्षित होने वालों को जाननी चाहिये। जेआइआर आंदोलन के द्वारा निर्मित द बिलाल कुरानिक स्कूल¹ ने उदाहरण के

लिये इस व्यवस्था का विकल्प चुना। परंतु इस स्कूल के अलावा, जो केवल प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है, जेआइआर ने एक माध्यमिक विद्यालय बनाया था, जो कि भले ही बिलाल स्कूल से स्नातक विद्यार्थियों को प्राप्त करने के लिये था, लेकिन उसको उन माता पिता की स्वीकृति नहीं मिल सकी जो अपने बच्चों को धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक शिक्षा वाले पाठ्यक्रम में आगे पढ़ाना चाहते थे। जेआइआर स्कूलों में, प्रत्येक कक्षा में सभी विषयों के लिये दो शिक्षक होते हैं, अर्थात् एक फ्रेंच बोलने वाला शिक्षक और एक अरबी बोलने वाला शिक्षक। इसके अलावा, जेआइआर कई संस्थानों को शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम अध्ययन में सहायता करता है। वास्तव में, अल हदजी ओमार टॉल स्कूल, अरब-इस्लामिक पाठ्यक्रम ने बड़े पैमाने पर धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक शिक्षा पाठ्यक्रम को पीछे छोड़ दिया। यद्यपि कुछ अभिभावक अरब इस्लामिक शिक्षा का पक्ष लेते हैं, लेकिन इस मार्ग का अनुसरण विद्यार्थी के लिये कई मामलों में अपवर्जन का एक रूप है। फिर भी यह इंगित किया जाना चाहिये कि चूंकि द इकोल नोरमेल सुपरियर (बदला हुआ नाम फास्टेफ²) अरबी में स्नातकों को प्रशिक्षण देता है, इसलिये अब अरबी के शिक्षकों और अन्य शिक्षकों में कोई अंतर नहीं रह गया है: सभी को समान वेतन मिलता है (थीयर्नो का, एलियने डियोप और जिम ड्रेम, 2013)।

> फ्रेंको-अरब स्कूल: दोहरी पहचान का दावा

हालांकि सांस्कृतिक नागरिकता (या नागरिकता के नये प्रकार) का दावा शुरुआत में अरबी बोलने वाले शिक्षित तथाकथित "संभ्रांत-विरोधी" लोगों द्वारा आगे रखा गया, यह अब अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष संस्थानों में प्रशिक्षित नये फ्रेंकोफोन मुस्लिम संभ्रांत लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है (कमारा, 2016)। यह दोहरी पहचान इसके सदस्यों को "दूसरी श्रेणी की नागरिकता" से छुटकारा पाने और राष्ट्रीय नागरिकता से उनका संबंध होने का दावा करने की अनुमति देती है। उनका

दावा, यद्यपि राज्य और उसकी धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं के रूबरू महत्वपूर्ण है, परंतु मौजूदा संस्थागत ढांचे और राज्य के नियंत्रण के बाहर व्यक्त नहीं किया गया है। इसके विपरीत, उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अभिव्यक्ति में, ये मुस्लिम नागरिक "इस्लामिक समाज" की परियोजना के नियमों को अपनाते हैं और पश्चिमीकृत और धर्मनिरपेक्ष संभ्रांत वर्गों के आधिपत्य को चुनौती देते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के समय से ही सेनेगल पर शासन किया है।

> निष्कर्ष

फ्रेंको-अरब स्कूल अब सेनेगल में, खासकर के शहरी क्षेत्रों में, अच्छी तरह से स्थापित हो गये हैं। अरब-इस्लामिक स्कूलों के स्नातक, जो स्वयं को "अरबवादी" (अरबीसैंट्स) कहते हैं, लंबे समय से नौकरियों के अवसरों की कमी से पीड़ित हैं। आज राष्ट्रीय परीक्षाओं (बीएफइएम, बैकालॉरिएट) में अच्छे अंकप्राप्त करने से फ्रेंको-अरब स्कूलों से अंततः सेनेगलीज लोगों की राय और राज्य द्वारा इसे देश के लिये वास्तविक संपत्ति के रूप में देखने तक आ गये हैं। ये कारक, जिनमें से अधिकतर सेनेगलीज इस्लामिक आंदोलन में सक्रिय हैं, फ्रेंको-अरब स्कूल का उपयोग करते हुए कल्पित पहचान के एक प्रमुख साधन के रूप में पश्चिमी परिप्रेक्ष्य को पुनः योग्य बनाने में सक्षम रहा है। ■

1. इस विद्यालय के कुछ पूर्व विद्यार्थी उच्च-स्तरीय सार्वजनिक अधिकारी हैं, जबकि अन्य माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च-शिक्षा शिक्षक हैं।

2. Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation.

सभी पत्राचार एल हदजी मैलिक साइ कमारा को <asmalick20031@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> सेनेगल में धर्मनिरपेक्ष निजी शिक्षा

सांबा डिओफ, शेख अन्ता डियोप ऑफ डकार विश्वविद्यालय, सेनेगल द्वारा



वैश्विक दक्षिण के देशों में शिक्षा व्यवस्था पर अपनी पारंपरिक संरचनाओं की और उपनिवेशकों की दोहरी छाप होती है। यूरोप से निर्यात किया गया मॉडल निश्चित रूप से अफ्रीका में अछूते प्रदेश पर आरंभ नहीं किया गया था। यह दोनों, जिनके पास इसे एक विशिष्ट संदर्भों में अनुकूलन करने का काम था और जिन्हें इसे अपनाना था, के द्वारा एक अनोखे तरीके से विनियोजित किया। जबकि इसका स्थानीय स्तर पर अनुवाद इसके कुछ शुरुआती सिद्धांतों से दगा करता था, इसमें इसके कुछ सिद्धांतों का इस संस्कृति के साथ समायोजन भी शामिल था (चार्लियर, 2002)। इसके परिणामस्वरूप, उपनिवेशकों के द्वारा स्कूल स्थापित मॉडल की परिलक्षित सर्वोच्चता हमें भटका नहीं सकती है: इसे "पश्चिमी", "फ्रेंच", "औपचारिक", या "आधुनिक" के रूप में वर्णित करके, लोग यह दोनों जाहिर करते हैं कि वे इसे विदेशी मानते हैं और इसे सम्मान देने के इच्छुक हैं सिर्फ जहां तक यह उन्हें पश्चिमी आधुनिकता के साथ जुड़ी हुई भौतिक वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस प्रकार के सशर्त समर्थन ने पारंपरिक शिक्षा व्यवस्थाओं के लिये स्थान छोड़ा है: कुरानिक स्कूल, सामाजिक परिवर्तन द्वारा लायी गयी नई परिस्थितियों के साथ लगातार अनुकूलन करते हुए, सेनेगल में हमेशा से सक्रिय रहे हैं। राजकीय विद्यालय, समाजीकरण के इन पुरानी संस्थाओं को उखाड़ने के जगह, जबकि व्यक्तियों और ज्ञान के पदानुक्रमों को स्थापित करने के स्वयं के अपने मानदंडों को शुरू करते हुए भी, उनके पूरक बनकर आये।¹

सेनेगल में, निजी विद्यालयों ने अभिवावकों के मध्य अच्छी साख अर्जित की है, जो उन्हें हड़तालों की अनुपस्थिति के कारण स्थिरता की गारण्टी के रूप में देखते हैं।
श्रेय : एलन लेवाइन/पिलकर। कुछ अधिकार सुरक्षित।

औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता सेनेगल को अपने संबंधों की प्रकृति और स्वरूप को स्पष्ट करने की ओर ले गयी, जिनकी युवा पीढ़ियों की प्रशिक्षण में सम्मिलित विभिन्न निकायों के बीच बनने के लिये परिकल्पना की गयी थी। इस प्रकार, 1963 का संविधान बताता है कि: "गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और सामाजिक है [...]। सभी को शिक्षा का अधिकार है [...]। युवा शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। धार्मिक संस्थाएँ और समुदायों को भी "शिक्षा के साधन के रूप में" मान्यता प्राप्त है [...]। निजी विद्यालय राज्य के नियंत्रण के तहत और उनकी अनुज्ञा के साथ काम कर सकते हैं [...]। धार्मिक संस्थाएँ और समुदाय [...] राज्य के नियंत्रण से मुक्त हैं।" सेनेगल के धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र ने उन धार्मिक संस्थाओं और समुदायों को अपनी देखरेख से हटा दिया जिसे इसने "शिक्षा के साधन के रूप में" माना। दूसरे शब्दों में, शिक्षा की निगरानी सिर्फ एक दूरगामी लक्ष्य के रूप में वर्णित की गयी और इसे धीरे धीरे त्याग दिया गया: 1996 में, क्षेत्रों, नगरपालिकाओं और ग्रामीण समुदायों में क्षमताओं का हस्तांतरण करने वाले कानून को लागू करने वाली आज्ञाप्ति ने आंशिक रूप से शिक्षा की जिम्मेदारी को उपराज्यों के स्तरों पर पुनर्वितरित कर दिया। 2001 के संविधान ने हर निकाय की भूमिका को फिर स्पष्ट किया। राज्य के पास "सार्वजनिक स्कूलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। सभी बच्चों [...] को स्कूल तक पहुँच का अधिकार है [...] सभी राष्ट्रीय संस्थाओं, सार्वजनिक या निजी का अपने सदस्यों को साक्षर बनाने का और राष्ट्रीय भाषाओं में से किसी एक में राष्ट्रीय साक्षरता प्रयासों में भाग लेने का कर्तव्य है।" जहाँ शिक्षा के लिये राज्य की जिम्मेदारी को मजबूती से पुख्ता किया गया, उपराज्यों या निजी निकायों की भूमिका को भी मजबूत किया गया।

> धर्मनिरपेक्ष निजी विद्यालय

निजी गैर-सांप्रदायिक शिक्षा 1980 के दशक में सेनेगल में उभरी। धर्मनिरपेक्ष निजी विद्यालय वैयक्तिक प्रोत्साहकों द्वारा स्थापित किये गये जो उनके प्रशासनिक, वित्तीय और अध्यापन संबंधी प्रबंधन के लिये जिम्मेदार हैं। कैथोलिक निजी विद्यालयों के विपरीत, धर्मनिरपेक्ष निजी विद्यालयों के संचालन की किसी सामान्य प्रबंधन द्वारा निगरानी नहीं की जाती यद्यपि वे जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ प्रायवेट एजुकेशन से जुड़े होते हैं जैसे कि सभी निजी स्कूल होते हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक विभाग है।

2000 के दशक के बाद से, धर्मनिरपेक्ष निजी विद्यालय जनसाधारणीकरण के मामले में एक शानदार सफलता रहे हैं। यद्यपि वे अन्य विद्यालयों की तुलना में अधिक मांग में हैं, वे अक्सर व्यवधानों का सामना करते हैं जो उनके समुचित कामकाज में बाधा डालते हैं। इनमें शिक्षकों का देर से भुगतान, न्यूनतम वेतन से कम वेतन, और परिसरों के किराये का भुगतान न करना शामिल हो सकता है जो कुछ मालिकों को विद्यालय बंद करने की ओर ले जाता है।

> धर्मनिरपेक्ष निजी शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण

यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि निजी विद्यालयों का विस्तार और इस क्षेत्र में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या यह इंगित करती है कि निजी शिक्षा ने डकार में निर्विवाद स्थान प्राप्त किया है। साक्षात्कार में शामिल अभिभावकों ने दावा किया कि निजी क्षेत्र की स्थिरता मुख्य कारणों में से एक थी कि उन्होंने अपने बच्चों को इस क्षेत्र में दाखिला दिलाने का विकल्प चुना। इस तरह की स्थिरता ट्रेड यूनियन

आंदोलनों के द्वारा आयोजित हड़तालों और कार्य बहिष्कार की अनुपस्थिति में प्रतिबिंबित होती है, जो कि किसी प्रकार का व्यवधान है जो आज के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को परेशान करत है। हमारे उत्तरदाताओं में से एक ने कहा कि "कुछ सार्वजनिक विद्यालयों में हिंसा और युवा अपराध के मामलों ने कई अभिभावकों को अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने के लिये प्रेरित किया।" एक अन्य उत्तरदाता, एक 38 वर्षीय ग्रहणी ने माना कि "यदि एक बालक आज निजी शिक्षा में सफल नहीं होता है, यह इसलिये है क्योंकि वह पढ़ाई नहीं करना चाहता है। निजी क्षेत्र में, कोई हड़तालें या शिक्षकों की कमी नहीं है, और अभिभावक बच्चों की शिक्षा में बहुत सारा निवेश करते हैं।" दिलचस्प रूप से, अभिभावक उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के स्थान पर सार्वजनिक विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों की स्थिरता पर अधिक जोर देते हैं। उनके विचार में, सफलता के लिये एक मुख्य कारक विद्यालय की स्थिरता है और निजी विद्यालय में नामांकित किसी भी बच्चे को सफल होना चाहिये।

धर्मनिरपेक्ष निजी शिक्षा के बारे में सार्वजनिक धारणा से पता चलता है कि अधिकांश अभिभावक निजी विद्यालयों को स्थिरता के कारण चुनते हैं। इन विद्यालयों ने अपने अच्छे अंकों के लिये आबादी के बीच एक अच्छी जगह बना ली है, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, उनकी स्थिरता के लिये। ■

1. See Suzie Guth and Éric Lanoue (eds.), (2004). *Écoles publiques, Écoles privées au "Sud": usages pluriels, frontières incertaines, Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*, 3.

सभी पत्राचार सांबा डिओफ को
<bathie78@yahoo.fr> पर प्रेषित करें।

> सेनेगल में धार्मिक नेतृत्व का सामाजिक-नृविज्ञान

मोहम्मद मोस्तफा दिये, चेक अन्टा डिओप विश्वविद्यालय, डाकर, सेनेगल



डाकार, सेनेगल में डिगिनीटी मस्जिद,
श्रेय : वेलेन्टिना बुज/पिलकर।
कुछ अधिकार सुरक्षित।

> धार्मिक नेतृत्व की विरासत

पुरातन से, सेनेगल यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के मध्य विभिन्न प्रकार के विनिमय का केन्द्र रहा है। यह एक सीमा तक सेनेगलवासियों के खुलेपन, उनकी मेहमानवाजी एवं मुसलमान और ईसाई समुदाय के मध्य सहिष्णुता को समझाता है। उनके सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य तीन सांस्कृतिक स्रोतों से व्युत्पन्न होते हैं : सांस्कृतिक परम्पराओं की गहरी जड़े, इस्लाम एवं ईसाई धर्म एवं गणतंत्र पर आधारित पश्चिमी अंदाज की आधुनिकता। इन तीन स्रोतों में से इस्लाम का प्रभाव अत्यधिक निर्णायक है। 95 प्रतिशत सेनेगलवासी मुसलमान हैं एवं ज्यादातर धार्मिक भाईचारे वाले हैं जो सही रूप में सामाजिक नियामक हैं। 41 प्रतिशत तिजान्या ब्रदरहुड से संबंधित हैं, 35

प्रतिशत मुरीद हैं, 7 प्रतिशत कादिरया ब्रदरहुड से संबंधित हैं एवं 5 प्रतिशत लेलिनी से संबंधित हैं।

सेनेगल का राजनैतिक-धार्मिक इतिहास दर्शाता है कि इस्लाम ने ऐसे साहित्यिक पुरुष एवं नेता दिये हैं जो देश के सामाजिक संतुलन को प्राप्त करने एवं बनाये रखने में सक्षम रहे हैं। इन धार्मिक नेताओं ने सेनेगल एवं यहां केवासियों के उद्विकास को गंभीरता से आकार प्रदान किया। फूटा-हीरो के एल हदज ओमार टाल, दिओला कांति के प्रसिद्ध नेता सामोरी तौरी, मावा डायको बा एवं शीलरनो साउलीमेन बाल जिन्होंने कोली तेनगुइला के सोनमई साम्राज्य के विरुद्ध फूटा-टोरो में कांति का नेतृत्व किया, जैसे धार्मिक नेता सेनेगलवासियों की सामूहिक याद में हैं।

>>

उनके नेतृत्व की ताकत, इस्लाम एवं अफ्रीका के प्रजातंत्र की "पुरातन परम्परा के मध्य अभिसरण के कारण थी। इसका आधार है, शक्ति पर संदेह एवं यह धारणा कि इसका विस्तार एवं सर्वशक्तिमान होने को भी सीमित करना चाहिए। किसी भी पूर्ण सत्ता के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति जागरूकता के कारण, परम्परवादी अफ्रीकी समाजों ने अधिकतर अपने नेताओं को "मुखिया के रूप में खेलने" से रोका है एवं एक विश्वसनीय नेतृत्व को सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किये जिससे की पूर्ण शक्ति प्रकट न हो।

वोलोफ समाज में, राजा के अनुष्ठानिक अभिषेक में प्रमुख प्रतिज्ञा लेता है, कि वो परम्पराओं के अनुरूप एवं सबकी खुशहाली के लिए कई कार्य करेगा। वालो में (वोलोफ साम्राज्य), उदाहरण स्वरूप, कुलीन लोगों के प्रवक्ता ने ब्राक (राजा) को, जो अभी-अभी चुना गया है, यह करते हुए चेतवानी दी कि, "यदि आप अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हुये, तो आपको अपना जीवन हमें देना होगा। यदि आपके कार्य मिजाज के विरुद्ध हुए, तब आपको अपने मतदाताओं के गुस्से एवं आवश्यक रूप से अपने लोगों की नफरत को झेलना पड़ेगा।" यह अविश्वास वोलोफ के प्रसिद्ध कथन में दिखाई पड़ता है जो राजा को अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारियों की याद दिलाता है—"बुर डू मबूक" अर्थात् "राजा पिता नहीं है"। समान रूप से, हम यह याद कर सकते हैं कि इस्लाम में, कहा गया है कि, जिस क्षण व्यक्ति ने विश्वास को कबूल किया, वो अन्य व्यक्ति के प्रति अपनी निष्ठा या निर्भरता को खारिज करता है। इस प्रकार इस्लाम में कोई पादरी या मुखिया नहीं होता है और मुखिया एक पथ प्रदर्शक है, आज्ञाकारी लोग उसके आगे अपना सर झुकाते हैं, यह शायद इसलिये कि वो इस्लाम के सिद्धांतों का आदर करता है, जो कि उपर लिखित परंपरागत मूल्यों से मेल खाते हैं। थीरनो साउलीमेन बाल, अठारवीं सदी के सिपहसालार एवं फूटा के मुस्लमान विद्वान, जानते थे, कि किस प्रकार विश्वसनीय नेतृत्व का प्रतिरूपण किया जाय जो अभी भी कई सेनेगल धार्मिक एवं नागरिक आंदोलनों को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा :

"मैं एक मार्गदर्शक का चुनाव करने के लिए इन दिशा निर्देशों की सिफारिश करता हूँ :

- एक बुद्धिमान, पवित्र एवं ईमानदार व्यक्ति, जो इस विश्व के अमीरों को अपने एवं अपने बच्चों के फायदे के लिये एकाधिकार न दे ;
- किसी भी इमाम को अपनी गद्दी से उतार दे जिसकी दौलत बढ़ गयी हो एवं उसकी पूरी दौलत को जब्त कर ले।
- यह सुनिश्चित करे कि इमामदारी आनुवांशिक साम्राज्यवाद में परिवर्तित न हो, जहां पुत्र पिता का स्थान विरासत में लेता हो।
- उससे लड़ो एवं यदि वो बना रहता है तो उसे बाहर निकालो।
- इमाम किसी भी जनजाति में से चुना जा सकता है।
- सदैव बुद्धिमान एवं मेहनती व्यक्ति का चुनाव करो
- कभी भी एक या समान जनजाति तक अपना चुनाव सीमित मत करो
- हमेशा अपना आधार काबलियत को रखो।

> नेतृत्व के महत्व को संरचित करने वाले मूल्य

धार्मिक नेता, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो न्याय, परमार्थ एवं ईमानदारी जैसे मूल्यों से ओतप्रोत हो। उसके निर्णय सदैव व्यक्तिगत लाभ के उपर हो। उसके अन्दर अपने मूल्यों एवं साथियों के प्रति उच्च कोटि की प्रतिबद्धता हो। वो अपनी धारणाओं को, अपनी नैतिकता को एवं वस्तुनिष्ठता को हर जगह एवं हर परिस्थिति एवं हर स्थान पर बनाये रखे। इस प्रकार के नेतृत्व के रूप में हाल हीह के इतिहास के दो नेताओं ने उदाहरण पेश किया है — सेरीजन आबदो अजीज सी दबख, 1957-1997 तक सेनेगल के तिड़जानी ब्रदरहुड के तीसरे खलिफ एवं सेरिगन सेलियू मेबेक, पांचवे मुरीद खलिफ। पहले वाले अपने अनुयायियों को कहने में कभी हिचकिचाते नहीं : "कि यदि कभी तुम मुझे ऐसा कार्य करते हुए देखो जो, उस कार्य से भिन्न हो जो मैं तुम्हें कहता हूँ एवं करने के लिए बुलाये अन्यथा मैं आपको माफ नहीं करूंगा एवं आवश्यकता हुई तो अपने आप को मुझसे दूर कर लेना।"

नैतिक मूल्य एवं साझेदार परिप्रेक्ष्य के निर्माण से परे, नेता की शक्ति आधारित है, उसकी क्षमता है कि वह वही कार्य करे जो वह दूसरों को करने को कहता है। नेता को मानवशस्त्रीय प्रतिरूप के नैतिक मूल्यों वाले भाग, "नित कू बाकस" (एक अच्छा व्यक्ति) जो "नित कू एम जोम" (गर्व की अनुभूति) "नित कू एम करसा" (एक अंतर्मुखी व्यक्ति, जिसने सौम्यता हो जब वो लोगों के बीच हो), "नित कू जुब" (सही कार्य करने वाला व्यक्ति), "नित कू एम डाइन" (व्यक्ति जो विश्वसनीय हो), "नित कू डोबूलू" (एक सौम्य व्यक्ति), "नित कू कादू" (व्यक्ति जो अपने शब्दों पर अडिग रहे) एवं 'नित कू गोर' (एक योग्य व्यक्ति) का आदर करना चाहिए। इन मूल्यों में से, "जोम" की विशेष जगह है क्योंकि यह विभिन्न अर्थ को समाहित करता है : जिम्मेदारी, गर्व एवं आदर की भावना, "वरागुल" (जिम्मेदारी की समझ), अच्छा करने प्रयास, स्वयं का त्याग, साहस, स्वयं की अनुभूति एवं खुद के मूल्यों के प्रति जागरूकता। वोलोफ लोगों के लिए, एक नेता को उन सभी मूल्यों को समाहित करना होता है जो "जोम" में हो मूल्य जो आलस्य, डर, झूठ, संदेहहीनता के असंगत हो।

सेनेगलवासियों की अधूरे वादों के प्रति घृणा इन दो राजनेताओं के दो मामलों से उचित प्रकार से बतायी जा सकती है जो अपने वादों से मुकर गये। पूर्व राष्ट्रपति अबदोउ वादे ने यह कहने के बाद कि वे 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरी बार नहीं खड़े होंगे "वख वखीद" (मैं कहता हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ) किया। वर्तमान राष्ट्रपति मैकी साल जिसने उनकी जगह ली ने भी, समयावधि जिसके लिए चुने गये थे को सात वर्ष से घटा कर पांच वर्ष करने के वादे को तोड़ कर "वाख वखीद" की पुनरावृत्ति की। प्रसिद्ध वोलोफ मुहावरा "गौरे सा वैक्सजा" (कुलीनता अपने शब्दों को इज्जत देने से निश्चित होती है), दर्शाता है कि सेनेगलवासी अपने शब्दों को कितना महत्व देते हैं। यह इन राष्ट्रपतियों की आलोचना के द्वारा दिखाई देता है। ■

सभी पत्राचार मोहम्मद मोस्तफा दिये को
<mouhamed.dieye@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> महिला अधिकारों को अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना

बेंगी सुलु, द ग्रेजुएट सेन्टर, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, यू.एस.ए.¹ द्वारा



महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग के 63 वें सत्र का शुभारम्भ।
श्रेय : यू.एन.वूमेन। फिलकर। कुछ अधिकार सुरक्षित।

कमीशन आन द स्टेटस ऑफ वुमेन का 63 वाँ सेशन (CSW 63), जिसका प्रमुख विषय "सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, जन सेवाओं तक पहुँच एवं लैंगिक समानता एवं महिला और बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु संवहनील आधारभूत संरचना" था, 11 से 22 मार्च 2019 तक न्यूयॉर्क स्थित यू.एन. मुख्यालय में आयोजित किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों एवं पैनलों ने महिलाओं एवं बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रोत्साहन एवं संरक्षण के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्यों और संवहनीय विकास लक्ष्यों के सम्बंध में देखा। आयोग का मुख्य फोकस महिलाओं के लिए संरक्षण एवं लाभों के क्रियान्वयन पर था : महिला प्रस्थिति पर बढ़ती समझ और व्यापक सर्वसम्मति के बावजूद, विश्व के विभिन्न भागों में महिलाओं एवं बालिकाओं को जीवन में सम्पूर्ण भागीदारी एवं उन्नति सुनिश्चित करने के लिए अभी काफी लम्बा सफर तय करना है।



महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग के
63 वें सत्र का प्लेनरी सत्र।
श्रेय: अफ्रीका रिनुअल। फिलकर।
कुछ अधिकार सुरक्षित।

आयोग के अध्यक्ष (एवं आयरलैंड से यू.एन. के स्थायी प्रतिनिधि) गिरालडिन बेरेन नेसन के कंसलटेशन दिवस-संयुक्त राष्ट्र के साथ एक परामर्शदात्री स्थिति में गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक सूचना एवं संघटन कार्यक्रम-पर दी गई टिप्पणी ने महिला अधिकारों की मानवाधिकारों के रूप में मान्यता और जीवन अवसरों में पूर्णतया भागीदारी करने के लिए सक्षम बनाने वाली आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक अवसरों तक महिलाओं की पहुँच में असमानता को रेखांकित किया। जिस दूरी को पाटने के लिए हमें कार्य करना है, वह महिला अधिकारों एवं विकास को मान्यता और स्थानीय स्तर और दैन्य जीवन में लैंगिक असमानता को खत्म करने वाले रक्षात्मक उपायों और कार्यक्रमों को नवोन्मेषी, व्यवस्थागत, संवहनीय, सांस्कृतिक रूप से संवदेनशील, लैंगिक प्रत्युत्तरों के मध्य की दूरी है। हमें महिलाओं के राजनैतिक प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक जीवन में उनकी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सहभागिता के मध्य सम्बंधों को देखना होगा। यह सब उन तरीकों से होगा जो ज्ञान, रीतियों और योजनाओं के निर्माण में महिलाओं के अनुभवों, दृष्टिकोणों, अंतर्दृष्टि और स्थान के योगदान को मानेंगे। हमें यह भी पहचानने की आवश्यकता है कि लैंगिक भेदभाव के विविध रूप जाति, वर्ग, राष्ट्रीय पहचान, धर्म, भूगोल, व्यवसाय और अन्य कई “उत्पीड़न के इंटरलॉकिंग व्यवस्था” के आगे जाते हैं। पी. एच. कोलिन्स के शब्दों में, किसी विशेष सन्दर्भ में लैंगिक असमानता के बनते स्वरूपों में योगदान करना।

सबसे प्रभावी और स्थाई लैंगिक समानता के परिणामों के लिए नीति एवं व्यवहार और अन्तरानुभागीय सोच को समन्वित करने की आवश्यकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ चित्रण महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक विन्यास में महिला सुरक्षा, आर्थिक लाभ और सामाजिक एवं राजनैतिक अवसरों से महिलाओं को अपवर्जन और देखरेख कार्य एवं पुनः प्रवेश प्रक्रिया पारिवारिक जिम्मेदारियों के अवैतनिक कार्य का असमान हिस्सा की तरफ मुँह देख कर किया जा सकता है। ये मुद्दें, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ द्वारा सीएसडब्ल्यू 63² में प्रायोजित पैनलों में उठाया गया, शिक्षा, बाल देखभाल, आपराधिक न्याय, रोजगार एवं नगरीय नीतियों जैसे नीतिगत व्यवस्थाओं में अंतर्सम्बंधों को प्रदर्शित करते हैं। नगरीय नीतियों

में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक सहभागिता को सक्षम बनाने वाली आवासीय एवं यातायात से संबंधित नीतियां सम्मिलित होती हैं और ये नवान्मेषी विचारों, प्रभावी कियान्वयन और अमल की आवश्यकता की ओर इंगित करती हैं।

उदाहरण के लिए, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, एक ऐसा मुद्दा है जिसे सम्बोधित करना अक्सर कठिन है क्योंकि यह निजी क्षेत्र तक सीमित है और इसलिए इसे एक परिवार के अन्तर्गत एक निजी समस्या माना जाता है। महिलाओं का उपलब्ध सेवाओं के बारे में ज्ञान घरेलू हिंसा द्वारा पनपाये जाने वाले अवरोधों की बहुलता, जिसमें रोजगार अवसरों तक सीमित पहुँच, स्वतंत्र एवं सुरक्षित आवास, निशुल्क या वहनशील बाल देखभाल और संरक्षण एवं परामर्श सेवाएँ सम्मिलित हैं लेकिन वहाँ तक ही सीमित नहीं, के साथ आवश्यक रूप से मेल नहीं खाता है।

घरेलू हिंसा महिला अधिकारों के उल्लंघन का एक रूप है जो दर्शाता है कि उचित प्रवर्तन के बिना कानून महिलाओं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा एक अन्य मुद्दा है। *महिलाओं और बालिकाओं की न्याय तक पहुँच : कानून प्रवर्तन एवं शान्ति बनाये रखने में महिलाओं की भूमिका* के पेनल में बेडफोर्ड शायर पुलिस विभाग, यू.के. में सहायक मुख्य कांस्टेबल के पद पर कार्यरत डॉ. जैकी सेबेर ने अपने अनुभवों के आधार पर जैसा कहा, महिला अधिकार सर्वोत्तम रूप से समुदाय सदस्यों द्वारा संरक्षित एवं व्यवहार में लाये जाते हैं। वे महिलाओं की समस्याओं और जिस तरह उन्हें महसूस किया जाता है और उनका बोझ उठाया जाता है को पहचानने में सक्षम होते हैं। पुलिस के पेशे में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन महिला सशक्तिकरण में योगदान देगा और एक सांस्कृतिक सफलता की अनुमति देगा क्योंकि यह इस पेशे के साथ जुड़े पितृसत्तात्मक मानदण्डों के विरुद्ध जाता है; इसमें महिलाओं के अनुभव या “नारीवादी ज्ञान” को लैंगिक हिंसा के खिलाफ युद्ध में केन्द्रीय उपकरण बनाने की क्षमता है। ऐसा मौजूदा प्रवर्तन के मॉडलों में प्राथमिकता पर नहीं है। यह स्कूल या अन्य शिक्षण संस्थाओं तक यात्रा करने वाली युवा महिलाओं की समस्याओं पर बढ़ते शोध क्षेत्र के आलोक में भी महत्वपूर्ण है।

नटराजन और अन्य (2017) द्वारा जैसा प्रलेखित किया गया, महिला कॉलेज छात्राएँ विद्यालय जाते समय अक्सर यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं। ऐसा शोध, जो महिलाओं की धारणाओं और अनुभवों से सीखता है, नगरीय नीति को सूचित करने में और प्रौद्योगिकी एवं सार्वजनिक सेवाओं को नगरीय सार्वजनिक स्थानों और संस्थाओं के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करने हेतु दिशा दिखा कर मदद कर सकता है।

हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ सामाजिक और आर्थिक अवसरों से महिलाओं को लाभ प्राप्त करने से रोकने वाला एक मात्र कारक नहीं है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अवैतनिक देखरेख कार्य एवं घरेलू हिंसा उनके श्रम बाजार में प्रवेश के अवसरों और रोजगार जो उनकी स्वतंत्रता और आर्थिक लाभ को सक्षम बनाए, को सीमित करता है। शोध बताते हैं कि :“दुनिया भर में, पुरुषों की तुलना में महिलाएँ दो से दस गुना अधिक समय अवैतनिक देखभाल कार्य पर व्यतीत करती हैं।” (फेरन्ट और अन्य, 2014)। यह स्पष्ट है कि देखभाल के कार्य को सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्थाओं और जीवन के संपोषण के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है; सवैतनिक मातृत्व अवकाश एवं अभिभावक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा का अभाव सामाजिक कल्याण व्यवस्था की सबसे बड़ी कमियाँ हैं; जो या तो महिलाओं को रोजगार बाजार में प्रवेश नहीं करने देती या बच्चे को जन्म देने के बाद उसे छोड़ने पर मजबूर करती है। यदि ये महिलाएँ बाद में रोजगार लेना चाहती हैं, तो उन्हें अधिकांश/ज्यादातर रोजगार के अनौपचारिक स्वरूपों को जबरन लेना पड़ता है जो कोई संरक्षण नहीं प्रदान करते हैं। जैसा कि *महिला, पुनः प्रवेश एवं सामाजिक संरक्षण* पेनल में चर्चा हुई, यह संरचनात्मक भेदभाव विशेष रूप से बंदी महिलाओं को प्रभावित करता है जिनका श्रम बाजार में पुनः प्रवेश विशेष रूप से सीमित कार्य इतिहास के कारण कठिन हो जाता है। परिवार-उन्मुख नीतियाँ जो परिवार में पुरुष और महिलाओं के मध्य जिम्मेदारी के वितरण और काम-परिवार के संतुलन पर जोर देती हैं, का अभाव सभी महिलाओं को प्रभावित करता है लेकिन वंचित महिलाएँ, जिन्हें पूर्व में कारावास के दौरान अवसरों से वंचित किया गया, को सबसे अधिक हानि होती है। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब कारावास की अवधि के दौरान ऐसे हस्तक्षेपों की कमी होती है जो शिक्षा की निरंतरता और जीवन में भागीदारी पर जोर दें।

महिलाओं के लिए संरक्षण एवं लाभों के क्रियान्वयन के लिए एक समग्र और व्यापक उपागम की आवश्यकता है। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि जो हस्तक्षेप कानून एवं नीति में स्थान पाते हैं, उनको लागू कैसे करें? यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक महिलाओं की पहुँच ऐसे तंत्रों तक हो जो न केवल सुरक्षा को सक्षम बनायेंगे अपितु उन्हें पनपने में भी मदद करेंगे, सरकारों को अधिक सक्रिय होना होगा। नागरिक समाज संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ, इन विषयों पर नीति-निर्माताओं को शिक्षित करने और लिंग समान नीतियों एवं व्यवहारों के लिए पैरवी करने का कार्य करते हैं। ■

1. लेखक आई.एस. की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में युवा प्रतिनिधि है और इसने 2019 में प्रथम बार महिला प्रस्थिति पर आयोग के 63 वें सत्र में भाग लिया है।

2. पेनल आई.एस., द अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्रिमिनोलोजी, द वर्ल्ड सोसायटी ऑफ विक्टिमोलोजी, क्रिमिनोलिज्स्ट विदाउट बाडर्स के संयुक्त प्रायोजन में आयोजित हुए। आप, [रोजमेरी बारबेरेट](#), संयुक्त राष्ट्र में आई.एस.की प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र पर सी.एस.डब्ल्यू 63 के बारे में बालेते हुए सुन सकते हैं अथवा सभी छः पेनलों की [विडियो प्लेलिस्ट](#), सभी छः पेनलों की [फोटोग्राफ्स](#) का देख सकते हैं एवं संयुक्त राष्ट्र में आई.एस. प्रतिनिधियों द्वारा तैयार, कार्यक्रमों में वितरित [रीडिंग लिस्ट](#) देख सकते हैं।

संदर्भ:—

Ferrant, G., L.M. Pesando and K. Nowacka (2014). “Unpaid care work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes.” OECD Development Centre Policy Brief.

Natajaran, M., Schmuhl, M., Sudula, S. & Mandala, M. (2017). “Sexual victimization of college students in public transport environments: a whole journey approach.” *Crime Prevention and Community Safety*, 19(3-4): 168-182. (Special Issue: Women’s victimisation and safety in transit environments: An international perspective).

सभी पत्राचार बेंगी सुलु को bsullu@gradcenter.cuny.edu पर प्रेषित करें।